# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

07 मार्च, 2017 (द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक–9

अधिकृत विवरण

## विषय सूची

मंगलवार, 07 मार्च, 2017

पृष्ठ संख्या


वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा उन व्यक्तियों, जो राज्य में राज्य सरकार के संरक्षक कार्यवाहक के अधीन अवैध खनन कर रहे हैं, के विरूद्ध आरोप लगाना।

श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा आरोप लगाने संबंधी तथा उनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित करने संबंधी मामला उठाना

वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

विधान कार्य–

1. दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नंबर–1) बिल, 2017
2. दि हरियाणा लॉ ऑफिसर्ज (इंगेजमेंट) अमैंडमैन्ट बिल, 2017

श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरूद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 07 मार्च, 2017 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

## वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ

**उपाध्यक्ष महोदया :** माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होगा ।

**श्री जय तीर्थ (राई):** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का मौका दिया । हरियाणा की भाजपा सरकार का यह तीसरा बजट है । बजट से पहले बड़ी–बड़ी घोषणाएं की गई थी जिससे जनता को इस बजट से भारी उम्मीद थी । लेकिन जितना निराशाजनक यह बजट रहा उससे लोगों को बहुत भारी मायूसी हुई । इस बजट में सरकार ''नो टैक्स'' बताकर जनता को ट्रैप में फंसाने की तैयारी करती है । सरकार यह वाहवाही लूटने की कोशिश में है कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया । लेकिन यह सब ढ़कोसला है क्योंकि पिछले बजट में भी यही घोषणाएं हुई थी । अब मैं हाऊस के सामने 5 मार्च 2017 का एक दैनिक भास्कर अखबार रख रहा हूं जिसमें यह लिखा है कि – सरकार से जनता को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन पिछले बजट में सीधा जनता को लाभ पहुंचाने के लिये की गई दस घोषणाओं का भास्कर ने हाल जाना तो पता चला कि अभी तक लोगों को 10 प्रतिशत भी लाभ नहीं मिल पाया है । जितनी पिछले साल घोषणाएं हुई थी उन में से 10 प्रतिशत लाभ भी जनता को नहीं मिला है । इसमें हैल्थ विभाग का हवाला दिया गया है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के जिला अम्बाला में हीमोडायलिसिस की सुविधा नहीं है । वहां सीटीस्कैन के लिये मशीन खरीद कर आ चुकी है लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है । उच्चतर शिक्षा में लिखा है कि अलेवा, मानेसर, उकलाना, गुहला चीका, सहजादपुर, उकलान, कुरूक्षेत्र, कनीना, पृथला, जुंडला, सोनीपत, छिलरो कालांवाली, सोना, रानियां में राजकीय कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी जिनकी फरवरी मास में नींव तो रखी गई थी लेकिन आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई । करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन अभी तक वहां पर न तो बागवानी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और न मैडिकल यूनिवर्सिटी में कोई नियुक्ति हुई है । इसके साथ साथ मरीजों का इलैक्ट्रिक हैल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक कोई स्वास्थ्य कार्ड सुविधा शुरू नहीं हुई । पिछले साल 600 नई बसें और दो अन्तर्राजीय बस अड्डों की घोषणाएं की गई थी जिसमें फरीदाबाद के सैक्टर–12 में बनने वाले अन्तर्राजीय बस अड्डे की अभी तक शुरूआत भी नहीं हुई है।

**शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा)** : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री जयतीर्थ जी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं लेकिन ये सदन में अखबार लेकर आए है । यह ठीक नहीं है ।

**श्री जय तीर्थ** : मंत्री जी, मैं तो केवल बता रहा हूं, आप इसको मानें या न मानें । आप इसका जवाब दे देना ।

**श्री राम बिलास शर्मा** : नहीं, जय तीर्थ जी, पहले दिन आप सदन में काली टोपी पहन कर आए थे । एक तो बात ये है कि आपने वह क्यों उतार दी ?

**श्री जय तीर्थ** : उपाध्यक्ष महोदया, पिछले साल 600 नई बसों की घोषणा हुई थी जिसमें से केवल 300 बसों का ही टैंडर हो पाया है लेकिन अभी तक उनमें से एक भी बस सड़क पर नहीं चली है। इस संबंध में मेरी सबमीशन ये है कि सरकार सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं करती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार की 3500 घोषणाएं और 157 वायदे हैं जिनमें से अब तक एक भी पूरा नहीं हुआ ।

**परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार)** : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने विभाग के संबंध में माननीय सदस्य को जवाब देता हूं ।

**श्री जय तीर्थ** : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी अपना जवाब बाद में दे लेंगे । एक बार मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा ।

**श्री कृष्ण लाल पंवार** : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की बात को मानते हुए मैं अपने विषय से संबंधित भाग का उत्तर बाद में ही दे दूंगा।

**श्री जयतीर्थ** : उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बजट पेश हुआ है इससे जनता को बहुत भारी निराशा हुई है। वर्ष 1966 से लेकर वर्तमान तक यानि हरियाणा बनने की 50 वर्ष की अवधि में जो सरकारी कर्जा था वह 70 हजार करोड़ रूपये था, लेकिन इस सरकार ने मात्र अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में इस सरकारी कर्ज को 141854 करोड़ रूपये पहुंचा दिया है यानि सरकारी कर्ज डबल कर दिया है जबकि काबिल–ए–गौर यह है कि इस अढ़ाई वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में न तो प्रदेश में कोई बढ़ा प्रोजैक्ट आया है, न ही किसी प्रकार के विकास कार्यों को प्रदेश में अंजाम दिया गया है। अतः प्रश्न यह उठता है कि जो प्रदेश पर इतना अधिक सरकारी कर्जा लाद दिया गया है, यह पैसा कहा गया? इस पैसे का प्रयोग कहां

पर हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदया, बड़े अफसोस की बात है कि इस पैसे का कोई हिसाब–किताब ही नहीं है? (विघ्न)

**मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह विर्क):** उपाध्यक्ष महोदया, जैसाकि सदन में कांग्रेस के लोगों द्वारा बात कही जा रही है कि प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, इस परिपेक्ष्य में मैं सदन की जानकारी के लिए कांग्रेस के शासल काल की एक घटना बताना जरूरी समझता हूँ। वर्ष 1991 में, मैं नीलोखेड़ी में ब्लॉक समिति का चेयरमैन हुआ करता था और वर्ष 1992–93 में जब चौधरी भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस कांग्रेस के काल में भजनलाल जी के नाम से लड़कों का कॉलेज बनाने बारे एक पत्थर लगाया गया था । अगर कोई जाकर देखना चाहे तो जब तरावड़ी से करनाल जाते है तो वहां खब्बे हाथ यह पत्थर देखा जा सकता है। वर्ष 1992–93 में लड़कों के कालेज के लिए लगाये गए इस उद्घाटन पत्थर के अतिरिक्त आज तक उस कॉलेज की एक ईंट तक भी नहीं लगी है और आज कांग्रेस के लोग विकास की बात करते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए अलाउ किया है। जब किसी सदस्य को बोलने के लिए अलाउ किया जाता है तो उसे बीच में किसी अन्य सदस्य द्वारा डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक कृषि का संबंध है, कृषि के बारे में वर्ष 2016–17 के बजट में 'वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी प्रावधान का जिक्र किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि हमारी सरकार आने पर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी जोकि अब मेरी बात को सुनकर बैठे–बैठे गर्दन भी हिला रहे हैं, इन्होंने भी उस समय स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने की बात कही थी और इन्होंने अपने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा था कि जब इनकी पार्टी सत्ता में आयेगी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जायेगा लेकिन आज यह इस बात का जिक्र तक नहीं करते हैं और जिक्र तो दूर की बात आज ये सदन में डबल–डबल कपड़े पहने हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बजट पेश किया गया है इससे जनता को बहुत भारी निराशा हुई है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब दाल का रेट 40 से 62 रूपये प्रति किलोग्राम हुआ था तो विज साहब ने भी कपड़े उतारकर अम्बाला में प्रदर्शन किया था । आज वही दाल 162 रूपये प्रति किलोग्राम से भी ऊपर जा

चुकी है लेकिन अब इस बारे में कोई नहीं बोलता । अब भाजपा के लोग जनता के कपड़े उतारने में लगे हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक कर्जे का प्रश्न है तो कैग ने भी इस बात पर सवाल उठाये हैं । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, कैग ने भी यह माना है कि आज के दिन हर एक हरियाणावी पर 47,155 रूपये का कर्ज है । इस सरकार में कैग की रिपोर्ट के अनुसार हर हरियाणवी 47,155 रूपये का कर्जदार है। (शोर एवं व्यवधान) यह कर्ज एक महीने में 50 हजार रूपये हो जाएगा। 50 हजार रूपये और 47 हजार रूपये कर्ज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है । यह रिपोर्ट फरवरी माह की है । (विघ्न) यह वर्ष 2016 की रिपोर्ट है । (विघ्न) कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है । कैग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में वित्तीय संकट गहरा सकता है और प्रदेश पर 1,20,518 करोड़ रूपये का कर्ज है । यह कर्ज दिनांक 31 मार्च, 2016 तक का है । इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार ने इतना कर्जा ले रखा है कि कर्जा लेने की लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है । यह सरकार कर्ज में डूब चुकी है । हरियाणा प्रदेश का हर आदमी आज कर्जदार है । जैसेकि डॉक्टर साहब ने बताया कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति कर्ज 50 हजार रूपये को भी क्रॉस कर गया है । सरकार के कृषि विभाग ने फसल बीमा की एक योजना शुरू की है । उसमें हर किसान को जिसने बैंक से लोन लिया था उसके लिए मैंडेट्री कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि उसको यह बीमा करवाना पड़ेगा चाहे उसने फसल बो रखी हो या न बो रखी हो । सरकार ने आदेश कर दिया कि उसको बीमा करवाना पड़ेगा । 4 मार्च के अमर उजाला अखबार में आया है कि खरीफ के समय प्रदेश के किसानों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई थी । उसमें 6,96,454 किसानों का फसल बीमा योजना के तहत जबदरस्ती बीमा करवाया गया था । जिस किसान ने कर्जा लिया था उसके लिए यह जरूरी था कि वह फसल का बीमा कराये । किसानों की 11,49,274 हैक्टेयर जमीन बीमे में कवर की गई और उसमें सरकार की तरफ से किसानों के 121,90,00,000 रूपये काटे गए । इसमें सैंट्रल गवर्नमैंट ने अपनी तरफ से 45 करोड़ 57 लाख रूपये जमा किये और हरियाणा गवर्नमैंट ने 83 करोड़ 94 लाख रूपये जमा किये । इस तरह से टोटल 251,42,00,000 रूपये का प्रीमियम इकट्ठा किया गया और वह सारा प्रीमियम कम्पनी को दे दिया गया । कम्पनी ने नुक्सान का जो मुआवजा दिया वह सिर्फ 9,86,00,000 रूपये था यानी एक साल में कम्पनी को 241 करोड़ रूपये का

फायदा हुआ । आप सबको मालूम ही है कि वह कम्पनी अडानी, अम्बानी और बजाज इत्यादि हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को अपनी जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए । हुड्डा साहब के समय में भी यही फसल बीमा कम्पनियां थी और अब भी यही कम्पनियां हैं । हरियाणा में कोई नई कम्पनियां नहीं आई हैं । तब भी बजाज थी, तब भी रिलायंस थी, तब भी आई.सी.आई. थी और तब भी ऐसे ही पैसा काटा जाता था । माननीय सदस्य को अपनी बात को करैक्ट कर लेना चाहिए । (विघ्न) अभी यह मुआवजा केवल और केवल उन खेतों का मिला है जिनमें अधिक पानी भर गया था । क्रॉप कटिंग एक्सपीरियैंस का जो पैसा है वह आना अभी बाकी है । विघ्न)

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि किसान की आय कैसे बढ़ेगी ? उसे न तो पानी मिलता है और न ही बिजली मिलती है । हमारे एरिया में 42 दिन के बाद नहर आती है और 42 दिन में टेल पर पानी पहुंचने का कोई मतलब नहीं है । हजारो एकड़ जमीन सूखी पड़ी है लेकिन कहीं भी पानी नहीं पहुंचता है ।

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ः** दहिया साहब, आप अपनी जानकारी ठीक कर लें पहले 24वें दिन पानी आ जाता था। दहिया जी, यह बात सदन में पहले ही बता दी गई थी कि भाखड़ा नहर में 10 लाख एकड़ फीट पानी कम है इसलिए जो पानी चार बार में आता था, वह अब पांच बार में आता है। जहाँ पहले पानी 24वें दिन आ जाता था अब 32वें दिन आता है।

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. कैनाल का मामला वैसे तो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। हमें उम्मीद है कि हरियाणा के हक में फैसला आयेगा। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** दहिया जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ चुका है।

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, मेरे कहने का मतलब यह है कि एस.वाई.एल. कैनाल नहर का निर्माण सरकार को करवाना चाहिए। एक मैसेज सोशल मीडिया में

काफी फैल रहा है कि ***। (विघ्न)

**उपाध्यक्ष महोदयाः** सोशल मीडिया के इस मैसेज को रिकॉर्ड न किया जाए। (विघ्न)

**डॉ. पवन सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, बजट से इस मैसेज का कोई लेना–देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदयाः** दहिया साहब, आप अपनी बात जारी रखें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, गन्ने के बारे में कहा गया है कि सरकार 320 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीद रही है। उपाध्यक्ष महोदया, सही बात तो यह है कि सोनीपत में शुगर मिल गन्ना खरीद ही नहीं रही है, जिसके कारण सारे का सारा गन्ना उत्तर प्रदेश में जा रहा है।

**सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर):** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि हरियाणा में किसानों का एक–एक गन्ना शुगर मिल खरीद रही हैं बल्कि जितनी शुगर मिलों की क्षमता है उससे भी अधिक गन्ना खरीद रही हैं। दहिया जी, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि मिड वैरायटी के गन्न का 78 प्रतिशत बॉण्ड कैंसिल कर दिया और 50 प्रतिशत बॉण्ड अगली वैरायटी के गन्ने का कैंसिल हुआ है।

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः** उपाध्यक्ष महोदया, जो दहिया साहब सदन में कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आज के दिन गन्ने का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आज सैंकड़ों गन्ने की ट्रैक्टर–ट्रालियां भरकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड तक जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिए मैं सबूत भी ला सकता हूँ क्योंकि मेरी स्वयं की गन्ने की ट्रैक्टर–ट्राली बाहर जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यह एक चिंतनीय विषय है। विपक्ष का सदस्य यदि सही बात बताए तो सत्ता पक्ष द्वारा उसका विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है।

.....

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

**श्री मनीष कुमार ग्रोवरः** उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा की सभी शुगर मिलें अपनी क्षमता से 18 प्रतिशत ज्यादा गन्ना खरीद रही हैं। यदि किसी के पास सबूत हो तो सदन में पेश कर दें। (विघ्न)

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, यू. पी. के चुनाव के दौरान मेरी ड्यूटी पक्ष्चिमी यू.पी. में लगी थी। वहां पर मेरी कार के आगे एक गन्ने से भरी ट्रैक्टर–ट्राली आ गई, जो मेरे हल्के के जमालपुर के जमींदार की थी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या कर रहा है? वह जमींदार कहने लगा कि मैं अपना गन्ना बेचने के लिए रूड़की जा रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बात का गवाह हूँ। (विघ्न)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवरः** उपाध्यक्ष महोदया, हो सकता है उसका बॉण्ड न हो । इस कारण से गन्ना बाहर गया होगा। हरियाणा सरकार ने लिखित में दिया हुआ है कि कोई भी गन्ना बाहर नहीं जायेगा।(विघ्न)

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, उसका शुगर मिल से बॉण्ड कैंसिल हो गया था। (विघ्न)

**उपाध्यक्ष महोदयाः** दहिया जी, आप जल्दी कन्क्लूड कीजिए।

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, गन्ने का किसान किस कारण से अपनी फसल बाहर ले जा रहा है इसका रिटन में कोई बॉण्ड नहीं हो सकता। लेकिन हरियाणा का किसान अपने गन्ने की फसल को बाहर लेकर नहीं जा सकता

**उपाध्यक्ष महोदयाः** जय तीर्थ जी, आप कनक्ल्यूड करें।

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, जी माननीय सदस्य बीच में बोलकर मेरा समय खराब कर रहे हैं इसलिए मेरा समय थोड़ा और बढाया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माननीय सदस्यों को मेरे हल्के के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे वहां पर फल, फूल और दूसरी सब्जियां बहुत उगाई जाती हैं इसलिए मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे वह एरिया बिल्कुल दिल्ली से लगता है। मेरे हल्के के किसान जो फल, फूल और सब्जियों में टमाटर, आलू आदि की खेती करते हैं उन फल, फूल और सब्जियां को बेचने के लिए किसान दिल्ली ले जाता है। लेकिन नोटबंदी के कारण किसानों ने सारी पैदावार सड़कों पर फेंक दी क्योंकि उसे कोई खरीदने वाला नहीं था। वहां 50 से 80 रूपये वाली आइटम का रेट 5 से 8 रूपये तक आ गया। उपाध्यक्ष महोदया जी मैं यह बताना चाहता हूं कि नोटबंदी

से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारे सोनीपत में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिसमें से लाखों मजदूरों को नौकरी से हटा दिया गया।

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, मैं लिखकर दे सकता हूं अगर एक भी मजदूर को फैक्टरी से हटाया गया हो। कोई भी मजदूर नोटबंदी की वजह से नहीं हटाया गया और उनको समय पर सैलरी मिल रही है। कोई भी मजदूर फैक्टरी छोड़कर नहीं गया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** उपाध्यक्ष महोदया, ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर तो फैक्टरियों से निकाले गये हैं।(विघ्न)

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं।(विघ्न)

**उपाध्यक्ष महोदयाः** जय तीर्थ जी, अगर आपकी जानकारी में मजदूर फैक्टरी छोड़कर गये हैं तो आप लिखित में उनके नाम दे सकते हैं।

**डा0 रघुबीर सिंह कादियानः** उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदयाः** कादियान जी, आप पहले ही बोल चुके हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

**डा0 रघुबीर सिंह कादियानः** उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दो सप्ताह के अन्दर–अन्दर 4 लाख नौकरियां खत्म हो गयी हैं और ये सभी कर्मचारी अलग–2 क्षेत्रों में अपना श्रम योगदान दे रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदयाः** कादियान जी, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो सदन के पटल पर दे सकते हैं।

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, अगर इनके पास कर्मचारियों/मजदूरों के पलायन संबंधी कोई जानकारी है तो ये लिखित में दे सकते हैं। इस क्षेत्र में हमारा पुरा ध्यान है कोई भी इंण्डस्ट्री प्रदेश से बाहर नहीं जा रही है बल्कि इण्डस्ट्रीज आ रहीं है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आज एक भी कर्मचारी बाहर नहीं जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने का समय दिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदयाः** कुलदीप शर्मा जी, आपकी पार्टी के ही सदस्य बोल रहे हैं इसलिए आप बैठ जाएं।

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः** उपाध्यक्ष महोदया, हमारी शुगर मिल जो पंजाब में है उसकी जो पेमैंट आयी है वह मेरे छोटे भाई के बैंक में खाते में आयी है।(विघ्न)

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, किसान ने मिल का बॉण्ड भरा हुआ है उसके बाद कोई शुगर मिल गन्ना नहीं ले रहा है तो इसकी जानकारी हमारे विभाग को दें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान अपनी फसल की जल्दी कटाई के लिए किसी बाहरी मिल में चला जाए तो वह अलग बात है।(विघ्न)

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत शहर में म्यूनिसिपल कमेटी को निगम का दर्जा दिया गया है। उसमें 26 गांव में से 21 गांव मेरे हल्के से लिये गये हैं और 5 गांव खरखौदा हल्के तथा गन्नौर हल्के से भी लिये गये हैं। जो–2 गांव इसमें शामिल किये गये है उनका क्या क्राईटेरिया रखा गया है, यह सरकार ने आज तक नहीं बताया है। सोनीपत के इधर–उधर के लगभग 5 से 20 किलोमीटर तक के गांव तो लिये गये हैं और 2 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव था वह छोड़ दिया गया जबकि उस गांव से भी करोड़ों रूपये की आमदनी थी।

**उपाध्यक्ष महोदयाः** जय तीर्थ जी, आप कंक्ल्यूड करें।

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, लगभग 700 करोड़ रूपये इन गांवों की पंचायतों का पैसा निगम में गया तथा इन पैसों के साथ ही साथ अरबों रूपये की पंचायत की जमीन भी निगम में मिला दी गयी। उस वक्त भी हमने सदन में बताया था कि जिस गांव से पैसा लिया गया है वह पैसा उसी गांव के विकास में लगाया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदया :** जयतीर्थ जी, आप एक मिनट में कंक्ल्यूड करें।

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह बता रहा हूं कि सारा पैसा सोनीपत कांस्टीच्युएसी में ही लगाया गया, क्योंकि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमैंट की मंत्री हैं, वे सोनीपत से ही हैं, इसलिए उन्होंने सारा का सारा पैसा सोनीपत में

लगाया। उन्होंने सारा पैसा सोनीपत के फुटपाथों पर सड़क के किनारे खजूर के पेड़ लगा कर खत्म कर दिया।

**उपाध्यक्ष महोदया :** जय तीर्थ जी, आपका समय खत्म हो गया, कृपया आप बैठ जाएं।

**श्री जय तीर्थ :** उपाध्यक्ष महोदया, मेरी बात सुन तो लीजिए। वहां पर जितने भी खजूर के पेड़ थे, वे सब 15 दिनों के अंदर–अंदर गिर गए। खजूर के पेड़ों में लाखों–करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। 2800–2800 रुपए का एक–एक खजूर का पेड़ सड़क के किनारे पर लगा दिया गया और सारा पैसा बर्बाद कर दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदया :** श्री जय तीर्थ जी, आपके पास जो भी पेपर्ज़ हैं वे सदन के पटल पर रख दीजिए। (शोर एवं व्यधान) अब आप बैठिए। अब रामचंद कम्बोज जी बोलेंगे।

**श्री जय तीर्थ** : उपाध्यक्ष महोदया, एक कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले की इनक्वायरी भी होनी चाहिए। (शोर एवं व्यधान)

**श्री राम चंद कम्बोज (रानिया) :** उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब तक यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पढ़ा नहीं था उस समय तक इस बजट से बहुत–सी उम्मीदें की जा रही थी कि इस बजट के द्वारा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, उद्योगों के लिए राहत देने का काम किया जाएगा। मगर जैसे ही वित्त मंत्री जी ने इस बजट को सदन में पढ़ा तो एक बहुत–बड़ा झटका–सा लगा। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कृषि से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले मैं कृषि की बात करूंगा। राजस्व इकट्ठा करने में और प्रदेश को चलाने में कृषि का सबसे बड़ा हिस्सा है। मेरा सिरसा जिला कृषि उत्पादन में सबसे बड़ा जिला है, यानि वहां कृषि का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पिछले साल धान की फसल का रेट बहुत कम था। उपाध्यक्ष महोदया, जो किसान गेहूं की बिजाई टाईम पर करता था, वह बिजाई इस बार बहुत देर से हुई, क्योंकि धान का जो भूसा था, जिसे हम लोग पराली कहते हैं, उसे उठाया नहीं गया। सरकार के पास उस पराली का कोई आल्टरनेट नहीं था और उस भूसे को

जलाया गया जिसके लिए किसानों के 2500–2500 रुपये के चालान काटे गए। किसानों पर फसल बीमा योजना भी थोपी गई है। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने इसी सदन में एक बात कही थी कि खेत में आग लगाना धरती मां के कोख को जलाना है। इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन सरकार को इस बजट में इसके लिए कोई आल्टरनेट निकालना चाहिए था। धान का जो भूसा है उसके लिए उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो एथनॉल के प्लांट बिजली बनाने के लिए लगा रही है ये खण्ड स्तर पर उन एरियाज में लगाने चाहिंए थे जहां पर धान की खेती होती है ताकि पराली का यूज किया जा सकता । आज हमारे प्रदेश का किसान दबा–कुचला है । एक कहावत है कि किसान की धान गई ब्याज में और पराली गई लिहाज में जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई है । मेरा अनुरोध है कि पराली से चलने वाले जो एथनॉल प्लांट बिजली बनाने के लिए लगाने हैं वे खण्ड स्तर पर धान पैदा करने वाले एरियाज में लगाये जायें और उनके लिए बजट में पैसे का भी प्रावधान किया जाये ।

15%00 cts

**कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जो जानकारी सदन में दे रहे हैं, यदि वे करैक्ट जानकारी देते तो अच्छा होता । मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कापरेटिव बैंक्स से किसानों ने जो कर्जा ले रखा है उस पर ब्याज नहीं लिया जा रहा है । हमारी सरकार बनने के बाद से ही कापरेटिव बैंक्स किसानों से ब्याज नहीं ले रहे । (विघ्न)

**श्री राम चन्द कम्बोज :** उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश में छोटे किसान हैं और आज वे दूसरे बैंकों तथा आढ़तियों के कारण ऋण के नीचे दबे हुए हैं । मंत्री जी पूरे प्रदेश में सर्वे करवा लें कि हमारे किसान ऋण में दबे हुए हैं या नहीं । आज की जो जोत है वह 8–10 एकड़ से ज्यादा किसी किसान के पास नहीं है । इस बारे में मंत्री जी को मेरे से ज्यादा इलम है ।

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ :** उपाध्यक्ष महोदया, यह जानकारी मुझे हैं लेकिन जहां तक अवशेष का इशू है उनको खत्म करने के लिए जो भी मशीनें खरीदी जा रही हैं उन पर सरकार ने किसानों को तुरंत सबसिडी दी है । इसके अतिरिक्त हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि जितने भी हैपीसीडर हैं उनको किराये पर लेकर इस

समस्या का समाधान किया जाये । इस समस्या के समाधान के लिए कम से कम पैसे में किसान को हैपीसीडर का बैनीफिट दिया जाये। सरकार ने इसके समाधान के लिए और भी बहुत से कदम भी उठाये हैं ।

**श्री राम चन्द कम्बोज :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ये जो एथनॉल के प्लांट लगाने हैं इनके लिए बजट में पैसे का प्रावधान करना चाहिए था, क्योंकि पिछले वर्ष भी पराली जलाने का इशू मुख्य मुद्दा था । 2016–17 के बजट में कृषि के लिए 1516 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष यह कम कर दिया गया । उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से हमारी हिसार की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका लोकल किसानों को कोई फायदा नहीं है। मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए खण्ड और जिला स्तर पर क्लासिज शुरू की जायें ताकि किसानों को फसलों की उपज की जानकारी मिल सके । जहां तक ऑरगनिक खेती का सवाल है इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । पेस्टीसाईड्स की वजह से बहुत सी बीमारियों हो रही हैं । कृषि मंत्री जी ने स्वयं माना है कि 20 प्रतिशत क्षमता भूमि की आरगनिक खेति के लिए रह गई है । यदि भूमि की क्षमता को बढ़ावा देने की तरफ ध्यान दिया जाता तो ऑरगनिक खेती की तरफ किसानों को आकषित किया जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की प्रोपर व्यवस्था करना बहुत जरूरी है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में घग्गर नदी से सिंचाई की जाती है लेकिन आज घग्गर नदी के पानी में फैक्ट्रीज द्वारा विषैला पानी डाला जा रहा है जिसके कारण कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी होती हैं । भटिण्डा से डबवाली जो ट्रेन आती है उसको कैंसर ट्रेन के नाम से ही जाना जाता है । हमारे एरिया में घग्गर में जो दूषित पानी फैक्ट्रीज द्वारा डाला जाता है उसी के कारण बीमारियां फैल रही हैं । इसलिए सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दे । उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से हमारे क्षेत्र को अंडर ग्राउंड पानी का स्तर गिरने के कारण डार्क जोन में डाल दिया है और जिन किसानों ने 2013 में ट्यूबवैल के कनैक्शन एप्लाई किए थे तथा सिक्योरिटी के पैसे भी दिए हुए हैं उनको भी बिजली के कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। (विघ्न)

**परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 31 दिसम्बर, 2013 तक जिन लोगों ने ट्यूबवैल के बिजली के कनैक्शन के लिए एप्लाई किया हुआ है उनके डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिए गए

हैं। जल्द ही उनको कनैक्शन दे दिए जायेंगे । जहां तक माननीय सदस्य ने डार्क जोन की बात की है इस बारे में बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 21 ब्लॉक डार्क जोन में रखे गये हैं और उनमें 5 हजार के करीब ट्यूबवैल कनैक्शन होने थे जो रोक दिए गए हैं । अब उन ब्लॉक्स में माईक्रो इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से कनैक्शन दिए जायेंगे ।

**श्री राम चन्द कम्बोज :** उपाध्यक्ष महोदया, उसके बाद जो बी.जे.पी. सरकार ने आऊट ऑफ टर्म के नाम से किसानों से पैसा ऐंठा वह भी गलत बात है। इतना ही नहीं किसानों की वर्ष 2013 से 2015 तक की जो सिक्योरिटी भरी हुई थी वह भी ऐसी अलग से पड़ी रही। सरकार द्वारा सैल्फ कनैक्शन और आऊट ऑफ टर्म के नाम से वर्ष 2015–16 में जो पैसे किसानों से लूटे गये इस मामले में भी विधान सभा के सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी बनाकर जांच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री महीपाल ढ़ांडा :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य गलतब्यानी कर रहे हैं। जिस विषय का ये जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरूआत श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में हुई थी । उनकी सरकार ने ही किसानों को लूटने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदया :** ढ़ांडा जी, आप कृपया करके बैठ जायें। कम्बोज जी, आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री राम चन्द कम्बोज :** उपाध्यक्ष महोदया, वर्तमान बजट में पशुपालन के लिए 746 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इसी सदन में आज से दो साल पहले गो–संवर्धन और गो–संरक्षण बिल पास हुआ था। उस समय किसानों में इस बात की खुशी थी कि इससे उन्हें आवारा पशुओं के प्रकोप से राहत मिलेगी। मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे हल्के में कुरंगावाली में एक लड़के की आवारा पशु से टकरा जाने के कारण सड़क हादसे में डैथ हुई। यह 04 मार्च, 2017 की खबर है जो कि स्थानीय अखबारों में छपी है। यहीं बात खत्म नहीं हो जाती आवारा पशु से टकरा कर सड़क हादसा हो जाने से अब मेरे हल्के में डेढ़ साल में लगभग 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें अनिल कुण्डू, इंसपैक्टर की मोरीवाला के पास डैथ हुई। हिसार रोड पर सिरसा निवासी प्रवीण की डैथ हुई। पटियाला के निवासी सतनाम सिंह की खैरपुर चौकी के पास डैथ हुई। इस

प्रकार से ये 12 मौतें आवारा पशुओं के कारण हुई। गौ–संवर्धन और गो–संरक्षण बिल पास हुआ तो मैंने एक अनस्टार्ड क्वैश्चन के माध्यम से सरकार से यह पूछा था कि गौ–शालाओं के लिए पिछले तीन साल के दौरान सरकार द्वारा कितनी राशि वितरित की गई। प्रदेश में जो गौशालायें चल रही हैं वे किसानों की मेहनत से और उनके द्वारा इक्ट्ठे किये गये चंदे के सहयोग से चलती हैं। सरकार का इसमें न तो कोई योगदान है और न ही सरकार द्वारा इसके लिए कोई अनुदान राशि दी जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे जो कृषि मंत्री जी से मेरे सवाल का लिखित जवाब आया है उसके मुताबिक पिछले तीन साल के दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्त गौशालाओं के लिए मात्र 6.50 करोड़ रूपये की राशि वितरित की है। मेरे अनुमान के मुताबिक पूरे हरियाणा प्रदेश में इस समय 500 रजिस्टर्ड गौशालायें हैं। इस प्रकार से अगर इन गौशालायें के लिए एवरेज धनराशि निकाली जाये तो वह महज 40 हज़ार रुपये प्रति गौशाला आयेगी। सरकार द्वारा नंदीशालाओं के निर्माण की बात पिछले बजट सैशन के दौरान की गई थी। सरकार को प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नंदीशालाओं का निर्माण करना चाहिए था जिससे प्रदेश को आवारा पशुओं के प्रकोप से निजात मिल सकती। अगर ऐसा होता तो रोड एक्सीडैंट्स में भी कमी आती और किसानों की फसलों का नुक्सान भी नहीं होता। हरियाणा सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में एक परिपत्र भी जारी किया गया है कि अगर कोई पंचायत नंदीशाला के लिए अपनी जमीन देना चाहे तो उसके केस को कंसीडर किया जा सकता है। इस प्रकार से जो नंदीशाला बनेगी वह सरपंच की अध्यक्षता वाली कमेटी के अधीन होगी। सरकार द्वारा ऐसा करके एक अनावश्यक विषय को पंचायतों पर थोपने का काम किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरी यह मांग है कि अगर सरकार इसके लिए बजट का भी प्रावधान करती तो इससे एक सकारात्मक संकेत जाता और प्रदेश के आवारा पशुओं पर भी अंकुश लगाया जा सकता था। पिछले समय मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुतावड़–रानिया पुल की घोषणा की गई लेकिन इस मामले में अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। इससे लोगों में यह संदेश गया है कि माननीय मुख्यमंत्री मात्र नींव पत्थर रखने का ही काम करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुतावड़–रानिया पुल की घोषणा तो कर दी गई थी लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्य चालू नहीं हुआ है । उपाध्यक्ष महोदया, जब अगले साल का बजट आता है तो पिछले साल के बजट के ऊपर पब्लिक में दिखाई देना चाहिए कि हां कुछ

काम हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो घोषणाएं हुई थी वे केवल मात्र घोषणाएं ही रह गई । पिछले 10 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो केवल घोषणाएं होती रही हैं । मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सरकार घोषणाओं पर काम शुरू करेगी या वे केवल मात्र घोषणा बन कर रह जायेंगी । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि रानियां को सब–डिवीजन का दर्जा दिया जाये क्योंकि वह सभी नॉर्म्स पूरे करता है तथा वह हर प्रकार से सही है। इसी प्रकार से मेरे रानियां में सी.एच. सी. की बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए । सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है । घग्गर नदी का पानी पीने लायक नहीं है और ट्यूबवैल के पानी में शोरे की मात्रा बहुत ज्यादा है जिससे बीमारियां बहुत फैलती है। इसलिए रानियां में कैनाल बेस्ड पानी उपलब्ध करवाया जाये ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके । इसी प्रकार से गांवों में जो वॉटर टैंक बनने हैं उसके तहत बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी की बहुत किल्लत रहती है जिनमें खाई, शेरगढ़, सादेवाला, जोधपुरिया तथा बुखाराखेड़ा आदि गांव हैं । इसलिए इन गांवों में वॉटर टैंक बनवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वे बनवाए जायें । उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं सौर ऊर्जा पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । इस बारे में कल मेरा एक प्रश्न भी लगा हुआ था आपको भी पता है कि आज हर वर्ग के लिए बिजली की बहुत बड़ी समस्या है । मैं कहना चाहूंगा कि सौर ऊर्जा के प्लांट बड़े पैमाने पर लगाये जायें । इस बारे में कल मंत्री जी ने भी बताया था कि बिजली खरीद का जो लास्ट एग्रीमैंट हुआ था उसके मुताबिक प्रति यूनिट बिजली की कीमत 4.88 रुपये पड़ती है और वही बिजली उपभोक्ता को लगभग 9 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बिजली की समस्या के समाधान के लिए ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा प्लांट लगाये जायें जिससे न केवल हरियाणा के लिए बल्कि बाहर के प्रदेशों में भी हम मदद दे सकें । इसी प्रकार से मैं किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती की बात करना चाहूंगा । सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक खेती के रेट फिक्स करके इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी ओर अग्रसर हो सकें । उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा खेती होती है और उसको सरकार ने महेन्द्रगढ़, नारनौल की तरह डार्क जोन घोषित कर दिया । इस तरह से हमें चारों तरफ से बांध दिया गया है । इस प्रकार से सबका साथ सबका विकास किस

प्रकार से हो सकेगा ? यह बात सही है कि भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है मगर उसके लिए सरकार की तरफ से नहरी पानी की व्यवस्था की जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

**श्री महीपाल ढांडा :** उपाध्यक्ष महोदया, अभी हमारे साथी रामचंद कम्बोज जी कह रहे थे कि सरकार केवल घोषणाएं ही करती है या कोई विकास का काम भी करेगी । मैं हमारे माननीय मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक पत्थर हमारे गांव में स्टेडियम के नाम का श्री ओमप्रकाश चौटाला जी के नाम से लगा हुआ है मैं पंवार साहब को याद दिलाना चाहुंगा कि वह आपने ही लगवाया था इसलिए उस काम को भी पूरा करवा दें । (विघ्न)

**श्री टेक चन्द शर्मा (पृथला) :** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं । आज मैं कुछ बोलने से पहले एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो भी हम यहां सदन में बोलते हैं उसकी एक कॉपी सभी सदस्यों के पास जानी चाहिए जिससे कि यह पता लग सके कि हमने सदन के अन्दर जाकर के यह बात कही है और जिससे कि वह अपने विधान सभा क्षेत्र में जाकर यह बता सके कि मैंने अपने हल्के की बात सदन में उठाई है । इसके साथ–साथ जो भी बात हम यहां सदन में कहते हैं उसका सरकार पर कुछ असर होना चाहिए और उस पर एक्शन भी होना चाहिए । वह तो ठीक है कि प्रत्येक सदस्य को उसकी कॉपी तो जाती है लेकिन उस पर एक्शन भी होना चाहिए । एक्शन की भी एक परिपाटी डालनी चाहिए । इसमें कोई बुराई नहीं है । उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में पहली बार 102 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश हुआ है । यह शायद अपने आप में एक इतिहास है । यह बजट पिछली बार से 13.18 प्रतिशत बढ़ाकर दिया गया है । इस बजट के अन्दर मैं सबसे पहली बार यह देख रहा हूं कि टोटल बजट का 58 प्रतिशत पैसा चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र मे, बिजली के क्षेत्र में, दलित व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और शहरी विकास के क्षेत्र पर खर्च किया गया है । इसके लिये मैं सरकार को मुबारक बाद भी देता हूं । विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बजट में 15546 करोड़ रूपये और कृषि के क्षेत्र में 12784 करोड़ रूपये तथा बिजली के क्षेत्र में 12665 करोड़ रूपये के इजाफे का प्रावधान किया गया है । यह तीन चीजें हमारे हरियाणा के लिये बहुत आवश्यक हैं । इसमें कृषि को जिस तरीके से बढ़ावा देने

की बात कही है और ग्रामीण विकास में जिस तरीके से देखा गया है कि उसमें सरकार ने पांच–छः योजनाएं चलाई हैं उसके लिये मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं । उसके लिये पुनः मैं यह कहता हूं कि सरकार ने एक नई पहल और नई योजना के तहत तीन हजार से दस हजार की आबादी वाले जो गांव हैं उनमें तीन साल में पांच हजार करोड़ रूपये खर्च करने की बात कही गई है । इस साल में 1500 गांव में जो पांच हजार करोड़ रूपये खर्च करने की बात हो रही है उसमें से इस साल में 1200 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है । मैं समझता हूं कि यह प्रत्येक गांव के अन्दर तीन करोड़ से चार करोड़ रूपये खर्च किया जाएगा । जैसे कि हमारी सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है 'सबका साथ, सबका विकास' उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 90 हल्कों में गये और वहां के प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिये पैसे देकर आए थे । हर क्षेत्र के अन्दर अर्थात 90 के 90 विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर इस योजना के तहत एक विधान सभा क्षेत्र में तीन हजार से पांच हजार की आबादी वाले लगभग चार गांव आ जाते हैं । उन चार गांव में हमारी स्कीम के तहत तीन से चार करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान है जोकि बजट की कॉपी के पेज नं0 50 पर 29 नम्बर आईटम में दर्शाया गया है । इसको सरकार द्वारा तुरंत लागू करते हुए इसके एस्टीमेट्स बनाकर इसको आगे बढ़ाया जाए क्योंकि कई बार जो स्कीमें यहां सदन से लागू हो जाती हैं वे साल भर में भी पूरी नहीं हो पाती हैं । इसी स्कीम के तहत स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के लिये पांच साल में 1461 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है जिसमें एक साल के अन्दर लगभग 300 करोड़ रूपये आते हैं । इस तरीके से जो ये ग्रामीण विकास का सिस्टम है अगर यह पूरी तरह से इम्प्लीमैंट हो जाता है तो उससे गांव का उद्धार भी होगा और लोगों में हमारी एक अलग तरह की पहचान भी बनेगी । दूसरी तरफ हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि –' देशों में देश हरियाणा, जहां दूध–दही का खाना' इस संबंध में कृषि मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर डेरी फार्मिंग के लिये और देसी गायों के लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी का अनुमोदन किया है । दूध का उत्पादन नं0–1 पर लाने के लिये भैंसों की डेरी भी खोली जाती है क्योंकि देसी गायों से शायद हमारा काम नहीं चल सकता । अगर सरकार द्वारा भैंसों को भी सब्सिडाईज किया जाए तो हमारा एक अच्छा माहौल बनेगा और गांवों में विकास के नये आयाम खुलेंगे । सिंचाई के क्षेत्र में मैंने बजट की कॉपी में देखा है, जो 44 नं0 प्वायंट पर दर्शाया गया कि 'हर खेत को पानी'।

उसमें हमारे दो–तीन प्वायंट्स हैं । मंत्री जी ने इरीगेशन विभाग के लिये 143 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । हर खेत को पानी के लिये मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं । हमारे वहां एक छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रूपए की लागत से 20 साल पहले छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी बनाई गई थी लेकिन रिकॉर्ड की बात है कि इस डिस्ट्रीब्यूटरी में आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया है। जब तिगांव में रैली का आयोजन हुआ तो उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस डिस्ट्रीब्यूटरी में एक महीने की अवधि में पानी डाल दिया जायेगा। इस डिस्ट्रीब्यूटरी में लिफ्टिंग वाटर सिस्टम प्रयोग होता है। अतः मेरा निवेदन है कि चूंकि इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हो चुकी है और बजट में भी हर खेत को पानी पहुंचाने के वीजन को बहुत ही गम्भीरता के साथ प्रस्तुत किया गया है, अतः इस परिपेक्ष्य में, इस डिस्ट्रीब्यूटरी को चालू करवाया जाना चाहिए। बजट में 15 डिस्ट्रीब्यूटरी के नवीनीकरण के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है गया है। इन 15 डिस्ट्रीब्यूटरी में मेरे पृथला विधानसभा क्षेत्र की भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी शामिल है जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। वर्तमान समय में रोजगार के लिए बच्चों में स्किल्ड डिवेलपमैंट होना बहुत जरूरी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के दुधोला गांव में स्किल डिवेलपमैंट यूनिवर्सिटी बन रही है। मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि यदि बजट में स्किल डिवेलपमैंट यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रावधान किया गया है तो क्या इस साल से यूनिवर्सिटी में क्लासिज लगाने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है? यदि है तो इसे तुरन्त लागू किया जाये। शिक्षा के क्षेत्र में रिटायर्ड टीचर्ज को लगाने के लिए एक सुगम शिक्षा नामक स्कीम बनाई गई है। सरकार के नियमों के हिसाब से टीचर्ज 58/60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि रिटायर्ड टीचर्ज को आगे भी लगाये रखने का कोई ऐज संबंधी प्रावधान करते हुए ज्यादातर स्कूलों में टीचर्ज की कमी को पूरा किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने 22 कालेजों का फाउंडेशन स्टोन रखा है जिनमें से एक कॉलेज मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है तथा जिनके लिए शायद बजट में प्रावधान भी कर रखा है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और एक अनुरोध भी करना चाहूंगा कि इन कालेजों को इसी सत्र यानि अप्रैल, 2017 से चालू करने का प्रावधान किया जाये। खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में सरकार द्वारा काफी पैसा दिया जा रहा है। अतः इस दिशा में जो नए स्टेडियम्ज इस समय बने हुए हैं

या बन रहे हैं, क्या इनमें कोच रखने का कोई प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है? अगर किया गया है तो इनके इंफ्रॉस्ट्रक्चर के काम को सरकार के माध्यम से जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए। पिछली सरकार के समय पृथला गांव में एक स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी लेकिन अफसोस है कि न तो स्टेडियम को कार्यरूप दिया गया है न ही इसमें कोई फैसिलिटी है इसलिए आपसे निवेदन है कि इंफ्रॉस्ट्रक्चर व डिवेलपमैंट पर ध्यान देते हुए तथा कोच का प्रबन्ध करते हुए इस स्टेडियम को चालू किया जाये। अभी मंत्री महोदय थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 31.12.2013 तक जिन किसानों ने ट्यूबवैल कनेक्शन एप्लाई किए हुए थे, उनके डिमांड लैटर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही उनको ट्यूबवैल कनैक्शन दे दिए जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, जब प्रदेश में बिजली की कमी ही नहीं है तो वर्ष 2013 के बाद, जिन किसानों ने ट्यूबवैल कनैक्शंज के लिए एप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी पैंडेंसी में है, उनको भी ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जायें ताकि किसानों को सहूलियत मिल सके। मैं समझता हूँ कि हम जनप्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा जितना फायदा किसानों का किया जा सकता है, वह करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, गांवों में पानी निकासी का एक सिस्टम बना होता है। इस सिस्टम के तहत गांव का पानी नालियों के माध्यम से जोहड़ में जमा हो जाता है। जिन गांवों में जोहड़ का पानी ओवरफलो हो जाता है, उन गांवों में पानी की निकासी के लिए ट्यूबवैल्ज लगाये गए है जिनसे कमर्शियल रेट्स पर चार्ज किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, यह ट्यूबवैल्ज जन कल्याण व आमजन को राहत पहुचाने के काम में शामिल होते है। अतः मेरा निवेदन है कि इन ट्यूबवैल्ज से कमर्शियल चार्ज की बजाए सबसीडाईज्ड रेट चार्ज किया जाये। इस तरह का प्रावधान बजट में जरूर करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण में पंचायती जमीन में इंडस्ट्रीज लगाने की बात आई थी और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पंचायती जमीनों को लीज पर लेकर उनमें इंडस्ट्रीज लगाई जायेगी, बहुत अच्छी बात है। जब पंचायती जमीनों में इंडस्ट्रीज लगाई जायेंगी तो निःसंदेह हमारे बच्चों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसका परिणाम यह होगा कि हमारे युवा रोजगार के लिए शहरों की तरफ नहीं भागेंगे और उन्हें उन्हीं के गांव में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और इसकी वजह से सरकार की 'सबका साथ–सबका विकास' की अवधारण को बल मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने मोहना में बैराज बनाने की बात पिछले दो तीन सैशन से की है। मेरे साथी चाहे होडल के विधायक उदय भान

जी हैं, पलवल के विधायक करण सिंह दलाल जी हैं, चाहे हथीन के विधायक केहर सिंह जी हैं, चाहे बल्लभगढ़ के विधायक मूल चन्द शर्मा जी हैं यह सभी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र की लाइफलाइन है । यह हमारी लाइफलाइन इसलिए है कि अगर वहां पर बैराज बन जाता है तो वहां वाटर लेवल कम से कम 20–25 फुट ऊपर आ सकता है वरना हमारे रैनीवैल में भी खतरे की घंटी बज सकती है । इसके न बनने से किसानों को भी बहुत नुक्सान हो रहा है । यमुना नदी पर बैराज बनाने के लिए हम सभी विधायक सरकार से अपील करते हैं । सभी दलों के साथी विधायक जो हमारे फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र से आते हैं उनके निर्वाचन क्षेत्रों की ये लाइफलाइन है । आप इसका किसी से भी सर्वे करवाकर करवा लीजिये और सर्वे करवा इस पर तुरंत कार्यवाही कीजिए । मैं अब इस विषय में ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धनयवाद । जय हिन्द ।

## वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

## शहरी स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा

**शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा वैयक्तिक स्पष्टीकरण है । अभी कुछ देर पहले हमारे राई विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री जय तीर्थ ने सोनीपत नगर निगम के बारे में बाकायदा मुझे एड्रैस करते हुए कुछ शब्द कहे थे। मैं उस वक्त हाउस में उपस्थित नहीं थी । (विघ्न) मैं अब उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं । मैं उनके सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहती हूं । मुझे सिर्फ दो मिनट बोलने का समय दिया जाए । मैं सारी स्थिति को स्पष्ट कर दूंगी । इन्होंने कहा है कि सोनीपत नगर निगम में 26 गांव शामिल किये गए हैं । उन पंचायतों के अपने खाते में 700 करोड़ रूपये थे जो फिलहाल सोनीपत नगर निगम में शामिल किये गए हैं । माननीय सदस्य श्री जय तीर्थ ने कहा है कि पंचायतों के उस पैसे का सोनीपत विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रयोग किया गया है । उपाध्यक्ष महोदया, यह हाउस को मिसलीड करने की बात है। ये हाउस के साथ–साथ सोनीपत नगर निगम में जो गांव आये हैं उनकी भोली–भाली जनता को भी बहका रहे हैं । मैं इस बात को रिकॉर्ड में ला रही हूं कि इन 26 गांवों की पंचायतों के खाते में 157 करोड़ रूपये हैं । मैं कहना चाहती हूं कि अगर मैं गलत तथ्य पेश कर रही हों तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं

और अगर माननीय सदस्य श्री जय तीर्थ गलत तथ्य पेश कर रहे हों तो वे इस्तीफा दे दें । (विघ्न) मैं इधर–उधर की बात नहीं करूंगी । (विघ्न) डिप्टी स्पीकर महोदया, आप मुझे बोलने के लिए सिर्फ दो मिनट का समय दीजिए । इन्होंने पूछा कि किस नियम के तहत ये गांव सोनीपत नगर निगम में शामिल किये गए हैं ? मैं कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने 7 नगर निगम बनाये थे । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या नगर निगम के तहत गांव को लाना गलत होता है ? मैं पूछना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने इन गांवों को किस आधार पर नगर निगम के तहत लिया था ? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या पिछली सरकार ने ऐसा करके उन गांवों की जनता के साथ धोखा किया था ? ये कहते हैं कि शहर के सौंदर्यकरण के लिए खजूर के पेड़ क्यों लगाये गये ? मैडम, सोनीपत शहर में माननीय सदस्य श्री जय तीर्थ भी रहते है । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमें सौंदर्यकरण पसन्द नहीं है ? ठीक है, मैं किसान की बेटी नहीं हूं लेकिन अपने घर में तो पेड़–पौधे हम भी उगाते हैं । जब भी कोई बड़ा पेड़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लगाया जाता है तो पहले उसके पत्ते झड़ते हैं और उसके बाद नये हरे पत्ते आते हैं । ठेकेदार से पेड़ लगाने संबंधी यह शर्त भी रखी है कि अगर कोई पेड़ सूख जाएगा तो उसे उसी कांट्रैक्ट के तहत बदला जाएगा तथा कोई पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक पेड़ हरा नहीं होगा । स्पीकर साहब, इसके अतिरिक्त इन्होंने गांव के विकास की बात कही है । मैं इस मुद्दे को सदन में उठाने के लिए इनका धन्यवाद करती हूं । इन्होंने प्रदेश और विशेषकर सोनीपत की जनता को गुमराह कर रखा है । माननीय सदस्य श्री जय तीर्थ वहां की जनता से रोज धरने करवाते हैं । मैं उनका धन्यवाद भी करती हूं कि उन्होंने सदन में यह प्रश्न उठाया है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमने निगम में आने वाले गांवों में कितने काम करवाये हैं ? उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर 12.20 करोड़ रूपये के काम हो चुके हैं, 8.37 करोड़ रूपये के काम चल रहे हैं, 13 करोड़ रूपये के टैण्डर कर दिये गए हैं और वहां के लिए 32 करोड़ रूपये के एस्टीमेट्स तैयार हैं । इसके अलावा हमारी सरकार के द्वारा उन सभी गांवों में अमृत योजना के तहत पीने के पानी का स्थाई प्रबंध भी करवाया जाएगा ।

## हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनंदन

**शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा):** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस महान सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री रोशन लाल आर्य जी

सदन की कार्यवाही को देखने के लिए वी.आई.पीज. गैलरी में बैठे हुए हैं। मैं इनका पूरे सदन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

## वर्ष 2017–18 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारंभ)

**श्री सुभाष सुधा (थानेसर):** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर बजट सत्र वर्ष 2017–18 पर सदन में बोलने का मौका दिया। यह बजट ''सबका साथ–सबका विकास'' की तर्ज पर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास की लहर लेकर आया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में बताना चाहूँगा कि हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है और हमारा हरियाणा प्रदेश छोटा है, लेकिन हमारी सरकार ने प्रथम बार ऐसा बजट पेश किया है जो एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। वर्ष 2017–18 का कुल बजट 102329.35 करोड़ रूपये है। यह एक सराहनीय कदम है। यह पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में 13.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान बिजली की निजी कंपनियों का सरकार पर 35 हजार करोड़ रूपये का कर्जा था। हमारी सरकार ने उनका 29950 करोड़ रूपये का कर्जे का भुगतान किया जिससे निजी कंपनियों का 2800 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष ब्याज कम हुआ व 800 करोड़ रूपये की बचत सरकार को हुई। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने कुल बजट में से ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 4963.09 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 56.69 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है। इसके साथ शहरी क्षेत्र विकास की तरह ग्रामीण विकास के लिए हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं देने के लिए तीन हजार से दस हजार तक की आबादी वाले 15 सौ गांवों के लिए पांच हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। एक नई योजना स्वर्गीय चौधरी छोटूरामजी के नाम से ''दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना'' शुरू की गई है जिसके लिए 1200 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई है। यह योजना नाबार्ड के सहयोग से आगे बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से शहरी विकास के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। पिछले तीन सालों में कुल 4925.84 करोड़ रूपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए थे। इस वर्ष 2017–18 में शहरी

विकास के लिए 4973.58 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 45.93 प्रतिशत अधिक है। उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ–साथ हरियाणा के महान नेता पूर्व उप–मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सेन के नाम से नई योजना ''मंगल नगर विकास योजना'' आरम्भ की जा रही है जिसके लिए एक हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी सदन को जरूर बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए ''पंडित दीन दयाल सेवा बस्ती उत्थान योजना'' आरम्भ की गई थी जो पहले शहर में रिजर्व वार्ड में ही लागू होती थी। अर्थात् इस योजना का लाभ केवल मात्र रिजर्व वार्ड को ही प्राप्त होता था, परंतु आज किसी भी जनरल वार्ड में अगर 100 से अधिक रिजर्व वर्ग के मकान बने हुए हैं, वह वार्ड भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व कम आय श्रेणी के गरीब परिवारों के लिए नए मकान बनाने व खरीदने के लिए दिनांक 25.05.2015 को एक नई योजना सभी के आवास के लिए ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' का शुभारम्भ किया है। इस योजना के प्रथम चरण में हरियाणा सरकार की भागीदारी के कारण हरियाण के 21 शहरों कुरूक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, रोहतक, गुरूग्राम, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, पंचकुला, कैथल, जीन्द, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, नूंह, फतेहाबाद, भिवानी  आदि को शामिल किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री व माननीय शहरी व स्थानीय निकाय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, स्वच्छता अभियान के बारे में मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना ''स्वच्छ भारत'' अभियान को साकार करने के लिए दिनांक 01.11.2014 को ''स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान'' की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय ने घर–घर शौचालय बनाने के लिए 114.02 करोड़ रूपये की राशि खर्च की है। इस प्रकार हरियाणा में सिरसा व कुरूक्षेत्र जिलों के नौ कस्बों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया व अन्य जिलों को इस वर्ष के अंत तक खुले में शौच मुक्त करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में यह गंभीर समस्या बनी हुई है। गांव के गड्ढों में अर्थात् खाली जगहों पर कचरा फेंका जाता है, जिससे वहां पर गंदगी और बीमारियां फैलने का डर लगा रहता है। हमारी सरकार ने इसमें

एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए घर–घर से कूड़ा उठवाने व कचरे के प्रबंधन के लिए 80 स्थानीय निकायों को 15 कलस्टरों में विभाजित किया है। इसमें फरीदाबाद, सोनीपत और गुरूग्राम के टैंडर हो चुके हैं बाकि कलस्टरों का प्रस्ताव कार्य प्रक्रिया में है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा कि छोटे शहरों व कस्बों में भी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी बहुत समस्याएं होती है जिनके लिए बहुत विशेष प्रबंध नहीं होता है जैसे पेयजल, परिवहन, सीवरेज, कूड़ा प्रबंधन, पार्क इत्यादि। इन सभी समस्याओं के निपटान के लिए व शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 25 जून, 2015 को राजधानी दिल्ली में ''अमरूत परियोजना'' की शुरूआत की थी। इस परियोजना के अंतर्गत बिजली पानी की सप्लाई, सीवरेज, कूड़ा प्रबंधन, अच्छी सड़कें, पार्क, चारों तरफ हरियाली के विकास के लिए 5 हजार करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की है। उपाध्यक्ष महोदया, इस अनूठी पहल के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शहरी विकास व कस्बों के विकास के लिए ''अमरूत योजना'' जैसी महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ रहा है। इसलिए यह योजना जरूर साकार होगी। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा प्रदेश के 20 स्थानीय शहर पंचकुला, गुड़गांव, अंबाला शहर, अम्बाला सदर, थानेसर, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत, बहादुरगढ, पलवल, सिरसा और जीन्द को शामिल किया गया हैं इनमें से 8 शहर थानेसर, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर व पानीपत में सीवरेज, वाटर सप्लाई व पार्को के प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं व अन्य 12 शहरों का सर्वे चल रहा है। मैं आदरणीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 27 करोड़ रूपये इस क्षेत्र के लिए आबंटित करने के लिए प्रस्ताव है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में शहरों को वाई–फाई करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसी के साथ पूरे प्रदेश के अन्दर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य किया जा रहा है। गुड़गांव और फरीदाबाद में यह कार्य चल रहा है तथा पंचकुला में कार्य पूरा हो चुका है और दूसरे शहरों के लिए टैंडर्स लगा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हमारी नगरपरिषद्ों/नगरपालिकाओं में स्ट्रीट लाईट का बिजली का बिल पहले कॉमर्शियल रेट पर आता था। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि

अब इसका बिल डोमैस्टिक बेसिज पर लिया जाएगा। इससे नगरपालिकों/नगरपरिषदों की वित्तीय स्थिति में बहुत लाभ हुआ हैं। शहरों में एल. ई.डी. स्ट्रीट लाईटों के लिए टैंडर्स किए जा रहे हैं जिनसे हमारे शहरों का सौंदर्यीकरण का काम होगा। शहरों के बाजारों में शौचालय बनाये जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा शहरों में 50 पार्क स्वर्ण जयंती के नाम से बनाने का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार ने पार्किंग की सुविधा के लिए जिन लोगों के पास के 500 गज से ऊपर के जो प्लाट हैं और जो पार्किंग बनाना चाहते हैं उनको प्राईवेट पार्किंग बनाने के लिए अनुमति प्रदान की है। शहरों में बी.पी.एल. परिवारों के पढे–लिखें बच्चों के लिए कौशल विकास योजना के तहत 3100 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ–साथ मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी तथा प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कुरूक्षेत्र को कृष्णा सर्किट प्रोजेक्ट में शामिल किया है और उसके लिए 97.5 करोड़ रूपये देने का काम किया। इस पैसे से हमारे जो तीर्थ स्थल हैं जैसे ज्योतिसर, ब्रह्मसरोवर, नरकातारी, छोटा ब्रह्मसरोवर आदि उनके लिए योजना बनायी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदया, कुरूक्षेत्र एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसमें टूरिज्म को बढावा देने के लिए यह कार्य किया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि आज से लगभग तीन वर्ष पहले जब गीता जयंती महोत्सव कुरूक्षेत्र में मनाया गया था तो उसमें 10,000 व्यक्ति आए थे। लेकिन पिछली बार प्रोफेसर राम बिलास शर्मा जी की पूरी टीम के साथ–साथ गीता जयंती के अवसर पर एक लाख लोग आये और अबकी बार यह महोत्सव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया और लगभग 18 लाख लोग वहां पर आए। 574 जिलों के लोग वहां पर आए। इसके लिए मैं पूरी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, कुरूक्षेत्र के गांव फतुहपूर की ग्राम पंचायत ने आयूष यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए 100 एकड़ जमीन का एक रिजोल्यूशन पास करके सरकार के पास भेजा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं इसको सैंक्शन किया जाए। इसके साथ ही साथ कुरूक्षेत्र एक टूरिज्म प्लेस है और इसके चारों तरफ बाईपास की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस कार्य को जल्दी पूरा करवाने का कष्ट करे। इसके अतिरिक्त भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो केवल कलकत्ता में स्थित है, इसकी एक ब्रान्च कुरूक्षेत्र में भी खुलवाने का प्रावधान किया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं।

**श्री कुलदीप शर्मा (गन्नौर):** उपाध्यक्ष महोदया आपने मुझे बोलने के समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । एक ऐसे समय में बजट पर चर्चा हो रही है जब सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि मैं रहूं या न रहूं सरकार की नीतियां ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं नहीं चाहता कि माननीय श्री मनोहर लाल जी सी.एम. न रहें क्योंकि अगर वह नहीं रहेंगे तो जो सी.एम. विंडों है वह सी.एम. विडो रह जाएगी।

**श्री राम बिलास शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं कुलदीप शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर रहेंगे।

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी पद पर नहीं रहेंगे तो जो सी.एम विंडो है वह सी.एम विडो बन जाएगी। अभी इस तरह की परिस्थितियां तो बनी ही हुई हैं।

**उपाध्यक्ष महोदया :** कुलदीप शर्मा जी, इस बारे में तो पार्टी अपने आप विचार करेगी।

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, लोग विचार कर रहे हैं। आपका का भी नंबर आ सकता है। हो सकता है कि आप उपाध्यक्ष के पद से मंत्री पद पर बैठ जाए और राम बिलास जी मंत्री पद से उपाध्यक्ष पद पर बैठ जाए। (शोर एवं व्यधान) परिस्थितियां कुछ भी बन सकती हैं।

**उपाध्यक्ष महोदया :** कुलदीप शर्मा जी, आप बजट पर अपनी बात कंटीन्यू करें।

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, बहुत से हमारे साथियों ने उधर से कहा था कि हम अनुभवहीन लोगों ने पता नहीं क्या–क्या कर दिखाया है। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ पवन सैनी :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं कुलदीप जी से कहना चाहता हूं कि इस बारे में तो वे खुद ही अच्छे से बताएंगे और मैंने तो यह भी कहा था कि कैसे अनुभवहीन होकर भी अच्छे काम करके दिखाये।

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, क्योंकि अब इनको बहुत सी बातों का अनुभव हो गया है।

**श्री महीपाल ढांडा :** उपाध्यक्ष महोदया, उन्होंने इस हरियाणा का बेड़ा–गर्क कर दिया। इनके कहने का मतलब है कि हम तो अनुभवहीन लोग हैं। हम तो हरियाणा प्रदेश की स्थिति सुधारना चाहते हैं।

**श्री कुलदीप शर्मा :** डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं यह कह रहा हूं कि अब इनको बहुत अनुभव हो गया है। बहुत लेन देन हो रहा है। हर चीज का अनुभव हो गया है। तो और गलत बयानी का भी अनुभव हो गया है। मैंने सदन में सुना था कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कुटेल में खुल रहा है उसका नाम रखा ही नहीं गया था। यह इकोनोमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2016–17 का डॉक्यूमैंट है, जिसमें लिखा है कि कल्पना चावला हैल्थ यूनिविर्सिटी एट विलेज कुटेल। इसका नाम बाद में बदल कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से रख दिया। मुझे कोई एतराज नहीं है नाम बदलने में, लेकिन अभी तक इकोनोमिक सर्वे में यह कल्पना चावला के नाम से चल रहा है। इसका मतलब उच्च स्तर पर गलतबयानी हो रही है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सवाल उठा था और मैंने भी उसमें इंटरवीन किया था और मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मैं अब से दो दिन पहले करनाल गया था और वहां पर यह चर्चा है कि कल्पना चावला यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर आपने दीन दयाल जी के नाम रख दिया। हमें कोई एतराज नहीं है दीन दयाल जी के नाम पर कुछ भी बनाओ लेकिन किसी का नाम बदलकर कोई दूसरा नाम रखना गलत है। मुख्यमंत्री जी ने on the floor of the House कहा था कि यूनिवर्सिटी का कभी नाम रखा ही नहीं गया था और यह डॉक्यूमैंट कह रहा है कि नाम रखा गया था। अब इसका फैसला कौन करेगा ? अगर मुख्यमंत्री जी की बात पर भी हम यकीन नहीं करेंगे तो किसकी बात पर भरोसा करेंगे।

**श्री राम बिलास शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी जो बात कह रहे हैं उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 संस्थाएं हैं। कल्पना चावला के नाम का मेडिकल कॉलेज है और यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। दोनों नाम सही हैं, एक के नाम यूनिवर्सिटी है और एक के नाम मेडिकल कॉलेज है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, हमने डाक्यूमेंट पढ़े हैं। उसमें उसका पूरा नाम कल्पना चावल मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। आप इकोनोमिक सर्वे

ऑफ हरियाणा 2016–17 के 120 नंबर पेज पर देखो तो उसमें साफ–साफ लिखा हुआ है कल्पना चावल मेडिकल यूनिवर्सिटी। उपाध्यक्ष महोदया, ये बहुत जिम्मेवार मंत्री हैं। on the floor of the House इन्होंने ऐसी बात कही है, इसलिए पहले इन्हें डाक्यूमैंट पढ़ लेने के लिए कहें।

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :** उपाध्यक्ष महोदया, आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं। ये 10 साल तक क्या करते रहे। इनको पता होना चाहिए कि नाम कब और कैसे रखा जाता है। एक मात्र मीटिंग हुई नाम रखने के लिए और उसमें उसका नाम दीन दयाल उपाध्याय रखना ही तय हुआ। (विघ्न)

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, विज साहब इकोनोमिक सर्वे ऑफ हरियाणा का पेज नम्बर 120 निकालकर देख लें। इसमें साफ लिखा हुआ है। (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, मैंने इकनोमिक सर्वे का पेज संख्या–20 ही नहीं बल्कि सारे पेज पढ़े हुए हैं । (शोर एवं व्यवधान) कहीं किसी ने कुछ कह दिया होगा । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी यह बतायें कि क्या इकनोमिक सर्वे में यह नहीं लिखा हुआ कि कुटेल मैडीकल यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावल के नाम से रखा जायेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, कहीं कुछ भी लिखा हुआ हो । हुड्डा साहब, ने दस साल राज किया है । उस समय ये सरकार चला रहे थे या भेड़ें चरा रहे थे । किसी भी संस्था का नाम रखने का अपना एक तरीका होता है । (शोर एवं व्यवधान) जिस समय इस मैडीकल यूनिवर्सिटी का नाम रखने के बारे में मीटिंग हुई उस समय एक ही नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय का सामने आया था और उसी के नाम से इसका नाम रखा जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, आप रूलिंग दें कि इकनोमिक सर्वे में इस यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावल के नाम से रखने बारे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ । It is a Government document. (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदया :** ठीक है, इसको चैक करवा लिया जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, यदि लिखा भी हुआ है तो क्या हुआ । इसको चैक करवाने की क्या जरूरत है ? हमने इसका नाम रखने के बारे में जो मीटिंग हुई थी उसमें पण्डित दीन दयाज जी का नाम ही तय किया था और उसी के नाम से यह यूनिवर्सिटी होगी । (शोर एवं व्यवधान) We have decided.

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी मान लें कि इन्होंने कल्पना चावला के नाम को बदला है । सरकार बदल सकती है । इसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन ये इस बात का मानें तो सही । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, हमने किसी का नाम नहीं बदला । कांग्रेस के साथियों को मालूम होना चाहिए कि नाम करण कब होता है ? जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसे पप्पू, बिला, काला आदि किसी भी नाम से बुलाया जाता है । उसका असली नाम तो नाम करण संस्कार के समय ही रखा जाता है । (शोर एवं व्यवधान) जिस समय इस मैडीकल यूनिवर्सिटी के नाम करण के विषय को लेकर मीटिंग हुई उस समय एक ही नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय का सामने आया था और उसी के नाम से इस मैडीकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी यह बतायें कि वह मीटिंग किस तारीख को हुई थी ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं कोई क्लर्क नहीं हूं जो तारीख याद रखूं और बता दूं । (शोर एवं व्यवधान) मैं मंत्री हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री करण सिंह दलाल :** उपाध्यक्ष महोदया, विज साहब मंत्री न होकर एक क्लर्क होते तो अच्छा होता । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं तारीख कहां से बता दूं । माननीय साथी मेरी पूरी बात तो सुन लें । मैं डाक्यूमैंट्स के बेस पर बात कह रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, गांव कुटेल की पंचायत ने जो रैजोल्यूशन किया था वह कल्पना चावल हैल्थ यूनिवर्सिटी के नाम से किया था या पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से किया था । मंत्री जी इस बारे में जानकारी दे दें हम

इनकी हर बात को मान लेंगे । मंत्री जी को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : उपाध्यक्ष महोदया, कुटेल गांव के लोगों ने मैडीकल यूनिवर्सिटी के नाम से ही जमीन दी है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदया, कुटेल गांव की पंचायत के रजोल्यूशन में कल्पना चावल मैडीकल यूनिवर्सिटी ही लिखा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : उपाध्यक्ष महोदया, कहीं भी लिखा हुआ हो । मैं केवल एक बात जानता हूं कि मेरी मौजूदगी में एक मीटिंग हुई और उसमें सभी ने माना कि इस मैडीकल यूनिवर्सिटी का नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से रखा जायेगा । उस मीटिंग में दूसरे नाम पर चर्चा नहीं हुई । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : उपाध्यक्ष महोदया, जो इनोमिक सर्वे का सरकारी डाक्यूमैंट इसको मंत्री जी डिसओन कर लें और मान लें कि इनकी जितनी भी किताबें हैं वे झूठ के पुलिंदे हैं । ये इस बात को मान लें । हम इनकी बात मान लेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब सारे सरकारी रिकार्ड को झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) मैं बार–बार बता चुका हूं कि जिस मीटिंग में इस मैडीकल यूनिवर्सिटी का नाम करण होना था उस दिन विस्तार से चर्चा हुई कि एक शहर में एक नाम के दो संस्थान खोलने का कोई औचित्यय नहीं है । कल्पना चावल मैडीकल कालेज पहले ही करनाल में चल रहा है और कुटेल मैडीकल कालेज का नाम पण्डित दीन दयाल के नाम से रखा जायेगा । This is on record.

**श्री राम बिलास शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदया, श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा और श्री कुलदीप शर्मा जी इकॉनोमिक सर्वे ऑफ हरियाणा जिस डॉक्यूमैंट का जिक्र कर रहे हैं, वह सही कर रहे हैं। ये दो संस्थायें हैं। कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज का तो बहुत सा काम जैसे बिल्डिंग का व स्टॉफ की नियुक्ति का पूरा हो चुका है। Kalpana Chawla Medical College is very much in existence जहां तक कुटेल यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है उसका नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यहां पर जानकारी दी है।

**श्री हरविन्द्र कल्याण** : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सदन के अंदर क्लीयर भी किया था। इस यूनिवर्सिटी के लिए जो 178 एकड़ जमीन दी गई है यह मेरे ही गांव की जमीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इस बात को स्पष्ट किया था कि जब इस यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई उस समय ऐसा विचार था कि कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज और कल्पना चावला यूनिवर्सिटी दोनों एक ही कैम्पस में रहेंगे। मगर बाद में जब यह तय हुआ कि इतनी कम जगह के अंदर मैडीकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हो सकती तब यह तय हुआ कि कुटेल के अंदर मैडीकल यूनिवर्सिटी बनेगी और जो मैडीकल कॉलेज है वह वहीं उसी जगह पर रहेगा। शुरू में जब यह चर्चा हुई तो उस समय अखबारों में इस मैडीकल यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावला नाम से रखे जाने की खबरें भी छपी थी। इस मामले में असलियत यह है कि जब मैडीकल यूनिवर्सिटी के नाम की बात आई तो पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखने का सुझाव सामने आया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पिछले दिनों स्पष्ट कर चुके हैं।

**श्री कुलदीप शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनके इस गुनाह के लिए इनको माफ करता हूं। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

**Shri Bhupinder Singh Hooda:** Madam Deputy Speaker, we are talking about the documents which are supplied by the Government. या तो ये कहें कि यह डॉकूमैंट गलत है अर्थात इसमें गलत लिखा है। We will accept it. या ये यह कहें कि पहले यह नाम था अब हमने इसको बदल दिया। सरकार ऐसी करती है क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है और अगर यह गलत हुआ है तो सरकार विन्रमता से अपनी गलती को स्वीकार कर ले लेकिन इस मामले में जिस प्रकार का रवैया सरकार द्वारा सदन में अपनाया जा रहा है वह ठीक नही है। This cannot be done. The Government cannot mis-lead the House. This is not accepted at any stage.

**श्री राम बिलास शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदया, यह डॉकूमैंट बिल्कुल सही है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि यह डॉकूमैंट छपने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर यह सूचना दी थी जिसका माननीय सदस्य श्री हरविन्द्र कल्याण जी ने

जिक्र किया है। यह उनके गांव का मामला है। मैं भी यह बात स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ही है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, यह कोई बहुत लम्बी पुरानी बात नहीं है। आज से तीन दिन पहले मैंने इस बारे में बात की थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे प्रोसीडिंग्स निकाली जायें और यह देख लिया जाये कि मैंने क्या कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? इस मामले में अभी फैसला हो जायेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछा था कि क्या कल्पना चावला मैडीकल यूनिवर्सिटी के नाम की कभी घोषणा हुई है। मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने यह कहा था कि नहीं हुई है। यह रिकार्ड की बात है। इसलिए अगर अथॉरिटी जरूरत समझे तो रिकार्ड को निकलवाकर चैक करवाया जा सकता है। मैं भी यह बात मानता हूं कि मैं भी गलती पर हो सकता हूं लेकिन अगर मेरी गलती हुई तो मैं भी उसके लिए माफी मांग सकता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदया :** ठीक है, इस मामले को बाद में देख लिया जायेगा। अभी आप कृपया करके बैठ जायें और हाउस की कार्यवाही को चलने दें।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** उपाध्यक्ष महोदया, हमारे पास जो सरकार का डॉकयूमैंट है इसमें कुटेल गांव का नाम लिखा हुआ है। महोदया, आप इस मामले में अपनी रूलिंग दे दें। हम यह भी कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम सरकार बदल सकती है क्योंकि सरकार इसके लिए सक्षम है। सरकार इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दे हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले ये इस बात को असैप्ट करें कि पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावला यूनिवर्सिटी था जिसको हमने बदलकर पण्डित दीन दयाल उपाध्याय रख दिया है। (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस मामले पर श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और श्री कुलदीप शर्मा जी चर्चा कर रहे हैं इसमें यह नाम गलती से छप गया होगा इसलिए इसको ठीक करवा दिया जायेगा।

**उपाध्यक्ष महोदया :** हुड्डा जी, आप कृपया करके बैठ जायें। कुलदीप शर्मा जी, आप कृपया कंटीन्यू करें।

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश की जनता हर साल इंतजार करती है कि बजट आयेगा लेकिन बजट में जनता के हाथ कुछ नहीं आया । यह बात ठीक है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा है । बजट आंकड़ों और संख्या का खेल है । अब टैक्स नहीं लगा है क्या सरकार कहेगी कि इस बजट से लेकर अगले बजट तक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जायेगा । पिछले साल देखने में आया कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगा था लेकिन उसके एक महीने के बाद ही न जाने कितनी बार टैक्सिज को बढ़ाया गया और रेट्स को रिवाइज किया गया और टैक्स बढ़ाये गये । क्या वित्त मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि पूरे साल आज जो बजट ऐस्टीमेट्स हैं वही रखेंगे और घाटे को पूरा करने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया जायेगा । आज हरियाणा की जनता सबकुछ देख रही है । उपाध्यक्ष महोदया, गन्नौर विधान सभा का प्रतिनिधि होने के नाते मैं 2–3 बातें जरूर कहना चाहूंगा । एन.सी.आर. से चण्डीगढ़ की तरफ चलने के बाद गन्नौर ऐसा पहला शहर है जो जी.टी. रोड पर लगता है । अभी तक सरकार ने गन्नौर को इग्नोर कर रखा है और गन्नौर की इम्पौर्टेंस को अण्डरमाइन किया है । हमने कोशिश की थी कि वहां पर इन्टरनेशनल होर्टीकल्चर, फ्लॉवर और वेजीटेबल मार्केट लगे । उसके लिए प्रयास हुये लेकिन वे प्रयास सफल नहीं हुये । फसल विविधीकरण के बारे में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं । घोषणाएं अलग बात है लेकिन घोषणाओं के क्रियान्वयन की बात जहां आयेगी तब सरकार की असली नीयत का पता लगेगा । आज के दिन स्थिति यह है कि गन्नौर की डिवैल्पमैंट टिंटिड है । आज इन्टरनेशनल होर्टीकल्चर मार्केट में भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसी तरह से राजीव गांधी एजूकेशन सिटी एक इम्पोर्टेंट लैंड मार्क बन सकता था जहां 1 लाख से 2 लाख तक के छात्रों की कैपेसिटी है it would have been the Cambridge of East. उसको भी इस सरकार ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है हालांकि वह राई विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है । इसी तरह से तीसरी बात जो गन्नौर में इग्नोर हो रही है वह है गन्नौर का स्पोर्ट्स पोटैंशियल । हमारे इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां नेशनल और इन्टरनेशल लेवल के प्लेयर्स हैं, लेकिन वहां पर कोई भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवाया गया है । गन्नौर रीजन को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इग्नोर किया गया है ।

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :** उपाध्यक्ष महोदया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रिय मित्र शर्मा जी ने बजट स्पीच को ठीक से सुना नहीं है । पहली बार सरकार ने

अगर किसी मद में सबसे ज्यादा पैसा बढ़ाया है तो वह स्पोर्ट्स में बढ़ाया गया है । स्पोर्ट्स में 59 प्रतिशत बजट इन्क्रीज हुआ है । जब हमारी सरकार आई थी उस समय स्पोर्ट्स का 80–90 करोड़ रुपये का बजट होता था लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद इस साल स्पोर्ट्स के लिए हम 550 करोड़ रुपये का बजट लेकर आये हैं । हम इतना बजट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ही लेकर आये हैं । हम कांग्रेस सरकार की तरह नहीं हैं कि गांवों में पंचायती राज की तरफ से स्टेडियम के रूप में इंटें खड़ी करके चले गये । न तो वहां पर कोच लगाये गये और न ही वहां पर इक्विपमैंट्स खरीदे गये केवल सिविल वर्क करके और अपना कमीशन लेकर चले गये । हम योजनाबद्ध तरीके से सबकुछ बना रहे हैं और हर गांव में एक व्यायामशाला और योगशाला बनाने का काम शुरू किया है । यह सभी 6500 गांवों में किया जायेगा । 700–800 गांवों में तो इस साल बनाने की पूरी सम्भावना है जिनकी सभी अनुमति दी जा चुकी हैं ।

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ऐसी घोषणाएं करने की आदी हो चुकी है । मैं जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन की बात कर रहा हूं । अढाई साल तो आपकी सरकार के निकल गये हैं और बाकी के अढ़ाई साल भी निकल जायेंगे उसके बाद जब कुश्ती होगी तो हम इनको बतायेंगे कि आप स्पोर्ट्स को कितना आगे लेकर गये हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदया :** शर्मा जी, आपको आगे आने वाले अढ़ाई साल के बारे में कैसे पता है कि सरकार कुछ नहीं कर पायेगी?

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं पंडित हूं और मैं इतना तो जानता ही हूं । आगे आने वाली बात के बारे में बता सकता हूं । इसी प्रकार से ऐग्रीकल्चर में मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस बात को नोट कर लें क्योंकि सरकार का

16:00 बजे

दावा है कि एग्रीकल्चर में बहुत कुछ इनवैस्ट हो रहा है लेकिन हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिसर्च कितनी आ रही हैं । आज तक गन्ने की किस्मों को सुधारने के लिये सरकार ने क्या किया है ? राईस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये क्या किया है ? क्रोप वेयर हाउसिंग के लिये क्या किया गया है ? एनीमल हसबैंड्री के लिये क्या प्रोग्राम्ज हैं ? उन बातों को तब महत्व मिलेगा जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिसर्च आएगी । एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस बारे में कुछ नहीं हो रहा है । इसलिये एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए । एजूकेशन

विभाग के लिये बजट में बड़ी एलोकेशन आई है । इतनी बड़ी एलोकेशन के बाद भी एजूकेशन सैक्टर की आउटपुट के लिये बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । प्रदेश में कॉलेज तो बना दिये गये और उस समय बड़ी मेजें भी थपथपाई गई थी कि प्रदेश में 21–22 नये कॉलेजिज की आधारशिला रखी गई हैं । परिस्थिति यह है कि गवर्नमैंट कॉलेजिज और एडिड कॉलेजिज को मिलाकर केवल 15 प्रिंसिपल रेगुलर हैं और 12 प्रिसिंपल टैम्प्रेरी हैं जो कॉलेजिज में काम कर रहे हैं । जब कॉलेजिज में प्रिंसिपल ही नहीं हैं, टयूटोरियल स्टाफ नहीं है, लैक्चरर नहीं हैं तो किस एजूकेशन की आउटपुट की बात कर रहे हैं । एजुकेशन की एलोकेशन सबसे बढ़िया जरूर हो गई है । आप देखेंगे कि एजूकेशन सैक्टर में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही हैं । लेकिन एजूकेशन सटैंडडर्डाइज्ड नहीं हो रही है । माननीय मंत्री महोदय, रिसर्च कहां है ? रिसर्च के बारे में बताएं कि एजूकेशन सैक्टर के अन्दर रिसर्च का क्या हाल है ? एजूकेशन का हाल ये है कि नये पेपर पब्लिश नहीं हो रहे हैं । नई रिसर्च निकल कर सामने नहीं आ रही हैं । मंत्री जी मुझे ये बताएं कि दाखिले क्यों फॉल कर रहे हैं ? क्यों स्टाफ की कमी है टीचर्स नहीं हैं और एजूकेशन की एलोकेशन सबसे ज्यादा है । इसमें आप क्या प्रोमिस करना चाहते हैं जब स्कूलों में टीचर्स नहीं रहेंगे, कॉलेजिज में प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, लैक्चरर्ज नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या आप एजूकेशन विभाग के लिये सबसे ज्यादा बजट लेंगे ? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राईमरी लैवल पर स्कूल्ज हैं उनमें दाखिले बहुत बुरी तरह से फॉल कर रहे हैं जिसके बारे में एजुकेशन मिनिस्टर को ध्यान देने की जरूरत है । सिर्फ सबसे बड़े बजट अलोकेशन से काम नहीं चलेगा । अर्बन डिवैल्पमैंट के अन्दर सबसे बड़ा पोटैंशियल जहां है वह गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ की तरफ है लेकिन सोनीपत, गन्नौर और पानीपत की तरफ अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर को विशेष ध्यान देना होगा । वहां पर जो रोड़ इन्फ्रास्ट्रैक्चर है उसके ऊपर एन.सी.आर. रीजन में पर्टिकुलरली इस एरिया के अन्दर जो मासरेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एम.आर.टी.एस.) है या मैट्रो की एक्सटैंशन है वह फरीदाबाद भी चली गई, बहादुरगढ़ भी चली गई । रोहतक तक पहुंचने के आसार हैं, गुड़गांव तक पहुंच गई और मानेसर तक पहुंच गई, रेवाड़ी तक भी पहुंचाने की बात हो रही है लेकिन इस तरफ मैट्रो के पहुंचने की बात अभी तक सरकार के सामने नहीं आई है । इसलिये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जो देखने में आ रही है कि नैशनल कैपिटल रीजन के अन्दर

बहुत अन–अथोराईज्ड ग्रोथ ऑफ कॉलोनिज हो रही है । हमारे गन्नौर विधान सभा के अन्दर रोजाना एक नई कालोनी बन जाती है । वहां रोजाना नई सड़कें दिखा देते हैं और एक नई कॉलोनी बन जाती है । अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप ग्रोथ को अथोराईज नहीं करेंगे और अगर इसी तरह मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ कॉलोनिज होता रहेगा तो जो ये योजनाओं का नाम रख कर के कभी श्री मंगल सैन जी के नाम पर या किसी और के नाम पर, इससे अर्बन डिवैल्पमैंट को क्या फायदा पहुंचने वाला है, जबकि इल्लीगल और अन एप्रूवड कालोनिज की मशरूमिंग ग्रोथ हो रही है । मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार की इच्छा के बिना नहीं हुआ करती है। मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी लाया था । अब वे यहां नहीं बैठे हैं लेकिन उनके नोटिस में यह बात है । वरना वह इस बात को मना नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार से आपकी सरकार के लोग इल्लीगल कॉलोनिज कटवा रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने उनको चैक भी करवाया है लेकिन वे कॉलोनिज रूकने की बजाय यूं की यूं बढ़ती जा रही हैं । रोजाना एक नई कॉलोनी निकल कर आ रही है । इससे सरकार की मंशा का पता लगता है ।

**श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा उन व्यक्तियों जो, राज्य में राज्य सरकार के संरक्षक कार्यवाहक के अधीन अवैध खनन कर रहे हैं, के विरूद्ध आरोप लगाना।**

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं माइनिंग के बारे में सदन को बताना चाहता हूं । जहां तक माइनिंग की बात है, माइनिंग के लिये सरकार ने कहा कि माइनिंग इनके लिये बहुत बड़ा रवैन्यू जनरेट करेगा । वह कहां से करेगा ? मैं जिस कांस्टीट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ वह यमुना के साथ साथ लगती है। वहां पर बहुत ज्यादा इल्लीगल माईनिंग हो रही है। इल्लीगल माइनिंग कौन करवा रहा है? मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अच्छा नहीं लगता है कि मैं सदन में उन लोगों के नाम लूं जो इस काम को करवा रहे है? निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ हैं तथा सरकारी लोग हैं, जिनकी मिलीभगत से इल्लीगल माईनिंग हो रही है और हर रोज हो रही है। तीन चार बार तो मैंने खुद ट्रकों की हवा निकलवाई है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जसविन्द्र सिंह संधू:** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय कुलदीप जी को उनका नाम बताना चाहिए? क्या इस तरह के लोग जो इललीगल माईनिंग करवा रहे हैं इनके रिश्तेदार हैं, जो यह सदन में उनका नाम नहीं बता रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, इल्लीगल माईनिंग तो यमुनानगर से लेकर दिल्ली बार्डर तक और हरियाणा प्रदेश के कईं हिस्सों में हो रही है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी):** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा । शर्मा जी, इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम तो बताने ही पड़ेंगे?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर इल्लीगल माईनिंग न हो रही हो? यही पर वे लोग बैठे हुए है जो इललीगल काम करवा रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मूल चंद शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी को इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताने होंगे? यह इस तरह दबी आवाज में आरोप नहीं लगा सकते हैं। इनको उनके नाम स्पष्ट रूप से बताने पड़ेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी को इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताने पड़ेंगें? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मूलचंद शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी ने दबी आवाज में आरोप लगाकर एक तरह से पूरे सदन पर आरोप लगाया है। इनको स्पष्ट रूप से इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताने होंगे? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, मै माननीय मुख्यमंत्री जी को कह चुका हूँ कि मैं बाद में अकेले में इन लोगों के नाम बताउंगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मूलचन्द शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से शर्मा जी को कहना चाहता हूँ कि वे इस तरह की बात करके एक तरह से सदन के सभी सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, जितनी इल्लीगल माइनिंग कांग्रेस के शासनकाल में हुई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। (शोर एवं व्यवधान) अगर हमारी सरकार के समय किसी भी आदमी ने इल्लीगल माइनिंग की है और कोई बात हमारे संज्ञान में आई है तो हमने उसी समय ऐसे इल्लीगल माइनिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह के बयान देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) शर्मा जी को इल्लीगल

माइनिंग करने वाले सदन में बैठे व्यक्तियों के नामों को जरूर बताना चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा मंत्री जी से अनुरोध कि यदि वे एक बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र गन्नौर में आयें, तो इन्हें हकीकत से रूबरू करा दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री नायब सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ हमारी सरकार के समय में बहुत ही गम्भीरता के साथ कार्रवाई की गई है। इनके कार्यकाल में जो भी किसी भी प्रकार के इल्लीगल भू–माफिया हरियाणा में पनपे थे, हमने उन सभी भू–माफियाओं को समाप्त करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

**परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार):** उपाध्यक्ष महोदया, जैसाकि अभी शर्मा जी ने इललीगल माइनिंग की बात की है तो उस परिपेक्ष्य में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमने अभी 14 फरवरी से लेकर आज तक 6 करोड़ 81 लाख रूपये के ओवरलोडिंग गाड़ियों के चालन किए हैं। हमारी सरकार माइनिंग के क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशील है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जसविन्द्र सिंह संधूः** उपाध्यक्ष महोदया, यह मामला बहुत गम्भीर है इसलिए कुलदीप शर्मा जी को सदन में इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. पवन सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताने से क्यों बच रहें हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मूलचन्द शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, अगर ये नाम नहीं बता सकते हैं तो इनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिए और सदन से माफी मांगनी चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री जाकिर हुसैनः** उपाध्यक्ष महोदया, सदन में नाम जरूर बताये जाने चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. पवन सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी, या तो इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बतायें या फिर अपने शब्द वापिस ले? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री करण सिंह दलालः** उपाध्यक्ष महोदया, यदि कुलदीप शर्मा जी ने नाम बता दिए तो सरकार में बैठे कई लोगों के इस्तीफे हो जायेंगे?(शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. पवन सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, आप दलाल साहब को बिठायें। (शोर एवं व्यवधान) सदन की कार्यवाही तभी आगे बढ़ेगी जब कुलदीप शर्मा जी अपने शब्द वापिस लेंगे और सदन से माफी मागेंगे । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सदन में बैठे उन लोगों के नाम बताये जायें जो इल्लीगल माइनिंग में शामिल हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदया, अभी कुलदीप शर्मा जी ने सरकार के उपर बहुत गम्भीर आरोप लगाये हैं और आरोप भी माइनिंग की चोरी का लगाया है और यह भी कहा है कि मैने मुख्यमंत्री जी से इस मामले में इंक्वॉयरी करवाने वाली बात कही है। इन्होंने यह भी कहा इनके पास इल्लीगल माइनिंग करने वाले लोगों के नाम मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हम भी चाहते है कि इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताये जायें और सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताये जायें, तो फिर नाम बताने में संकोच क्यो है?(शोर एवं व्यवधान) कुलदीप शर्मा जी ने यह भी कहा है कि इल्लीगल माइनिंग के काम में मंत्री भी शामिल हैं और आफिसर्ज भी शामिल है। उपाध्यक्ष महोदया, सौ फीसदी उन लोगों के नाम उजागर होने चाहिएं जो लोग इस कार्य में शामिल हैं। अगर कुलदीप शर्मा जी नाम नहीं बता रहे हैं तो कहीं न कहीं इनकी भी सांठ–गांठ है या फिर करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान ) या तो सदन में नाम बताये जायें और अगर न बताये जायें तो माफी मांगी जाये। दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ज्ञान चंद गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदया, शर्मा जी द्वारा इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं हैं और इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदया, इनको दोनों में से एक काम करना ही पड़ेगा? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, मैं अभय सिंह चौटाला जी से पूछना चाह रहा हूँ कि कि क्या अब भी इल्लीगल माइनिंग नहीं हो रही है? मै इस बारे में मुख्यमंत्री जी को अकेले में बताऊंगा। मुझे अभय सिंह चौटाला से किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदया, बात सर्टिफिकेट की नहीं है। इल्लीगल माइनिंग हो रही है और शर्मा जी ने यह कहा था उन्हें सदन में बैठे हुए उन लोगों के नाम मालूम हैं जो इल्लीगल माइनिंग करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) यदि सत्ता पक्ष के लोग इल्लीगल माइनिंग करने वाले लोगों के नाम जानना चाहते हैं तो उन्हें भी खड़े होकर कुलदीप शर्मा से उन लोगों के नाम पूछने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने सदन में कहा था कि इन्होंने ट्रकों की हवा निकाली। (शोर एवं व्यवधान) जिन ट्रकों की हवा निकाली वे ट्रक किसके थे?(शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा को इल्लीगल माइनिंग करवाने वाले लोगों के नाम बताने चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदया** : कुलदीप शर्मा जी, आप प्रदेश में इल्लीगल माइनिंग कराने वाले लोगों के नाम बताइये ? उनके नामों को सारा सदन जानना चाह रहा है ।

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा को नाम बताने चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. पवन सैनी :** उपाध्यक्ष महोदया, सदन में यह नहीं होना चाहिए कि जो मुंह में आया वो बोल दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा को उन लोगों के नाम अवश्य बताने चाहिएं जो हरियाणा में इल्लीगल माइनिंग करा रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा को या तो अपनी कही हुई बात पर माफी मांगनी चाहिए या फिर उनके नाम बताने चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदया** : शर्मा जी, अगर आपको प्रदेश में इल्लीगल माइनिंग कराने वाले व्यक्तियों के नाम मालूम हैं तो हाउस को बताइये ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा ने सदन में सरकार पर बहुत गम्भीर आरोप लगाए हैं । मेरा विचार है कि भ्रष्टाचार को छुपाना भी भ्रष्टाचार ही होता है । अगर माननीय सदस्य उनके बारे में जानते हैं और सदन में उनका नाम नहीं बताना चाहते हैं तो इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है । अगर इनको नाम पता हैं तो इनको सदन में बताने चाहिए और सदन में फेक बातें नहीं

करनी चाहिए । सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनके नाम जानना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है । ये भ्रष्टाचार का पोषण करने वाले हैं । ये भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले नहीं हैं । ये केवल यहां पर तमाशा खड़ा करना चाहते हैं । इनके पास इस संबंध में कहने के लिए कोई बात नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्मा :** माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैंने अभय जी के साथ–साथ सभी माननीय सदस्यों से यह सवाल पूछ लिया है कि क्या हरियाणा में इल्लीगल माइनिंग हो रही है ? इस प्रश्न का जवाब सभी ने हाँ में दिया है । (शोर एवं व्यवधान) सभी कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में इल्लीगल माइनिंग हो रही है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा को या तो सदन में उनके नाम बताने चाहिए या सदन से बाहर चले जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य शर्मा जी ने सदन में कहा है कि इनको इल्लीगल माइनिंग कराने वालों के नाम पता है इसलिए ये उनके नाम बतायें । अगर ये उनके नाम नहीं बताते हैं तो सदन से बाहर चले जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री नायब सैनी :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इनके समय में खनन माफिया पनपे हुए थे । इनका खनन माफिया को संरक्षण था । हमारी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उसे सभी देख सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**पं. मूल चंद शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा को इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम बताने चाहिएं ताकि इस बारे में जांच की जा सके । (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदया :** शर्मा जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहता है कि आप सदन को उनके नामों से अवगत करवायें । अतः आप इस बारे में स्पष्टीकरण दीजिए । अगर आप इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपकी खनन माफिया संबंधी कही हुई सारी बात को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा । अतः आप इस बारे में क्लीयर कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदया, यह क्या बात हुई ? एक आदमी सदन में आकर झूठ बोलता है और आप उसकी कही हुई बात को सदन की कार्यवाही से निकाल देने की बात कह रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ज्ञान चन्द गुप्ता :** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इनकी कही हुई ऐसी किसी भी बात को सदन की कार्यवाही से न निकाला जाए । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा ने सदन में झूठ बोला है । इनका कहना है कि ये प्रदेश में इल्लीगल माइनिंग करने वालों के नाम जानते हैं । अगर ये उनका नाम जानते हैं तो सदन को उससे अवगत करवाये । (शोर एवं व्यवधान)

**मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती सीमा त्रिखा) :** उपाध्यक्ष महोदया, इस सदन को गुमराह किया जा रहा है । माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा एक बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं । हम इनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं । इन्होंने हमारी सरकार पर गम्भीर आरोप लगाया है इसलिए इनको या तो अपने शब्द वापस लेने चाहिए या फिर उनके नाम सदन में उजागर करने चाहिए । हमें हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता ने इस महान सदन में चुनकर भेजा है । माननीय सदस्य इस महान सदन में प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार पर खनन चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, यह सरासर गलत है । मैं चाहूंगी कि या तो माननीय सदस्य को उनके नाम बताने चाहिए या फिर आज इनका सदन में बोलने का जो समय है उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया, इस महान सदन के जो अनेक सदस्य मेरे साथ बहस करने के लिए खड़े होकर बोल रहे हैं जब तक ये चुप नहीं होते तब तक मैं उनके नाम भला कैसे बता सकता हूं ? (शोर एवं व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदया :** कुलदीप शर्मा जी, आज आपने सदन में स्टेटमैंट दी थी कि मुझे उन लोगों के नाम पता हैं जो हरियाणा में इल्लीगल माइनिंग करा रहे हैं और मैंने इस विषय में मुख्य मंत्री जी को भी लिखा था । जब पूरा सदन उनके नाम जानना चाहता है तो आपको उनके नाम बता देने चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, इस बात में तो कोई ऑब्जैक्शन नहीं है कि अवैध रूप से माईनिंग हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा ने कहा है कि अवैध माईनिंग हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवर :** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप जी, सदन को उनके नाम बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विजः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी को आज सदन में नाम बताने पड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. पवन सैनीः** उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी सदन को नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, अवैध रूप से माईनिंग हो रही है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, सरकार के सरंक्षण में ही अवैध रूप से माईनिंग हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) बिना सरकार के सरंक्षण अवैध रूप से माईनिंग नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान) यह माईनिंग सरकार करवा रही है। मैं सदन में किस–किस का नाम लूं। (शोर एवं व्यवधान

**उपाध्यक्ष महोदयाः** कुलदीप जी, आप सदन को उनके नाम बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवरः** उपाध्यक्ष महोदया, शर्मा जी ने कहा है कि यमुना नगर से पलवल तक अवैध रूप से माईनिंग हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा हूँ कि कालका निर्वाचन क्षेत्र से लेकर पलवल निर्वाचन क्षेत्र तक सरकार के विधायक हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवरः** उपाध्यक्ष महोदया, सरकार तो पूरे हरियाणा में है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** उपाध्यक्ष महोदया, सरकार के सरंक्षण के बिना माईनिंग नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान) (**इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

**श्री अध्यक्षः** शर्मा जी, आप सदन को नाम बताएं। (शोर एवं व्यवधान) शर्मा जी, आपने कहा है कि मेरे पास नामों की जानकारी है तो आप उन नामों को सदन में बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** अध्यक्ष महोदय, मैं कह तो रहा हूँ कि अवैध रूप से माईनिंग सरकार करवा रही है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार के सरंक्षण में हो रही है।

**श्री अध्यक्षः** शर्मा जी, यह कोई नाम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्माः** अध्यक्ष महोदय, जब अवैध रूप से हो रही माईनिंग के ट्रक को पकड़ा नहीं जाता तो अवैध रूप से माईनिंग कौन करवा रहा है? (शोर एवं व्यवधान) यह काम सरकार करवा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :** अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी ने आधे घंटे से सदन में एक हंगामा सा खड़ा किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी ने नाम वाली बात सही नहीं कही है। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथी और सत्ता पक्ष के साथी चाहते हैं कि कुलदीप शर्मा जी उनके नाम सदन में बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवर :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके पास नामों की सूची है वे लोग सदन में बैठे हैं जो इल्लीगल माईनिंग करवा रहे हैं।(विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, इनकी इनक्वायरी करवा लेते हैं।(विघ्न)

**मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती सीमा त्रिखा) :** अध्यक्ष महोदय जी, या तो माननीय सदस्य उनका नाम बता दें अन्यथा जो शब्द कहे गये हैं उनको सदन की कार्यवाही से हटवा दिया जाये।(विघ्न)

**श्री ज्ञान चंद गुप्ताः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन में झूठ बोल रहे हैं।(विघ्न)

**श्री कुलदीप शर्माः** अध्यक्ष महोदय, इस तरह की खबरें प्रतिदिन अखबारों में छपती रहती हैं। (विघ्न)

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ :** अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी आप अखबारों की बात ना करें। अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो ये सदन में प्रस्तुत करें। सभी माननीय सदस्य इन नामों के बारे में जानना चाहते हैं। (विघ्न)

**श्री कुलदीप शर्माः** अध्यक्ष महोदयः मेरे हल्के में अवैध खनन का कार्य चल रहा है और मैं प्रतिदिन यह देखता हूं। (विघ्न)

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो माननीय सदस्य सदन में माफी मांगे अन्यथा उनके नाम सदन में बताएं। अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाइए। (विघ्न)

## श्री कुलदीप शर्मा एम.एल.ए. द्वारा आरोप लगाने संबंधी तथा उनके विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करने संबंधी मामला उठाना

**शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :** अध्यक्ष महोदय, लगभग आधे घंटे से पूरे सदन के सदस्य माननीय सदस्य कुलदीप शर्मा से बार–बार आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो इल्लीगल माईनिंग के बारे में कहा है कि प्रदेश में इल्लीगल माईनिंग हो रही है और उसमें लिप्त लोग इस सदन में बैठे हैं ये उनके नाम बताएं या अपनी बात विदड्रा कर लें। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में यह तीसरा वाक्या है जिसमें माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा ने खनन माफिया पर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। यह सदन माननीय सदस्य के इस बयान की निन्दा करता है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** यदि हाउस की सहमति हो तो माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा के खिलाफ यह निन्दा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाए।(विघ्न)

**आवाजें:** हां जी।

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, यह निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। (प्रस्ताव पारित हुआ।)

**श्री कुलदीप शर्माः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री अनिल विज मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। (विघ्न)

**डा0 पवन सैनीः** अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह पाप का भागीदार होता है।

**श्री अध्यक्षः** पवन जी, आप बैठ जाइये।

**श्री अनिल विजः** स्पीकर सर, मैंने सिद्धान्त की बात बतायी है कि जो भ्रष्टाचार करने वालों को बचाता है वह भी भ्रष्टाचार में शामिल होने के बराबर है।(विघ्न)

**श्रीमती शकुंतला खटकः** अध्यक्ष महोदय, सरकार इसकी जांच करवा लें।(विघ्न)

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, सरकार इसकी जांच करवा ले, नाम तो मुझसे पूछ लीजिए मैं भी बता सकता हूं।(विघ्न)

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से खनन माफियाओं के नाम पूछना चाहता हूं।(विघ्न)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी कह रहे थे कि पूरे प्रदेश के अन्दर इल्लीगल माईनिंग हो रही है। यह बात माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री के नोटिस में भी लायी थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यमुनानगर से लेकर पलवल तक के क्षेत्र में जो इल्लीगल माईनिंग हो रही है उसमें सरकार के मंत्री और विधायक शामिल हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच करवाने की बात कही थी। (विघ्न)

**श्री कुलदीप शर्माः** अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार के मंत्रियों के बारे में नही कहा था।

**श्री अध्यक्षः** एक ही बात है।(विघ्न)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवरः** अध्यक्ष महोदयः मंत्रियों के भी लिप्त होने की बात कही थी।(विघ्न)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** अध्यक्ष महोदय यह कहा गया था कि मंत्री और अधिकारी सदन में बैठे हैं उनके सरंक्षण में यह सारी इल्लीगल माईनिंग हो रही है। माननीय सदस्य ने बताया है कि वे उन मंत्रियों के नाम जानते हैं तो ये नाम बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं। सिर्फ एक निन्दा प्रस्ताव लाकर सारे मामले में लीपापोती की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा मुददा है क्योंकि प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी इस इल्लीगल माईंनिग के मामले में भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाये हैं उनके नाम लेकर कार्रवाई करें। अन्यथा सरकार इस मामले में चुप्पी साधकर अपने मंत्री के साथ–साथ अधिकारी को भी बचाने की कोशिश कर रही है।

**श्री अध्यक्षः** अभय सिंह जी सारे सदन में यह मैसेज चला गया है कि जो माननीय सदस्य ने बयान दिया है वह गलत है । उसी को लेकर निन्दा प्रस्ताव लाया गया है।(विघ्न)

**श्री कुलदीप शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, यह सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है, सरकार की मर्जी से हो रहा है और सरकार के लोग ही कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हो गया कि उन्होंने कही है उस बात को आपने स्वीकार कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अभय जी, सरकार कुलदीप शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आयी है और हमने निंदा प्रस्ताव को पास भी कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदमी यहां खड़ा होकर झूठ बोल देगा और उसके खिलाफ यदि आप केवल निंदा प्रस्ताव ले आएंगे तो क्या बात खत्म हो जाएगी? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** चौटाला जी, अब आप ही बताओ कि क्या किया जाए? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ज्ञान चंद गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदन में झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ आपको प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि उसके खिलाफ केवल निंदा प्रस्ताव ही ले आएं और उसका पीछा छोड़ दिया जाये। इस तरह तो सदन में हर व्यक्ति झूठ बोलने का काम करेगा। फिर तो किसी को इस बात का डर ही नहीं रहेगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन लेकर आओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनकी बात को मान लिया है। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके मंत्री और अधिकारी मिलकर इस प्रदेश में यह काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी ने हाउस में कहा है कि इल्लीगल माइनिंग करने वाले जो लोग हैं वे यहीं बैठे हैं, इसका मतलब क्या हैं? इन्होंने कहा मैं नाम जानता हूं, अवैध खनन कराने वाले यहीं बैठे हैं, ये

शब्द संपूर्ण सदन में से किसके लिए यूज हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इल्लीगल माइनिंग करने वाले लोग यहां बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम नहीं बतायेंगे तो यह पूरे सदन का अपमान है। आखिर इल्लीगल माइनिंग करने वाले कहां बैठे हैं? इस तरह ये पूरे सदन का अपमान है। अगर ये व्यक्तिगत इरादे से यह बात कह रहे हैं तो व्यक्तिगत कहें वरना यह पूरे सदन का अपमान है और इस अपमान के बदले इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इनके खिलाफ लाना चाहिए, निंदा प्रस्ताव लाना वह कम है। यह निंदा तो थी पर यह सुबह के मामले में थी, लेकिन अब यह निंदा नहीं है, यह सदन के माननीय सदस्यों पर आरोप है और किसी भी सदस्य को सदन के माननीय सदस्यों पर इस प्रकार से आरोप लागने का हक नहीं है। वे कौन लोग यहां बैठे हैं, ये उनके नाम बताएं। अगर नाम नहीं बताते तो इन्होंने बहुत गलत किया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि सरकार करवा रही है, (शोर एवं व्यवधान) सरकार की मर्जी से हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री पवन सैनी :** अध्यक्ष महोदय, केवल निंदा प्रस्ताव लाने से काम नहीं चलेगा या तो इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए या आप इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आएं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कविता जैन :** अध्यक्ष महोदय, केवल अपने शब्द वापस लेने से काम नहीं चलेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** पवन जी, वह कार्रवाई हम कर लेंगे, अभी आप लोग सदन को आगे चलने दें। हम इस बात की चर्चा बाद में कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग प्रिविलेज मोशन ले आइए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा था कि मैंने उनका नाम लिया तो ये सरकार गिर जाएगी, अब तो नाम जानना बहुत जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इतना बड़ा आरोप सारे सदन के ऊपर लगाया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह सिर्फ निंदा प्रस्ताव लाने से हम सहमत नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है, आप लोग प्रिविलेज मोशन ले आइए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत बात है। आप ऐसे लोगों को बोलने देने की बात पर भी सोचें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : अध्यक्ष महोदय, इसकी इनक्वायरी करा दें, इससे भी पता चल जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश धनखड़** : अध्यक्ष महोदय, ये नाम अभी बता दें, हम इनक्वायरी करा देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नाम देने के बाद ही तो इनक्वायरी हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)30

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधू:** अध्यक्ष महोदय, जिस समय चेयर पर उपाध्यक्ष महोदया उपस्थित थी, उस समय कुलदीप शर्मा जी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार प्रदेश में इल्लीगल माईनिंग करवा रही है । उन्होंने कहा कि मेरे पास इललीगल माईनिंग करने वालों के नाम हैं, जिनके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अलग से बताने की बात कही । उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इल्लीगल माईनिंग करने वालों के नाम हैं और वे सभी को जानते हैं तथा सदन में बैठे कुछ मंत्री भी इल्लीगल माईनिंग करवा रहे हैं । उनकी इन बातों पर सत्तापक्ष की तरफ से कोई भी नहीं बोला । इसका मतलब यह हुआ कि शर्मा जी सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वे सही हैं । मैंने ही खड़े होकर कहा कि शर्मा जी आप कह रहे हैं कि आपको सबके नाम पता है तो क्या वे आपके रिश्तेदार हैं । उसके बाद मैंने यह भी कहा कि यदि आपको इललीगल माईनिंग करने वालों के नाम मालूम हैं तो आप सदन में बतायें । शर्मा जी की बातों पर सत्तापक्ष के किसी भी साथी ने कुछ नहीं कहा इसका मतलब यही हुआ कि वे सही इल्जाम लगा रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) शर्मा जी सरकार पर आरोप लगाये जा रहे थे और सत्तापक्ष के साथियों को जैसे सांप सूंघ गया हो, चुप बैठे थे । (शोर एवं व्यवधान) इससे अच्छा तो सत्तापक्ष के साथी डूब मरें । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्लीज आप सभी बैठें । संधु साहब यदि शर्मा जी इललीगल माईनिंग करने वालों के नाम नहीं बता रहे तो उनके खिलाफ प्रीविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवर :** अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी को इल्लीगल माईनिंग करने वालों के नाम बताने चाहिंए । सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि खनन की चोरी उस समय ज्यादा होती है जब माईनिंग बंद होती है और सभी को यह भी मालूम है कि माईनिंग किस सरकार में बंद थी । जैसे ही माईनिंग चालू होती है उस समय खनन की चोरी कम हो जाती है । क्योंकि जिन ठेकेदारों को माईनिंग का ठेका मिलता है वे भी खनन की चोरी नहीं होने देते । यदि खनन की चोरी होगी तो ठेकेदारों को नुक्सान होता है ।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, जो ठेकेदार होते हैं वे ही खनन की चोरी करवाते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप यह समझायें कि ठेकेदार खनन की चोरी क्यों करवायेंगे ? ठेकेदारों को रॉयलटी मिलती है । वे खनन की चोरी नहीं करवाते । वे खनन की चोरी रोकने की कोशिश करते हैं । मैं यह नहीं कहता कि माईनिंग शुरू होने के बाद खनन की चोरी नहीं होती । चोरी तो तब भी होती है लेकिन जिस समय माईनिंग बंद होती है उस समय चोरी ज्यादा होती है और यह हम सभी को मालूम है कि माईनिंग किसकी सरकार में बंद थी ।

**श्री आनंद सिंह दांगी :** अध्यक्ष महोदय, जिस समय माईनिंग बंद थी उस समय रोड़ी–रेती के रेट कम थे और आज ज्यादा हैं । क्या माईनिंग खुलने के बाद रोड़ी–रेती के रेट में कुछ कमी आई है ?

**श्री अध्यक्ष :** दांगी साहब, माईनिंग खुलने के बाद रोड़ी और रेती के रेट आधे से भी ज्यादा कम हो गये हैं । (विघ्न)

**श्री मनीष कुमार ग्रोवर :** अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी ने आरोप लगाया है कि पलवल से लेकर यमुनानगर तक खनन मैं चोरी हो रही है और इनको इल्लीगल माईनिंग करने वालों के नाम भी मालूम है । इनको वे नाम सदन में बताने चाहिंए । सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, इल्लीगल माईनिंग के कारण सरकार को राजस्व का बहुत चूना लग रहा है । मैं यह बात बिलकुल सही कह रही हूं कि आज प्रदेश में इल्लीगल माईनिंग बहुत ज्यादा हो रही है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, यह जो इल्लीगल माईनिंग हो रही है, सरकार की मर्जी से हो रही है ।

**श्री अध्यक्ष :** शर्मा जी, आपने नाम जानने की बात कही है । आप उनके नाम बतायें । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जयवीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 15–20 ट्रक इल्लीगल माईनिंग करते हुए पकड़ गए हैं । उनसे पता लगा लिया जाये कि इल्लीगल माईनिंग कौन कर रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथी क्यों इल्लीगल माईनिंग करने वालों का साथ दे रहे हैं ? कुलदीप जी ने कहा है कि इनको नाम मालूम है लेकिन ये सदन में नहीं बता रहे । (शोर एवं व्यवधान) इनको इल्लीगल माईनिंग करने वालों का नाम बताना चाहिए । नाम न बताने वाली बात इनके गले में क्यों अटक गई ।

**श्री नायब सैनी :** अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के दस सालों के दौरान बहुत ज्यादा इल्लीगल माईनिंग हुई है । हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माईनिंग के टैण्डर ई–टैण्डरिंग के जरिये पारदर्शिता लाकर अलॉट किए हैं । जिस भी पार्टी को माईनिंग के टैण्डर दिए गये हैं उसमें माईनिंग लीज एरिया के अंदर खसरा नम्बर दिये हुए हैं । अब प्रदेश में ठीक तरह से माईनिंग हो रही है और सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो रही है । जबकि कांग्रेस सरकार के दस साल के शासन के दौरान इल्लीगल माईनिंग होती रही और सरकार को राजस्व का भी चूना लगा । उस समय बड़े–बड़े भू माफिया भी खड़े हो गये थे । आज हमारी सरकार ने उन भू माफियों के खिलाफ कार्यवाही भी की है ।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, कृपया आप सभी शांति से बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी ने यहां पर एक विषय उठाया है जिसके लिए उनको कहा जा रहा है कि वे जिस व्यक्ति से उस

सारे मामले को जोड़ रहे हैं उसका नाम यहां पर बतायें। नायब सैनी जी भी ऐसी ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार के समय में भी कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की सरपरस्ती में इस प्रकार के कुछ काम हुए हैं लेकिन आप उनसे तो सम्बंधित व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा जी, कुलदीप शर्मा जी ने तो यह कहा था कि उन्हें उन व्यक्तियों के नामों की भी जानकारी है लेकिन नायब सैनी जी ने यह नहीं कहा कि उन्हें नामों की जानकारी है। जब नायब सैनी जी ने यह कहा ही नहीं कि उन्हें नामों की जानकारी है तो फिर उनके द्वारा किसी का नाम बताये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रम एवं रोजगार मंत्री (श्री नायब सैनी)** : माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात को लेकर कांग्रेस के माननीय सदस्यगण शोर मचाकर हाउस की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यह इनकी हाउस की कार्यवाही को बाधित करने की सोची–समझी साजिश है और ये पहले से जो इनके खिलाफ यहां पर इनकी गलती से विवाद पैदा हुआ है उस मामले को डॉईवर्ट करने की कोशिश मात्र है।

**श्री अध्यक्ष** : भूपेन्द्र सिंह जी, आप मेरी बात सुने। आपकी सरकार के समय में इतने लम्बे समय तक हरियाणा में माईनिंग बंद रही लेकिन डिवैल्पमैंट के काम उसी प्रकार से चलते रहे। इसलिए यह बड़ी स्पष्ट सी बात है कि इल्लीगल माईनिंग के कारण ही ये डिवैल्पमैंट के काम हुए। नायब सैन जी ने जो बात कही है उसका यही आशय था। (शोर एवं व्यवधान) इस समय में माईनिंग की ऑक्शन हो रही है और माईनिंग सही तरीके से चालू है। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कृपया आप सभी शांति से बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आप शांति से बैठेंगे तभी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पायेगी। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप इस विषय पर ऐसे ही अनावश्यक चर्चा को लम्बा खीचेंगे तो फिर इस मामले का कोई हल निकलने वाला नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए में आपसे बार–बार यही कह रहा हूं कि आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। आप बोलते समय सदन की गरिमा और महिमा का भी ध्यान रखें। अगर सभी माननीय सदस्य सहयोग करेंगे तभी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पायेगी और बिना वजह का विवाद भी खड़ा नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया करके बैठ जायें और मैंने जो श्री

बलवान जी को बजट भाषण पर चर्चा के लिए समय दिया है उनको बजट भाषण पर अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री नसीम अहमद :** स्पीकर सर, सदन के अंदर यह बात उठाई गई है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान 10 साल तक पूरे हरियाणा प्रदेश को सभी प्रकार से लूटने का काम किया और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी प्रकार से प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है, इसमें इन दोनों की ही मिलीभगत है। मैं इन्से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा होने के बावजूद फिर ये नूरा–कुश्ती क्यों कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नसीम जी, आप कृपया करके बैठ जायें और श्री बलवान सिंह जी को बोलने दें । वे आपकी पार्टी के ही माननीय सदस्य हैं इसलिए आपको उनको बोलने देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** स्पीकर सर, हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री बलवान सिंह जी को आपने बजट भाषण पर बोलने के लिए समय दिया है। इसलिए आप कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों को बिठायें और उनको अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ललित नागर :** स्पीकर सर, मेरे हल्के के बॉर्डर के साथ लगभग 20 किलोमीटर यमुना लगती है। वहां पर एक मंत्री के रिश्तेदार द्वारा सारी–सारी रात अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** स्पीकर सर, ललित नागर जी को उस मंत्री और उसके रिश्तेदार का नाम भी बताना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** ललित जी, आप सम्बंधित मंत्री और उसके रिश्तेदार का नाम बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ललित नागर :** स्पीकर सर, वह मामा नाम का आदमी है जो वहां पर अवैध खनन का काम करता है और अन–अथोराईज्ड कालोनियां काटता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** ललित जी, आप सम्बंधित मंत्री का नाम भी बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ललित जी ने रिश्तेदार का नाम बता दिया है इसलिए यह जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है कि वह मंत्री के नाम का पता स्वयं लगा ले कि जो मामा नाम का आदमी है वह कौन से मंत्री का रिश्तेदार है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ललित जी, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप सम्बंधित मंत्री का नाम भी बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ललित नागर** : स्पीकर सर, अगर आप बार–बार कह रहे हैं तो मैं उसका नाम बता देता हूं। जिस मामा नाम के आदमी का मैंने यहां पर यमुना में हो रहे अवैध के सम्बन्ध में जिक्र किया है वह केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुज्जर का रिश्तेदार है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने सरकार पर अवैध खनन करवाने का आरोप लगाया और सरकार ने उस आरोप को मान लिया है और यदि नहीं माना है तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है यह बताया जाये ।

**शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला को बताना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में प्रिविलेज मोशन लेकर आ रही है ।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार उस सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आ रही है। जब तक प्रिविलेज मोशन आये तब तक श्री बलवान सिंह जी बोल लें ।

## वर्ष 2017–18 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया (फतेहाबाद)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की योजनाएं दर्शाई जाती हैं और बजट में उनकी मदों में राशि का प्रावधान किया जाता है । मैंने बजट भाषण को सुन कर और पढ़ कर देखा है कि जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शब्दों का मायाजाल बुना गया था उसी प्रकार बजट भाषण में भी शब्दों के मायाजाल से इस महान सदन के साथ–साथ हरियाणा प्रदेश की जनता–जनार्दन को गुमराह करने का असफल प्रयास किया गया है । अध्यक्ष

महोदय, आज हरियाणा प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन बजट में महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । वर्ष 2013 में जब तूअर की दाल के रेट 85 रुपये प्रति किलोग्राम थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्धनग्न हो कर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे और आज उसी तूअर की दाल के भाव 150–200 रुपये प्रति किलो हो गये हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हैं । इसी तरह से जब कच्चे तेल के भाव 150 डॉलर प्रति बैरल थे तो पैट्रोल का रेट 70–75 रुपये प्रति लीटर था उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी पर प्रदर्शन करते थे । आज जब कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल हैं तो भी पैट्रोल के रेट 70 रुपये प्रति लीटर हैं । इसी तरह जब बेसन 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली थाली बजा कर प्रदर्शन करते थे और आज वही बेसन 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है तथा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मौन धारण कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो पहले सर्विस टैक्स का विरोध करती रही लेकिन जब सत्ता में आई तो इन्होंने अढ़ाई प्रतिशत सर्विस टैक्स बढ़ाने का काम किया । इसी प्रकार से अब मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । कर्मचारियों के लिए हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल के लिए कैशलैस फैसिलिटी प्रदान करने बारे सरकार विचार करेगी । यह इतनी बड़ी बात नहीं है, सरकार इसको कर सकती है । आज किसी भी बीमारी का ईलाज करवाने के लिए प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे हैं वहां पर जाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे वहां पर ईलाज करवा सके । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिये जायें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों से वायदा किया था । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले दिनों ई–ट्रेडिंग का बहुत शोर मचा हुआ था । मैं इस ई–ट्रेडिंग के हक में बिल्कुल नहीं हूं क्योंकि इससे किसानों का तो पता नहीं कि भला होगा या नहीं होगा लेकिन आढ़ती का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो जायेगा । आढ़ती और किसान दोनों को इससे नुकसान होगा । हम सभी जानते हैं कि किसान और आढ़ती का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है । अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूं तो आढ़ती तो किसान का ए.टी.एम. होता है । जब रात को 12 बजे किसी किसान का बेटा बीमार हो जाता है तो उसी समय वह आढ़ती को फोन

मिलाता है और कहता है कि मैं शहर आ रहा हूं और मेरा बेटा बीमार है तो उसी समय आढ़ती अपने मुनीम को 10 हजार रुपये देकर अस्पताल में भेज देता है । अगर सरकार ई–ट्रेडिंग की व्यवस्था करेगी तो किसान के साथ–साथ आढ़ती का भी फायदा होने वाला नहीं है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ई–ट्रेडिंग को कतई तौर पर लागू न किया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे भाजपा के साथी पर्यावरण के बारे में बहुत बड़ी–बड़ी बात करते हैं लेकिन बजट में पर्यावरण का कहीं कोई जिक्र नहीं है । हमारी भारत सरकार बहन अमृता देवी के नाम से पर्यावरण पुरस्कार देती है । आज से 550 वर्ष पहले बहन अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने पर्यावरण के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी जो कि बिश्नोई समाज से संबंध रखती थी । मेरे फतेहाबाद जिले में बिश्नोई समाज बहुतायत में रहता है अगर हम इन लोगों के समारक बनायेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि किस–किस ने पर्यावरण का बचाव किया। इसलिए बहन अमृता देवी समारक स्थल मेरे फतेहाबाद जिले में बनाया जाये ताकि पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को प्रेरणा मिले । इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के लिए पिछले साल के बजट के मुकाबले इस बार बजट कम किया गया है । आज प्रदेश में कैंसर की बीमारी एक बहुत भयंकर रूप धारण करने जा रही है । पिछले दिनों पंजाब प्रदेश कैंसर के मामले में नं0–1 पर था लेकिन अब हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं है । अब हर गांव के अन्दर 5–6 मरीज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त मिलते हैं । इसलिये आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह जांच करवाए कि कैंसर की बीमारी कैसे फैलती है ? पंजाब प्रदेश में जब जांच करवाई गई तो उन्होंने पाया कि पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिक होना और कीट नाशक दवाईयों का हद से ज्यादा प्रयोग होना इसका एक कारण था । अगर हमारे हरियाणा में भी यही कोई एक कारण बनता है तो जन स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए और जो लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं उनको बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि अध्यक्ष जी, कैंसर या बड़ी बीमारी का ईलाज गरीब ही नहीं अगर कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी कराता है तो उसके भी बर्तन भांडे बिकने के कगार पर पहुंच जाते हैं । इसी तरह से सरकार किसानों को गुमराह करने के लिये बड़ी–बड़ी बातें करती है । लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो सरकार खाली जेब दिखाने का काम करती है । जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो ऊंट रेहड़े और बैल गाड़ियों पर स्वामी नाथन रिपोर्ट के लिये प्रदर्शन

करते हैं, अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन करते हैं । जब इनकी अपनी सरकार आती है तो स्वामी नाथन का जिक्र करना तो दूर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाए लाभकारी मुल्य भी देना पसंद नहीं करते । अध्यक्ष जी, जब तक हम किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तब तक किसान नहीं बच सकता । इस बार तो सरकार धान और जीरी का समर्थन मूल्य भी नहीं दे पाई है। सिंचाई के मामले में वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम हर खेत को पानी देंगे । लेकिन अब तक इसकी कोई योजना नहीं है तो इतना पानी कहां से आएगा । सरकार केवल गुमराह करने के लिये कहती है कि हम एस.वाई.एल. के लिये 100 करोड़ रूपये देंगे । जब तक एस.वाई. एल. नहर नहीं बनती तब तक सरकार को किसानों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए । इसके लिये सरकार का धर्म बनता है, कर्म बनता है, फर्ज बनता है कि सरकार किसान के खेत को पानी दे ताकि किसान अच्छे से गुजर बसर कर सके । अध्यक्ष जी, इस तरह से पूरे प्रदेश में दस हजार से ज्यादा पक्के खाल हैं । सर्वे के मुताबिक सात हजार खाल कंडम स्थिति में हैं, उनको रिमॉडलिंग की जरूरत है । सरकार कह रही है कि हम हर साल 400 खाल पक्के करेंगे । इससे तो इनको पक्के खाल रिमॉडलिंग करते हुए 20 साल लग जाएंगे । इसलिये सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक साल के अन्दर सभी खाल रिमॉडलिंग हो जाएं । जहां तक बिजली की बात है, बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी होती है । बिजली के क्षेत्र में इस बार बजट पिछले बजट की बजाए कम दिया गया है । पिछले दिनों जब बजट पस्तुत किया गया था तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट कम था । लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी पीड़ा व्यक्त की थी । जिससे इस बजट में उनको तो खुश कर दिया गया । लेकिन जितना होना चाहिए था उतना शिक्षा में भी नहीं दिया गया है। इसी तरह से बिजली के मामले में सरकार ने ढ़ाणियों में बिजली देने का वायदा किया था कि प्रत्येक ढ़ाणी के प्रत्येक घर को हम बिजली देंगे । लेकिन सरकार अब लोगों को गुमराह करने के लिये कह रही है कि हम ढ़ाणियों में पैट ट्रांसफार्मर देंगे । अध्यक्ष जी, पैट ट्रांसफार्मर से यह समस्या हल होनी वाली नहीं है । इसलिये सरकार को एकमुस्त आदेश जारी करने चाहिएं कि प्रत्येक ढ़ाणी में चाहे वह कितनी भी दूरी पर रहता हो, जब तक एक–एक ढ़ाणी तक लाईट नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा विकास नहीं होगा । लेकिन सरकार कहती है कि 100 लोगों का एक समूह एक जगह रहना चाहिए । जब 100 लोग अंधेरे में बैठेंगे तब जाकर सरकार की नींद

खुलेगी । इसी तरह परिवहन की बात करें तो आज परिवहन व्यवस्था की हालत बहुत दयनीय है ।

**परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार):** अध्यक्ष महोदय, जो मेरे साथी बलवान सिंह ने ढ़ाणी के लिए 100 मैम्बर का जिक्र किया है । मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जिस ढ़ाणी में 11 मैंबर हैं हमने उसको एक यूनिट माना है । 11 या 11 से अधिक कितने ही हों उसको एक ढ़ाणी माना है ।

**श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया:** अध्यक्ष महोदय, हमारा सरकार से निवेदन है कि वह एक–एक व्यक्ति को लाईट दे, एक–एक ढ़ाणी को लाईट दे । यह सरकार का धर्म बनता है, कर्म बनता है और फर्ज बनता है । इसका मतलब जब तक 11 लोग अंधेरे में नहीं बैठेंगे तब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी । क्या यह इनका सरकार चलाने का तरीका है । इनको चाहिए कि सबको पानी दें, लाईट दें, उनको शिक्षा दें, स्वास्थ्य सुविधा दें । यह सुविधा देना सरकार का काम है । 11 आदमियों को कोई सुविधा देंगे या 100 आदमियों को देंगे, यह तो गुमराह करने वाली बात है । इसी तरह बजट के अन्दर परिवहन के क्षेत्र में भी कमी की गई है । परिवहन मंत्री जी, इस बार आपके विभाग का बजट कम किया गया है । आप भी कहीं न कहीं मीडिया में जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त करें । क्योंकि शर्मा जी की तो सूत बैठ गई कि उनको शायद अबकी बार बजट ज्यादा मिल गया है। इसी तरीके आपको भी शायद मिल जाए । इसलिये आप भी कहीं न कहीं पीड़ा व्यक्त करें क्योंकि परिवहन विभाग महत्वपूर्ण विभाग है । आपके विभाग में स्टाफ की कमी है, बसों की कमी है जिस कारण लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कृष्ण लाल पंवार :** अध्यक्ष महोदय, जो परिवहन विभाग की बात आई है उसको मैं क्लीयर कर देता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी, वह तो आप क्लीयर कर ही दोगे ।

**श्री कृष्ण लाल पंवार :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को क्लीयर कर देता हूं क्योंकि कई मैंबरों ने कहा है । स्पीकर सर, परिवहन विभाग में 4200 बसों का बेड़ा है और हमारे बजट के अन्दर इन बसों की संख्या बढ़ाकर 5 हजार करने का फैसला किया गया है । हमने वायदा किया है कि हम 31 मार्च तक इसमें 600 बसें और डालेंगे । हम 300 लीलैंड बसों के ऑर्डर दे चुके हैं । जिनकी चेसी आनी शुरू हो गई हैं

और इन 300 बसों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एप्रूअल भी हो गई है । अब हाई पावर परचेज कमेटी में उसकी एप्रूवल लेकर 300 बसें भी ले ली जाएंगी ।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है । बलवान जी, आप वाईंडअप कीजिये । आपके केवल नौ मिनट रह गये हैं ।

**श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया:** अध्यक्ष महोदय, सरकार हर क्षेत्र में बजट तो घटाती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे 10–10 मिनट बोलने के लिये निवेदन करते हैं और जो सीनियर आदमी हैं वह एक–एक घण्टा खराब कर देते हैं ।

**श्री कृष्ण लाल पंवार :** अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने बजट के बारे में कहा है । मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि परिवहन के लिए वर्ष 2016–17 में 2291.30 का प्रावधान था और वर्ष 2017–18 में 2459.70 का प्रावधान है । इस प्रकार इसमें 7.35 की वृद्धि हुई है । अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती के नाम पर सरकार ने करोड़ों रूपये बहाने का काम किया। लेकिन एक आदमी श्री रॉकी मित्तल ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए कुछ अधिकारियों पर इल्जाम लगाये तो सरकार ने जांच करने की बजाय श्री रॉकी मित्तल को खुड्डे लाईन लगाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस मामले में जांच कराने से बचना कहीं न कही संदेह पैदा होता है कि स्वर्ण जयंती के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। करोड़ों रूपये गीता जयंती व स्वर्ण जयंती जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके, पानी की तरह बहाये जा रहे हैं। निःसंदेह इनकी जांच करानी चाहिए? जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को सरकार द्वारा इस तरह बेफिजूल में खर्च नहीं करना चाहिए। सरकार की तरफ से हर जगह पर गाय और गीता का जिक्र किया जा रहा है लेकिन जब गाय माता के लिए कुछ देने की बारी आती है तो सरकार की तरफ से खाली जेब दिखाने का काम किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गायों की डाईट के संबंध में 15 रूपये प्रति गाय का फैसला दिया तो उसके खिलाफ चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि यदि कोई स्टेट चाहे तो अपने स्तर पर गायो को यह डाईट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मद्देनज़र मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गांयों को 15 रूपये की बजाय 25 रूपये प्रति गाय डाईट पर गांय को दी जाये। यदि सरकार इस दिशा में काम करेगी तभी उसको सच्ची गौ–भक्ति माना जा सकता

है। केवल बोलने मात्र से ही कोई गौ–भक्त नहीं हो जाता? (इस समय विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई।) माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों फतेहाबाद गए थे। मैं सोच रहा था कि सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर चलने वाली सरकार द्वारा मुझे कार्यक्रम में आने के लिए बुलावा जरूर आयेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मांग पत्र दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट तक इंतजार करता रहा लेकिन मुझे कोई फोन या मैसेज नहीं आया। फिर मैंने एस.डी.एम. के माध्यम से मेरा मांग–पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाने का काम किया। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** बलवान जी, सरकार सबका साथ–सबका विकास करने वाली है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके हल्के को पैसे नहीं दिए? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः** अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात पुरी हो लेने दो उसके बाद इस के बारे में बताउंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट को पढ़कर देखा तो बिल्कुल निराशा ही हाथ लगी है। सरकार की तरफ से बजट में हर चीज के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रावधान तो करते हैं 150 करोड़ का क्योंकि यह इनकी आदत में शुमार हो गया है लेकिन देते 100 रूपये भी नहीं हैं। अगर सही मायने में सरकार विकास करवाना चाहती है तो विधायक निधि कोष बनाना चाहिए और उसके तहत प्रत्येक विधायक को 5–5 करोड़ रूपये देने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक–एक विधायक 5 करोड़ रूपये से 7 करोड़ रूपये के विकास अपने हल्के में करवाकर दिखा देगा, कार्य करवा सकता है, इसका कारण यह है कि प्रत्येक विधायक को हर गली व मोहल्ले का भरपूर झान होता है कि किस जगह पर पैसे लगेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः** अध्यक्ष महोदय, सरकार तो ऐसी योजनाएं बनाने में लगी हैं जिनको पूरा होने में 20 से 30 साल तक लग जायेंगे। इससे कैसे विकास होगा।(शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः** अध्यक्ष महोदय, यही तो सरकार की फिराखदिली है ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** कादियान जी, सरकार की फिराखदिली को छोड़ो, पूरे हाउस ने माना है कि मेरी फिराखदिली आपकी तरफ ही ज्यादा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. पवन सैनी (लाडवा) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जबकि हरियाणा अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है तो ऐसे शुभ अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने हरियाणा की जनता की खुशहाली व कल्याण के लिए जो यह बजट पेश किया है, उसके लिए मैं मैं अपनी ओर से तथा मेरे लाड़वा हल्के की देव तुल्य जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के समय जिस–जिस इलाके से मुख्यमंत्री बनता था, केवल उसी इलाके में ही विकास कार्य करवाये जाते थे। किसी ने सिरसा में विकास करवाया, किसी ने हिसार में विकास करवाया, किसी ने भिवानी में विकास करवाया तो किसी ने रोहतक व झज्जर में विकास करवाया और बाकी सारे हरियाणा के लोग आंखे गडाये देखते रहते थे कि कब उनके क्षेत्र का विकास होगा, कब मुख्यमंत्री जी उनके इलाके के लिए किसी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की कोई घोषणायें करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र के कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है। (शोर एवं व्यवधान)

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः** अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नया सदस्य सदन में अपनी बात रखता है और ऐसे नए सदस्य को बोलते हुए टोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही नया सदस्य जब हाउस में गलत बातें कहने लग  जाता है और इशारों ही इशारों में यह बात करता है कि किसी मुख्यमंत्री ने केवल अपने क्षेत्र का विकास करवाया है तो इस तरह की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। (शोर एवं व्यवधान) जब मैं मंत्री होता था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो उस पांच साल के कार्यकाल में उन्होंने 90 की 90 विधान सभा क्षेत्रों में पहुंचकर विकास कार्य करवाने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा के चुने हुए जो मौजिज लोग थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी डिमांड की थी, उसको पूरा करने का काम किया गया था। विकास कार्यों के लिए हर महीने चैक/ड्राफ्ट स्वयं उनके पास पहुंच जाया करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ पवन सैनीः** अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने क्षेत्र में विकास करवाया, यदि नहीं करवाया तो संधू साहब इस बात को नकार दें? (शोर एवं व्यवधान)

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो बात सच है उसको तो मानना ही चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** सैनी साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए।

**डॉ. पवन सैनी :** माननीय अध्यक्ष जी, विकास के बारे में सारे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है और इस बारे में संधू साहब भी बता देंगे कि इनके हल्के में कितना विकास हुआ था । इस बात को हरियाणा की अढ़ाई करोड़ की जनता भी जानती है । हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा प्रदेश को ऐसा मुख्य मंत्री मिला है जो हरियाणा के 90 के 90 हल्कों में गया और वहां पर विकास कार्यों की झड़ी लगाई है । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** संधू साहब, आपने अपनी बात रख ली है ।

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधू :** अध्यक्ष जी, इनेलो सरकार में मेरे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट और मार्केटिंग बोर्ड था । मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा जितनी सड़कें 5 साल में बनाई गई थी उतनी सड़कें पिछले 25 सालों में भी नहीं बनी हैं । हम 4 हजार 6 सौ किलोमीटर लंबी सड़कें बनाकर गए थे और हमने 2500 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की थी । जो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया इस सरकार ने अढ़ाई साल में उसके आसपास भी काम नहीं किया है । माननीय सदस्य को अपने इलाके की बात करनी चाहिए और किसी पर छीटाकंशी नहीं करनी चाहिए । अगर ये ऐसा करेंगे तो हम भी आराम से इनकी बात सुनते रहेंगे । (विघ्न)

**डॉ. पवन सैनी :** अध्यक्ष जी, मैं काम की बात बता रहा हूं । इनके समय में खुले दरबार लगते थे और माननीय सदस्य ने अपनी मर्जी से एक नलका भी लगवाया हो तो बता दें । उस समय मुख्य मंत्री जी स्वयं सारी ग्रांट बांटते थे । (विघ्न)

**श्री नसीम अहमद :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बात कर रहे हैं । उन्होंने जनता की अनेकों डिमांड्ज पूरी की थी । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** नसीम जी, संधू साहब इस विषय पर बोल चुके हैं ।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की सारी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री ही करते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना

चाहता हूं कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब 90 विधान सभा क्षेत्रों मे गये थे तो क्या तब किसी और ने घोषणाएं की थी ? प्रदेश का जो मुख्य मंत्री होता है विकास संबंधी घोषणाएं भी वही करता है । मेरे और माननीय सदस्य जैसे लोग तो मुख्य मंत्री से खड़े होकर मांगने वाले होते हैं । माननीय सदस्य को इसका ज्ञान होना चाहिए कि एक मुख्य मंत्री जब घोषणा करेगा तभी उसको प्रदेश में लागू किया जा सकेगा । इन्होंने खुद कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी 90 विधान सभा क्षेत्रों में गये हैं तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चौटाला साहब उन 90 विधान सभा क्षेत्रों में एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत पांच–पांच बार जाकर आये थे । उस समय जिस पंचायत ने जो मांग रखी वे उसको पूरी करके आये थे । (विघ्न)

**डॉ. पवन सैनी :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में ज्यादा आगे जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस बारे में सबको पता है । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** सैनी जी, आप अपने विषय पर बात कीजिए ।

**डॉ. पवन सैनी :** आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारी सरकार का कार्यकाल अढ़ाई साल का ही हुआ है । अब हमारी विकास दर 9 प्रतिशत है जोकि पिछली सरकार में 5.7 प्रतिशत थी । इस वित्त वर्ष में पहली बार एक लाख से भी ज्यादा यानि 1,02,329 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है । इसके साथ ही शहरों की तर्ज पर गांवों में भी विकास की गंगा बहाने के प्रयास किये जाएंगे । वहां पर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हरियाणा के महान नेता रहबर–ए–आजम स्वर्गीय चौधरी छोटूराम जी के नाम से 'दीनबंधू हरियाणा ग्राम योजना' चलाई है । इस योजना के अंतर्गत लगभग 1200 करोड़ रूपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव रखा है । शहरी क्षेत्रों में आधारभूत विकास संरचना का सृजन करने के लिए भी हरियाणा के महान नेता और पूर्व उप मुख्य मंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सैन जी के नाम से 'मंगल विकास नगर योजना' चलाई है । इस योजना के लिए भी एक हजार करोड़ रूपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नोटबंदी के माध्यम से 500 और 1000 रूपये के नोट करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है । इस निर्णय से भ्रष्टाचार और कालेधन पर अंकुश लगेगा । (विघ्न)

**श्रीमती शकुंतला खटक :** अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 1000 रूपये के बजाय 2000 रूपये के नोट से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है । (विघ्न)

17:00 बजे

**डॉ. पवन सैनीः** अध्यक्ष महोदय, सरकार के भीम एप के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए 5 प्रतिशत की छुट भी दी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2030 तक, 15 वर्षों में बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र को दोगुना करने और उत्पादन को तीन गुणा करने के लिए ''बागवानी विजन'' तैयार किया है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए भी सौभाग्य है कि मेरे लाडवा निर्वाचन क्षेत्र में ''उत्कृष्टता केन्द्र'' स्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है कि किसान खेती के साथ–साथ डेरी फार्मिंग का कार्य भी करें ताकि उनकी अतिरिक्त आय सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए देसी गायों की मिनी डेरी इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2017–18 के बजअ में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 3206.01 करोड़ रूपये का आबंटन किया है जोकि वर्ष 2016–17 के 2698.80 करोड़ रूपये से 18.79 प्रतिशत अधिक है। इसमें कृषि के लिए 1516.01 करोड़ रूपये, पशुपालन के लिए 746.88 करोड़ रूपये, बागवानी के लिए 396.93 करोड़ रूपये, वनों के लिए 457.62 करोड़ रूपये और मत्स्य पालन के लिए 88.57 करोड़ रूपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और जल संसाधन के बारे में आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में पानी पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है। ''हर खेत को पानी'' के विज़न को साकार करने की दिशा में, जे.एल.एन. पर सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पम्प घरों और नहरों की क्षमता को सुधारने के लिए 143 करोड़ रूपये की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिसम्बर, 2016 में पिहोवा में 13 जिलों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रदर्शन की 25 करोड़ रूपये की एक पायलट परियोजना का उद्घाटन करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 150 करोड़ रूपये की लागत से पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, पृथला डिस्ट्रीब्यूटरी, खनौरी माइनर, जाखौली डिस्ट्रीब्यूटरी, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी, नई उरलाना माइनर, जहांगीरपुर माइनर, पहाड़ीपुर माइनर, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, बसई डिस्ट्रीब्यूटरी आदि के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, हमारी सरकार ने नाबार्ड की वित्तीय सहायता से

वित्त वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 के दौरान 125 चैनलों और 400 जलमार्गों के पुनरोद्धार की योजना बनाई है। अध्यक्ष महोदय, सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा प्रदेश के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस विषय में ज्यादा चर्चा ना करते हुए जो मेरे मन में एक बात है अध्यक्ष महोदय, वह मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला मुझे नहीं पता कि किस कारण से सदन में उपस्थित नहीं हो रहे। लेकिन उन्होंने पंजाब में जाकर यह कहा था कि एक बूंद पानी पंजाब में से हरियाणा को नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सतलुज–यमुना लिंक नहर के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि इस नहर के निर्माण के लिए यदि 1 हजार करोड़ भी खर्च करने पड़ेंगे तो सरकार खर्च करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव में विकास के लिए ''स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना'' के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों के विकास के लिए जितनी भी राशि लगेगी वह राशि हमारी सरकार खर्च करेगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों के सहयोग से , राज्य ने वर्ष 2016–17 में 14 जिलों के लिए खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने नवम्बर, 2017 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। गांवों में आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्राम सचिवालय और अटल सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पिछली सरकार के समय में सरकारी अस्पतालों से लोगों का विश्वास उठ चुका था और जो लोग प्राईवेट अस्पतालों के अन्दर अपना ईलाज करवाते थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री श्री अनिल विज जी का धन्यवाद करता हूं कि आज हरियाणा की जनता का सरकारी अस्पतालों के प्रति विश्वास जागा है। हमारे कुरूक्षेत्र के एल.एन.जे.पी. अस्पताल में प्रतिदिन 2000 के करीब ओ.पी.डी. हैं और लाडवा के सामान्य अस्पताल में भी लगभग 500 ओ.पी.डी. है। हरियाणा सरकार के इस काम से आज लोगों का विश्वास जगा है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर जिले में मैडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया है, इसके

अतिरिक्त कल्पना चावला मैडिकल कालेज में इस सैशन से 100 सीटें एम.बी.बी.एस. की बढायी गयी हैं तथा तीन दूसरे चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.पी.पी. मोड़ पर एम.आर.आई. सी.टी. स्कैन मशीनें स्थापित की गयी हैं और डिस्टिक्ट हैडक्वार्टर पर अस्पतालों में डायलेसिस की यूनिट लगायी गयी है। अध्यक्ष महोदय जी आप वाइंड अप करने के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं कई महत्वपूर्ण बातों से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। अभी हमारे माननीय सदस्य कुलदीप जी बता रहे थे कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है और एनरोलमैंट कम हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार के ढाई साल के कार्याकाल के अन्दर सभी सरकारी स्कूलों में एनरोलमैंट बढा है। मेरे क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में नयें बच्चों का दाखिला हुआ है और एनरोलमैंट बढा है उनका सरकारी स्कूलों में विश्वास बढा है। क्योंकि पिछली सरकार ने स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया। 8 वीं तक के बच्चों को बिना पढे ही पास कर दिया जाता था। पिछली सरकार में यह प्रावधान था कि अगर कोई बच्चा 1 मार्च को भी दाखिला लेता है तो उसको 31 मार्च को पास का सर्टिफिकेट दिया जाता था तो उन्होंने बताया कि उन बच्चों को एक सप्ताह पहले पेपर दे देते थे। मैंने फिर कहा अगर आप एक सप्ताह पहले पेपर दे देते हो तो फिर तो बच्चे 100 में से 100 अंक प्राप्त करते होंगे। फिर अध्यापक ने बताया कि बच्चे फिर भी फेल हो जाते हैं। मैंने पूछा कि फिर तो आप क्या करते थे तो उन्होंने बताया कि बच्चों को किताब दे देते थे। मैंने कहा फिर तो बच्चे सारे सवाल एटैम्पट करते होंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे बड़ा दुःख हुआ उन्होंने बताया कि बच्चे फिर भी प्वाईंट पर पास होते थे क्योंकि कई बार पेज नं0 10 का सवाल पेज नं0 40 पर आ जाता था तो उस पर पब्लिशर लिख देता था देखें पेज नं0 10 पर। वे बच्चे पेपर में भी लिख देते थे कि देखें पेज नं 10 पर। पिछली सरकार के समय पर विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में अगर कोई नया इंस्टीटयूट/यूनिवर्सिटी खोली जाती थी उनके नाम अपने बुजुर्गों के नाम पर रख दिए जाते थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वकर्मा के नाम से विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय खोला है और महर्षि वाल्मिकी के नाम से भी विश्वविद्यालय का नाम रखा है। बिजली के मामले में पिछली सरकारें कहती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। हमारे प्रदेश के अन्दर पंचकुला ऐसा जिला बना है जहां 24 घंटे बिजली

उपलब्ध रहती है। हरियाणा के अन्दर लगभग 30 फीडर्ज ऐसे हैं। जहां पर 24 घंटे बिजली रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछ समस्याओं को जरूर रखना चाहता हूं। (विघ्न) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लाडवा शहर राजा अजीत सिंह की नगरी है। मैं चाहता हूं कि राजा अजीत सिंह के नाम से कोई समारक वहां बनाया जाए। हमारे यहां पर एक हिन्दु हाई स्कूल है वह इसके लिए जमीन देने के लिए भी तैयार है। हम बेटी बचाओं बेटी पढाओं की बात करते हैं तो हमारी बेटियों के लिए कोई फार्मेसी का नर्सिंग कालेज जरूर खोला जाए यह भी आपके माध्यम से मांग करता हूं। मेरे हल्के के अन्दर कोई भी लड़कियों का कालेज नहीं है मेरे हल्के का एक रामशरण गांव है वह कालेज के लिए जमीन देने के तैयार है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर कोई गवर्नमैंट कालेज खोला जाये ताकि वहां पर हमारी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इस हेतु जो 50 एकड़ या 60 एकड़ जितनी भी जमीन चाहिए, वे देने के लिए तैयार है। वहां पर कोई गवर्नमैंट गर्ल्ज कॉलेज खोला जाए, इसके लिए भी मैं मांग करता हूं। कुरूक्षेत्र से जब हल्के के अंदर जाते हैं तो पिपली एक बहुत बड़ा गांव है वहां घरों के ऊपर से हाई टेंशन तारें जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको हटाने के लिए जो 6 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी, उसके काम में थोड़ा जल्दी की जाए, क्योंकि छतों के ऊपर से जो हाई टेंशन की तारें जा रही हैं जिसके कारण लगभग 20–25 नौजवान बच्चों ने अपनी जानें गंवायी हैं। मेरे हल्के में बबैन जो कस्बा है वहां पर कोई सरकारी रैस्ट हाउस नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं और हमारे पी.डब्ल्यू.डी मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बबैन के अंदर पी.डब्ल्यू.डी रेस्ट हाउस बनाने की मेरी मांग को पूरा किया जाए। पिपली बस स्टैंड के बारे में सुबह चर्चा हुई थी और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि पिपली लाडवा रोड पर एक नया अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड बनायेंगे जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। पिपली के अंदर एच.वी.पी.एन का ऑपरेशन सब–डिवीजन है। उसका इलाका काफी बड़ा है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मथाना भी हमारा काफी बड़ा गांव है। अतः वहां पर भी ऑपरेशन सब–डिवीजन खोला जाए, क्योंकि आस पास के इलाकों के हमारे कंज्यूमर्ज तंग होते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी लाडवा में बाईपास की काफी पुराने समय से डिमांड है। उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाईपास बनवाया जाए। लाडवा से वाया इंद्री

करनाल जाते हैं तो उस रोड पर ट्रैफिक बहुत होता है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यमुना नगर से जो हैवी ट्रैफिक आता है वह या तो वाया कुरूक्षेत्र या फिर वाया इंद्री जाता है जिस कारण उस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि लाडवा से वाया इंद्री करनाल रोड को 4 लेनिंग बनाने का काम करवाया जाए। लाडवा में जो गवर्नमैंट वेटरनरी हॉस्पिटल है, उसकी हालत बड़ी जर्जर है, उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। मेरे यहां लगभग 32 वर्ष पूर्व सब तहसील बनी थी। किसी भी सरकार ने उसे अपग्रेड नहीं किया, उसको अपग्रेड करने की जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने रैली के अंदर घोषणा की थी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शाहबाद पिहोवा और थानेसर तीनों जगह सब डिवीजन है लेकिन लाडवा जो कुरूक्षेत्र जिले का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है वहां सब डिवीजन नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लाडवा को भी सब–डिवीजन बनाने का दर्जा दिया जाए। मेरे हल्के के अंदर 326 किलोमीटर पी. डब्ल्यू.डी की सड़कें हैं, जिसमें से लगभग 44 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 68 सडकें पहले मंजूर की गई थी और उनका काम लगभग निपट चुका है। 54 करोड़ रुपये की और सड़कें भी मंजूर की गई हैं। उन पर भी लगभग काम शुरू हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बबैन के अंदर पी.एच.सी या सी.एच.सी की घोषणा की गई थी, उसे भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का काम किया जाए। सिविल हॉस्पिटल में आउट सोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती होती है लेकिन पी.एच. सी और सी.एच.सी में नहीं होती है। फोर्थ क्लास कर्मचारियों के बगैर हमारा स्टाफ पूरे हरियाणा के अंदर तंग है। इसलिए मै निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पी. एच.सीज और सी.एच.सीज में भी आउट सोर्सिंग के माध्यम से भी इम्प्लॉयमेंट करने का काम किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सी.एच.सी में एक्स–रे मशीन तो है, लेकिन उसे चलाने वाला रेडियाग्राफर नहीं है जो कि एक बड़ी गंभीर समस्या है। मेरी मांग है कि जो कर्मचारी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेडियाग्रोफर का काम करते हैं, उनके साथ कोई पैनल पर एडजस्टमेंट किया जाए, क्योंकि छोटी सी तकलीफ में भी पेशेंट को पी.एच.सी से सी.एच.सी में रेफर कर देते है, जिससे उस पेशेंट का सारा समय उसी में लग जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र में आई–सृष्टि बनने का प्रस्ताव है। हमारा जो बोहली गांव है, वहां के सरपंच ने 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जी.टी रोड पर आई–सृष्टि बनायें। जो

राक्षी नदी और सरस्वती नदी का पुनरुद्धार हुआ, जिसमें लगभग 6 या 6.5 करोड़ रुपए से सरस्वती नदी का और लगभग 3 करोड़ रुपये से राक्षी नदी का जीर्णोद्धार हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दादूपुर नलवी नहर के बेड की सफाई करके उसमें भी पानी चालू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भारी बरसात के कारण गेहूं की फसल खराब हो गई थी उसकी दोबारा से गिरदावरी करवाई जाये । जिस समय बरसात हुई थी उस समय गेहूं की फसल हरी थी और नुक्सान की जानकारी नहीं लगी । सूखने के बाद किसानों को मालूम हुआ कि फसल में बरसात के कारण काफी नुक्सान हुआ है । डी.डी.एज. ने उस फसल की गिरदावरी करने से मना कर दिया है । मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस फसल की दोबारा से गिरदावरी करवाकर मुआवजा देकर किसानों को हुए नुक्सान का लाभ दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं और एक कविता आपकी इजाजत से सदन में सुनाना चाहता हूं कि–

मैं अपने हरियाणा नै इसा देखणा चाहूं रै,
नफरत हो जा खत्म चौगरदें प्यार देखणा चाहूं रै,
अपणे हरियाणा नै इसा देखण चाहूं रै ।
अहंकार का हरियाणा में नाम नहीं हो,
बेइमानी का किते कोई काम नहीं हो,
सब के विचार शुद्ध हो जाणे चाहिंए,
पाप की कमाई के ये दाम नहीं हों ।
आच्छी–आच्छी बात सोचें सब मन में,
कोई भी नहीं रहणा चाहिए गंदे पण में,
जात पात का ना कोई भेद भाव हो,
जागृति आ जावे सब जन–जन में ।
प्रेम प्यार ते मनणे सब त्योहार चाहिंए,
अन्नधन से भरे घर बार चाहिंए,
सब धोरे काम धंधा होणा चाहिए,
कोई भी नहीं बेरोजगार चाहिए ।
कदै बी किसी की तकरार नहीं हो,
झूठ और मतलब वाला प्यार नहीं हो,
समाज न बिगड़ कै धर दें सै जो,
गंदा गाणे आले कलाकार नहीं हो ।
बाढ़ और सुखा कितै आणे ना चाहिंए,
बेईमानी के कितै बी ए थाणे ना चाहिंए,
ईमानदारी तै करे जब काम अपणा,
भ्रष्टाचारी माणस कितै पाणें ना चाहिंए ।
धन्यवाद । जय भारत, जय हरियाणा ।

**श्रीमती प्रेम लता (उचाना कंला)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं । अध्यक्ष महोदय, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं । बजट पर जब भी कोई विपक्ष का साथी बोलने के लिए खड़ा हुआ है उसने उसका विरोध ही किया है और कमियां ही निकाली हैं। इसमें चाहे विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला जी हों, चाहे रघुवीर सिंह कादियान जी हों । उन्होंने जब से हरियाणा बना तब तक के आंकड़े बताये हैं । इस तरह की नकारात्मक बातें प्रदेश के लोगों में जायेंगी तो अच्छी बात नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ''हम दो, हमारे दो'' का नारा दिया गया था जो कि बहुत अच्छा नारा था लेकिन लालू प्रसाद यादव उस समय कांग्रेस के विरोधी थे । उन्होंने उस नारे का विरोध करते हुए अपने 9 बच्चे पैदा किये । (हंसी) इसी तरह से हमारा बजट भी बहुत अच्छा है लेकिन विपक्ष के साथियों ने केवल इसका विरोध ही किया है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017–18 के बजट का मैं स्वागत करती हूं और यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों के लिए बहुत ही विकासशील है । हमारी विपक्ष की सदस्या बहन किरण चौधरी जी ने बजट पर टिप्पणी की थी कि यह बजट शब्दों का मायाजाल है । इसमें कोई सकारात्मक या विकास से जुड़ी हुई बात नहीं है। यह तो घाटे का बजट है। सरकार का कर्जा बढ़ गया है। मैं यह कहना चाहूंगी कि विपक्षी पार्टियों के माननीय सदस्यों को शायद इस बात की जानकारी नही है कि घाटे का बजट इस बात को दर्शाता है कि आधारभूत ढ़ांचा तैयार करने के लिए और लोगों को मूलभूत सुविधायें देने के लिए अर्थात अगर इस प्रकार के कार्यो को प्राथमिकता दी जाये तो उस बजट को प्रगतिशील बजट कहा जाता है। यह सभी जानते हैं कि कोई बड़ा काम करने के लिए बहुधा लोन का सहारा लिया जाता है। चाहे वह लोन बिजनैसमैन द्वारा लिया जाये या फिर सरकार द्वारा लिया जाये। किसी कार्य हेतु लिये गये लोन का सतत और धीरे–धीरे भुगतान भी किया जाता है। यह आम जनता का बजट है। यह मैं नहीं इस बात को हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं। इस प्रकार से मेरी नजर में यह घाटे का बजट बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस बजट से यह अनुमान नहीं होता कि देश का जो जी.डी.पी. अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी दर 7.5 प्रतिशत नापी गई है जो कि हमारे देश को दुनिया की प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में शुमार करती है। हमारे हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर स्थिति में है जिसकी वृद्धि दर को माननीय वित्त मंत्री जी ने

7.2 अंकित किया है। हरियाणा प्रदेश का बजट पहली बार एक लाख करोड़ से भी ऊपर रखा गया है जो कि पंजाब से ज्यादा है। जब पंजाब से अलग होकर सन् 1966 में हरियाणा बना था उस समय यह कहा गया था कि हरियाणा अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पायेगा। यह प्रश्न भी उठाया गया था कि अपने आवश्यक खर्चों की पूर्ति के साथ–साथ क्या हरियाणा प्रदेश अपने कर्मचारियों को भी तनख्वाह दे पायेगा? हमारे हरियाणा प्रदेश ने इस प्रकार के सभी सवालों का जवाब प्रैक्टीकली दिया है। वर्ष 1966 में हरियाणा का कुल बजट केवल मात्र 250 करोड़ रूपये था लेकिन आज के हरियाणा ने विकास के लगभग सभी मामलों में पंजाब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारे हरियाणा का प्रत्येक किसान, व्यापारी और मजदूर बहुत ज्यादा मेहनती है। हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों ने भी हरियाणा की प्रगति में विशेष भूमिका निभाई है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारे नौजवान नशे की लत से बचे हुए हैं। यह बात भी सच हो सकती है कि हमारे प्रदेश के पंजाब से लगते नरवाना जैसे कुछ इलाकों में नशे की समस्या हो सकती है लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार नशे की प्रवृति पर काबू पाने में सफल सिद्ध हुई है और जहां–जहां पर थोड़ी–बहुत समस्या है वह भी आने वाले समय में समाप्त हो जायेगी। हमारे हरियाणावासी नशे से अभी तक बचे हुए हैं इसीलिए मेहनत हमारा स्वभाव बन गया है और हम सभी हरियाणा की चहुंमुखी प्रगति के लिए जी–तोड मेहनत कर रहे हैं। इसी प्रकार से जी.एस.डी.पी. अर्थात जिसको ग्रॉस स्टेट डोमैस्टिक प्रोड्क्ट कहते हैं अगर वर्ष 2011–12 की प्राईस को बेस माना जाये तो वर्ष 2016–17 में हमारी जी.एस.डी.पी. 8.7 प्रतिशत थी । इसी प्रकार से हमें उम्मीद है कि वर्ष 2017–18 में यह 9 प्रतिशत तक पहुंचेगी। यह बजट दर्शाता है कि हमारी ग्रोथ दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा है। इस बार के बजट में प्लान और नॉन–प्लॉन की क्लॉसीफिकेशन को समाप्त कर दिया गया है। पहले चार भाग होते थे जिनको अब दो कर दिया गया है। नॉन–प्लॉन में सैलरी, टी.ए. डी.ए. और पैंशन इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार से प्लान बजट में नहर की खुदाई, कॉलेज, सड़कें तथा भवन निर्माण इत्यादि मदें आती हैं। अब दो रेवेन्यू और कैपीटल हैड बना दिये गये हैं। इसको सिम्पलीफाई भी कर दिया गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाये वह कम होगी। इसके साथ ही साथ मैं यह बात भी कहना चाहूंगी कि रेवेन्यू एक्सपैंडीचर 60–65 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो 40 प्रतिशत

की ग्रोथ है उसमें सारे हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। जिसके तहत यह बात निर्धारित की जायेगी कि कहां–कहां पर सड़कें बनाई जायेंगी और कहां–कहां पर कॉलेजिज का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा यह भी विचारणीय होगा कि भविष्य में हम हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। जहां तक प्रगति की बात है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रदेश की प्रगति उसके कैपीटल एक्सपैंडीचर पर निर्भर करती है। मुझे यहां पर यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ष 2015–16 में 6780.12 करोड़ रूपये के कुल पूंजीगत खर्च के समक्ष वर्ष 2016–17 में संशोधित अनुमान 9.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर 7432 करोड़ रूपये का हो गया है। वर्ष 2017–18 में यह बढ़कर दुगुणा हो जायेगा और दुगुणे का मतलब यह है कि यह 14932 करोड़ रूपये हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा 4725 करोड़ रूपये खर्च किये जाने की सम्भावना है। कुल मिलाकर यह खर्च 20 प्रतिशत बनता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो इससे हरियाणा विकास के पथ पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर होगा। एक और बात के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने दो नये प्रोजैक्ट्स शुरू किये हैं। एक तो रहबर–ए–आज़म चौधरी छोटू राम के नाम से है। चौधरी छोटू राम जी वे इंसान थे जो आजादी से पहले अंग्रेजों के राज में मुख्यमंत्री रहे थे। किसी भी सरकार ने चाहे वह चौटाला जी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया । स्टैच्यू तो भले ही लगा दिये गये लेकिन उनको याद नहीं किया गया लेकिन हमारी सरकार ने उनको याद किया है तथा उनके नाम से एक योजना चलाई गई है । (शोर एवं व्यवधान)

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधू** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । बहन प्रेमलता ने जो बात कही है कि दीनबंधु सर छोटू राम जी को किसी भी सरकार ने याद नहीं किया उनको उपयुक्त सम्मान प्रदान नहीं किया यह ठीक नहीं है । जब प्रदेश में हमारी सरकार थी उस समय श्री ओमप्रकाश चौटाला के साथ हम भी लाहौर गये थे । चौधरी छोटू राम जी जिस असैम्बली में स्पीच देते थे हम वहां पर भी गये और जिस मकान में रहते थे वह मकान भी हमने देखा है । वह मकान अब नवाब मलेरकोटला को अलॉट हो चुका है। उन्होंने चौधरी छोटूराम जी की सभी

चीजों को सम्भाल कर रखा हुआ था। हम उनका सारा सामान वहां से लेकर आये और उनके नाम से रोहतक में म्यूजियम बना कर उसमें वह सामान रखा । इसलिए यह बात ठीक नहीं है कि चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार में उनको याद नहीं किया गया । हमने समय–समय पर उनकी यादगार मनाने का काम किया है ।

**श्री अध्यक्ष :** आप तो केवल सामान लेकर आये थे और आपने क्या किया है?

**श्रीमती प्रेमलता :** अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात का जवाब देना चाहती हूं । मैंने भी वह कमरा देखा हुआ है और उस कमरे में जो उनके नाम की चारपाई रखी हुई है वह तो बिल्कुल नई है । उनका सामान तो मेरे पास रखा हुआ है । जब वे रोहतक में वकालत करते थे तब की उनकी पुरानी अलमारी मेरे पास रखी हुई है । वे जो कपड़े पहनते थे वे आज भी मेरे पास रखे हुये हैं । उनकी अचकन आज भी मेरे पास रखी हुई है ।

**श्री करण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । बहन प्रेमलता जी ने बहुत अच्छी बात कही है तथा हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के साथियों ने भी कहा है कि हमने चौधरी छोटू राम के लिए बहुत कुछ किया है । शायद इनेलो के साथियों को इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन बहन प्रेमलता जी अवश्य जानती होंगी और मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे पास पंजाब असैम्बली की डिबेट है उसमें चौधरी देवी लाल जी ने छोटू राम जी को देशद्रोही कहा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री नसीम अहमद :** अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब गलत बयानी कर रहे हैं इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु):** अध्यक्ष महोदय, अगर हम इन बातों में जायेंगे तो बहुत सी बातें निकल कर आयेंगी । इसलिए अच्छा यही होगा कि बहन प्रेमलता जी जो बात कह रही हैं सबको उनकी बात को सुनना चाहिए । इसमें कोई दो राय नहीं है कि रहबरे आज़म दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी को हरियाणा की मिट्टी के सबसे बड़े महापुरूष थे जिनको किसान मजदूर और कमेरा वर्ग के मसीहा के तौर पर न केवल हरियाणा बल्कि पूरे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान तक के लोग याद करते हैं । बहुत लम्बे समय से हरियाणा प्रदेश में अतीत की सरकारों को उनका जितना सम्मान करना चाहिए था कहीं न कहीं आम आदमी महसूस करता है कि

उसमें कोताही जरूर रही है । आदरणीय सदस्या अपनी उसी बात को सदन के सामने रख रही हैं । जहां तक माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने बात कही है कि वे विधान सभा के रिकॉर्ड की वह प्रति लायेंगे, जिसमें चोधरी देवीलाल जी ने छोटूराम को देश द्रोही कहा हुआ है अगर उन बातों में जाने की सदन कोशिश करेगा तो 1920 में जो जमींदार यूनियनिस्ट पार्टी फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम जी ने बनाई थी तो चुनाव में रोहतक में कौन–कौन और किस–किस प्रकार से उनका विरोध किया करते थे ये बातें भी सामने आयेंगी । इसी तरह से संगरिया के विद्यालय में उनका किस प्रकार से विरोध हुआ था ये बातें भी आयेंगी और इन सभी बातों से एक अलग प्रकार के इतिहास पर चर्चा शुरू हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सदन अपनी मर्यादा और गरिमा बनाए रखे तथा आदरणीय सदस्या को अपनी बात रखने का मौका दें, मैं यही आपसे निवेदन करता हूं ।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, बहन जी अभी चौधरी छोटू राम जी की बात कर रही थी । वह कह रही थी कि उनको किसी ने याद नहीं किया। इसके लिये मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके परिवार से चौधरी वीरेन्द्र सिंह बहुत लम्बे समय तक इस सदन में मंत्री के पद पर रहे हैं। उस समय उन्होंने एक इंस्टीट्यूट नरवाना में बनाया था और एक इंस्टीट्यूट उचाना में बनाया था। उन्होंने जब वे इंस्टीट्यूट बनाए थे तब उनको चौधरी छोटू राम जी याद नहीं आए । उस समय तो उनको राजीव गांधी का नाम याद आया क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी में थे तो सोचते थे कि राजीव गांधी को कैसे राजी रखा जाए, उस परिवार को कैसे खुश रखा जाए? वे इंस्टीट्यूट उन्होंने सरकार की जमीन लेकर बनाए थे । उस वक्त चौधरी छोटू राम इनको याद नहीं आए थे । इनको आज चौधरी छोटू राम इसलिये याद आ रहे हैं क्योंकि अब वे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गये हैं । उनको चौधरी छोटू राम के लिये जो काम कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहते हुए करना चाहिए था तब तो किया नहीं । आज जब सरकार ने उनके नाम से ग्रामीण विकास योजना बनाई है तो कहीं न कहीं अब उस नाम को भुनाने की कोशिश की जा रही है । जबकि सबसे ज्यादा उनको भुलाने का काम किया है तो वह चौधरी विरेन्द्र सिंह ने किया है । वह वोट मांगते समय तो नाती बन जाते थे और जब कोई इंस्टीट्यूट बनाते थे तो उस समय उनको या तो इंदिरा गांधी याद आती थी या राजीव गांधी याद आता था । तब चौधरी छोटू राम जी को भूल जाते थे ।

**श्री जयप्रकाश :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि कम से कम इस सदन के अन्दर उन महापुरूषों का नाम न लिया जाए जिन्होंने समाज के लिये काम किया है। यह मेरा पूरे सदन से अनुरोध है क्योंकि वर्ष 1989 से पहले की बात मुझे भी याद है । श्री अभय सिंह जी की बात ठीक है कि जिस समय चौधरी देवी लाल कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे तो उस समय यह चर्चा चली थी और यह चर्चा इसलिए चली थी क्योंकि उस समय जो भी अंग्रेजों का साथ दे रहा था हर कांग्रेस का आदमी उसका विरोध कर रहा था । यह सही बात है । जो विरोध कर रहे थे उनके विरोध का एक कारण था कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिये एक लड़ाई लड़ी थी ।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु):** अध्यक्ष महोदय, इतिहास की यह सारी जानकारी सरासर गलत है । रहबरे–आजम दीन बन्धू सर छोटू राम ने कभी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया । वे ऐसे शख्स थे जिसने वाईस राय के सामने यह कहा था कि जब तक गेहूं की फसल के दाम ऊंचे न हो जाएं, तब तक मैं हरियाणा और पंजाब प्रदेश की जमीन से गेहूं की फसल नहीं कटने दूंगा । उन्होंने ही यह नारा दिया था कि जिस खेत से दहकान को मैय्यसर नोरोहोयती उस खेत के गोशाईं गंधब को जला दो । यह बात कहने की हिम्मत सर छोटू राम ने ही की थी । चौधरी छोटू राम ने कब अंग्रेजों का साथ दिया ? आपकी यह गलत जानकारी है । आप बताईये उन्होंने कब अंग्रेजों का साथ दिया ? आपकी जानकारी ठीक नहीं है । आप इतिहास पढ़कर आईये । आपको जिसने यह इतिहास पढ़ाया है वह गलत पढ़ाया है । यह स्वीकार नहीं होगा । आपकी यह बिल्कुल गलत जानकारी है । अंग्रेजों का साथ कौन दिया करते थे । दीन बन्धू सर छोटू राम की वजह से ही आज सभी किसानों के सिर पर पगड़ी है । जो किसान बे जमीन मजबूर मजदूर था, वह आज सर छोटू राम की वजह से ही जमींदार कहलाने का हक प्राप्त करता है । आपको इसकी जानकारी नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष :** यह सभी मानते हैं ।

**श्रीमती प्रेम लता :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा उदाहरण है कि जब चौधरी छोटूराम जी मंत्री थे तो जब वह रास्ते से जा रहे थे तो उनको एक बैल गाड़ी रास्ता नहीं दे रही थी । उन्होंने गाड़ी रोक कर कहा कि इससे पूछो तो सही कि यह रास्ता क्यों नहीं दे रहा है । इसकी हिम्मत कैसे हुई रास्ता न देने की, तो

उसने कहा कि मैं छोटू राम का भगत हूं । चौधरी छोटू राम ने यह कहा है कि आज हमने जमींदार का सिर ऊंचा कर दिया है । उन्होंने कहा कि तुम्हें रास्ते से हटने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहे सड़क पर चलो या कच्चे में चलो। मैंने तुम्हारा अभिमान बढ़ाया है । यह छोटू राम की ही देन है जिसके लिये आज का किसान अपने आप को इस बात के लिये बधाई भी देता है और अपने आप को आश्वस्त भी समझता है क्योंकि एक ही इन्सान ऐसा था जिसने किसान की, कमेरे वर्ग की बात की है ।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है बहन जी, आप वाईंड अप कीजिये ।

**श्रीमती प्रेम लता :** अध्यक्ष महोदय, जो ग्राम उदय योजना बनाई है जिसमें ऐसे 1500 गांवों को लिया जाएगा जिनकी आबादी तीन हजार से दस हजार होगी । यह सरकार का सही दिशा में कदम जा रहा है, जिसमें उन गांवों के विकास को सामाजिक आर्थिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके लिये हमारे वित्त मंत्री जी ने पांच हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । इसी तरह से डॉ0 मंगल सैन जी के नाम से ''मंगल नगर विकास योजना'' बनाई गई है, जिसमें 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है क्योंकि ज्यादातर लोग गांवों में बस्ते हैं । इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जहां तक राजनैतिक लोगों की बात है, अध्यक्ष महोदय, रोहतक तो सदा से राजनीति की धुरी रही है। चौधरी छोटू राम जी, डॉ. मंगल सेन जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी तथा वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी सभी के सभी रोहतक से संबधं रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का गांव बनियानी भी रोहतक में ही स्थित है। चौधरी बिरेन्द्र सिंह जोकि सर छोटू राम जी के नाती हैं, उन्होंने कभी भी चौधरी छोटू राम जी का नाम भुनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें दूसरे लोगों की तरह राजनीतिक फायदे उठाने के लिए अपने पूर्वजों का अर्थात् अपने नाना चौधरी छोटूराम जी का नाम लेना कतई पसंद नहीं है। वह तो कहते हैं कि वह सारे आदमी जो भी चौधरी छोटू राम जी का नाम लेते हैं, उनके साथ उनका खून का रिश्ता न सही लेकिन वे सभी उनके साथी हैं। वह तो यह भी मानते हैं कि चौधरी छोटू राम जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, यह बात उनके मुंह से न निकलकर दूसरे लोगों के मुंह से निकलनी चाहिए। उनकी महान शख्सियत के मद्देनज़र ही चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी छोटू राम जी के नाम से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई थी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी छोटूराम का नाम आगे बढ़ाने के लिए जो

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए मैं प्रशंसा करती हूँ। देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, चाहे वह आम आदमी था, चाहे वह फौजी था या फिर चाहे वह क्रांतिकारी ही क्यों न रहा हो, उन सबके जज्बे को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा निकालने की एक योजना बनाई और केन्द्र के एक मंत्री ने चौधरी छोटूराम के गांव गढ़ी सांपला आकर इस तिरंगा यात्रा को शुरू किया था जोकि चौधरी छोटूराम जी की यादगार को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महवपूर्ण कदम था। चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी ने अपने जीवन के 40 महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा दिए लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जबकि कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री की तरफ से चिट्ठी आ गई कि आपको केन्द्रीय मंत्री बनाया जा रहा है और जिस दिन मंत्री बनाये जा रहे थे उस दिन फिर से फोन आता है कि आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इससे बड़ा मजाक चौधरी बिरेन्द्र सिंह जैसे व्यक्तित्व के साथ क्या और कोई दूसरा हो सकता था? अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के 40 दिन के भीतर ही चौधरी बिरेन्द्र सिंह जैसे व्यक्तित्व के महत्व को समझते हुए उन्हें केन्द्र में मंत्री बना दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस दरियादिली को भूला जा सकता है? यह बहुत सराहनीय बात है और हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि जो चीज 40 साल में कांग्रेस न दे सकी उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने महज 40 दिन के अन्दर देने का काम किया। आज मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस महान सदन की एक सदस्या हूँ और यह केवल तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी टिकट प्रदान किया। यदि मैं कांग्रेस में होती, तो शायद मुझे टिकट भी न दिया जाता। (हंसी व विघ्न)

**श्री आनन्द सिंह दांगीः** अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अब मसला देवर–भाभी का आ गया है, हम और आप लोग क्या कर सकते हैं?

**श्रीमती प्रेम लताः** अध्यक्ष महोदय, जहां तक नोटबंदी की बात है इसके बारे में भी विपक्ष ने गलत बातें ही कही हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि नोटबंदी के बाद 125 करोड़ लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ा गया है, जिसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ही जाता है। निःसंदेह इससे कैशलैस सोसायटी बनेगी। जब कभी मैं विदेश में रह रही अपनी बेटी के पास मिलने के जाती थी तो अकसर देखती थी कि वह अपने पास कभी पैसे नहीं रखती थी तो मैने उससे पूछा

कि बेटी क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? वह तपाक से बोली कि मम्मी मेरे पास चार–पांच कार्ड हैं। मैं जो भी चीज लेना चाहूँगी कार्ड का प्रयोग करके पेमैंट कर दूंगी और चीज खरीद लूंगी। हमारे देश में यह चीज उस समय चलन में नहीं थी इसलिए मैंने भी कभी इसको सीखने की नहीं सोची लेकिन आज सोचती हूँ कि यदि उस समय सीख लेती तो ठीक रहता और आज मुझे कोई दिक्कत न आती। जब भी कोई जलूस या कोई अन्य इसी प्रकार के प्रोग्राम होते हैं तो अकसर देखते हैं कि लोगों की जेबें कट जाती हैं लेकिन यदि लोग कार्ड के माध्यम से पेमैंट का रास्ता चुनते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कार्ड किसी के काम नही आयेगा और इस तरह की घटनायें भी खत्म हो जायेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कैशलैस पेमैंट की कोशिश से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। प्रधानमंत्री जी की कोशिश का ही यह परिणाम है कि आज चलन में आए हुए नकली नोट बंद हो गए है और हवाला के जरिये जो पैसा देश में आता था उस पर भी अंकुश लग गया है। अध्यक्ष महोदय, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरीका तथा कैनेडा में 80 प्रतिशत लोग कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं जबकि हिंदुस्तान, चाईना और पाकिस्तान में कैश से पेमेंट करना ज्यादा अच्छा समझा जाता है। नोटबंदी की वजह से एक बार तो सबको तकलीफ हुई क्योंकि लोगों के घरों में रखे हुए 1000 और 500 रूपये के नोट चलन में बंद हो गए थे। दिक्कत हमारे को भी हुई क्योंकि हमारे पैसे भी बैंक में रखे थे क्योंकि यह थोड़े ही पता था कि इस तरह का भूचाल भी आ सकता है? दिक्कत तो सबको आई लेकिन हर बड़ी चीज को करने के लिए थोड़ा भूचाल आता ही है। इस प्रकार के भूचाल से दिक्कत बेशक हो परन्तु नुकसान नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से एक अनुरोध है। आज बड़े–बड़े नैशनल हाईवे बन रहे हैं। हरियाणा में के.एम.पी. सबसे बड़ा नैशनल हाईवे है। मेरा कहना यह है कि अगर हरियाणा की सड़कों के दोनों तरफ मार्किट या इंडस्ट्री को डिवेलप कर दिया जाये और इस काम का 50 प्रतिशत हिस्सा किसानों को दे दिया जाये तो संभव है कि उससे किसान की आजीविका का जुगाड़ हो जायेगा क्योंकि आज जो शिक्षा है वह आजीविका कमाने वाली नहीं है और न ही ज्यादा नौकरियां है इन परिस्थितियों में यदि किसान को इंडस्ट्रीज लगाने का मौका मिलेगा, चाहे वह लघु उद्योग ही क्यों न हो तो निःसंदेह उसकी जीविका बढ़ेगी और वह धरनों आदि पर नहीं बैठेगा। इस तरह से उसकी फ्रस्ट्रेशन समाप्त हो जायेगी और एनर्जी भी चैनलाईज्ड हो जायेगाी तथा इसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार

आयेगा। जहां तक एजुकेशन की बात है तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि जींद जिले में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है । मुझे दुःख होता है जब मेरे पास उनकी सप्लीकेशंज आती हैं । उनको अपने नाम भी ठीक से लिखने नहीं आते । वे खुद भी नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या नाम लिख रखा है । उनकी स्पैलिंग ठीक नहीं होती है । हमारे जीन्द जिले में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है । मैं इसके लिए पूर्व मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को कसूरवार ठहराती हूं । इन्होंने हमारे जीन्द जिले में कुछ भी विकास का काम नहीं होने दिया था । उन बच्चों की ऐसी एप्लीकेशंज आती हैं कि उनके नाम भी कौन पढ़ ले । आप रोहतक के आदमी को देख लें उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जैसे–जैसे जींद की तरफ जाते हैं तो गरीबी दिखने लग जाती है । वहां पर न तो उद्योग हैं और न अच्छी शिक्षा है । चौधरी बीरेन्द्र सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो हमारे प्रधान मंत्री जी की एक बहुत अच्छी योजना आई थी 'ग्रामोदय से भारत उदय' । वह ऐसी स्कीम थी कि जो हमारे गांव हैं उनको अगर हम शहरों की तरह सुविधाएं दे दें तो गांव का जो आदमी आज पलायन करने पर तुला हुआ है वह पलायन नहीं करेगा और उसको अपने गांव में ही सुविधाएं मिल जाएंगी । आपने भी देखा होगा कि अमेरिका के गांव गांव जैसे लगते ही नहीं है । वहां सफाई इतनी अच्छी रहती है और बिजली जाती ही नहीं है । हमारे देश के गांव तो गांव ही लगते हैं । गांव में घुसते ही सबसे पहले तो गोबर दिखेगा, फिर बिटोड़े दिखेंगे फिर आदमी दिखेंगे । हमें हैरानी होती है कि हमारे हरियाणा का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है । हमको सोचना चाहिए कि हम गांव के आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं ताकि वे भी अपने आपको शहरवासियों के बराबर समझे । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** प्रेमलता जी, अब आप प्लीज वाइंड अप कर लीजिए ।

**श्रीमती प्रेमलता :** अध्यक्ष जी, मैं कनाडा गई थी और मैंने वहां बहुत खेत देखे । मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत खेत देखे । मैंने देखा कि वहां के खेतों में भी साइलोज लगे हुए हैं । मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे हल्के उचाना में 90 एकड़ में के क्षेत्र जो मण्डी बनने जा रही है हमने उस मण्डी को मॉडर्न मण्डी का नाम दे रखा है । वहां पर अगर साइलोज लग जाएंगे तो उनमें गेहूं या जो भी चीज रखी जाएगी उनका नुक्सान जीरो परसेंट होगा । अब जब बारिश आती है तो हमारा गेंहू बह जाता है और सड़ जाता है । फिर हमें उसको फैंकना पड़ता है । इसका किसान को तो पैसा मिल जाता है लेकिन सरकार को बहुत ज्यादा नुक्सान होता

है । अगर मण्डियों में साइलोज लग जाएंगे तो उनमें एक–एक दाना सेफ रहेगा और भाव अच्छा होने से किसान को भी फायदा होगा । हमारे क्षेत्र से एक बीकानेर एक्सप्रैस ट्रेन चलती है । उसमें सारे कैंसर पेशेंट भरे होते हैं क्योंकि हमारे इलाके का पानी इतना खराब है कि ट्रेन की ट्रेन भरकर कैंसर का इलाज कराने के लिए बीकानेर जाती है । उस ट्रेन में आधे मरीज तो वैसे ही मर जाते हैं क्योंकि कोई देसी इलाज करवाता है, कोई तंत्र–मंत्रों से इलाज करवाता है, कोई किसी अन्य तरीके से इलाज करवाता है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में एक मैडिकल कॉलेज बनाने का सपना देखा है । मैं चाहूंगी कि वहां मैडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि मरीजों को आराम मिले । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** प्रेमलता जी, अब आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए ।

**श्रीमती प्रेमलता :** अध्यक्ष जी, मैं अन्त में मैं कैरोसिन फ्री हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहूंगी । चाहे हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के घर में परिवार नहीं है लेकिन ये दोनों औरतों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं । जो कैरोसिन फ्री वाली बात है आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिनांक 1 नवम्बर, 2016 को 'उज्ज्वला योजना' के नाम से एक स्कीम लाए हैं । इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को धूएं से निजात मिल जाएगी और जो बी.पी. एल. परिवार की महिलाएं हैं उनको एल.पी.जी. कनैक्शन लेने पर 1600 रूपये की सब्सिडी मिलेगी । इस योजना की शुरूआत पानीपत, पंचकुला और अम्बाला शहरों से हुई थी । हमें उम्मीद है कि साल के आखिर तक सारे जिले कैरोसिन फ्री हो जाएंगे । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं ।

**श्री बलकौर सिंह (कालावांली) (अ.जा.) :** अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा सारा ही हल्का सहूलियतों से वंचित है । वहां अस्पताल में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं तथा किसी तरह का स्टॉफ नहीं है। इस बारे में मेरा सदन में प्रश्न भी लगा हुआ था। अस्पताल में दवाइयां बिल्कुल भी नहीं है। इनेलो की सरकार के समय दादूपुर में एक पी.एच.सी. बनी थी, वह आज बंद होने के कगार पर खड़ी है। उस पी.एच. सी. में बिजली पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्ज तो बहुत दूर की बात है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया,

दिनांक 25.08.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे हल्के में गए थे और 29 घोषणाएं करके आए थे। उन घोषणाओं में से मुख्य घोषणा यह करके आए थे कि कालांवाली में सब डिवीजन का कार्य एक महीने में शुरू हो जायेगा। लेकिन 7–8 महीने बीत जाने के बाद भी कालांवाली सब–डिविजन में कोई भी अधिकारी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन के बाद भी नहीं आया है। सरकार ने बजट में लोगों को बहुत सारी सहूलियतें देने का वादा किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बुढ़ापा पैंशन दो हजार रूपये करने का वादा किया था लेकिन सरकार दो हजार रूपये ना देकर हर साल केवल 200 रूपये बुढ़ापा पैंशन में बढ़ोतरी कर रही है। नई बुढ़ापा पैंशन बनाने के लिए सरकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। बुढ़ापा पैंशन बनवाने में तरह–तरह की शर्तें लगाने का काम कर रही है। बहुत सारी बुढ़ापा पैंशन कट भी रही हैं। उपाध्यक्ष महोदया, चौधरी देवी लाल के नाम से जो बुढ़ापा पैंशन हरियाणा में शुरू हुई थी सरकार को चाहिए कि उसमें नई बुढ़ापा पैंशन बनवाने के लिए सरल तरीका अपनाए। सरकार ने होम गार्ड का मानदेय तो बढ़ा दिया है लेकिन होम गार्ड की भर्ती बिल्कुल बंद कर दी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालांवाली में सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप्प पड़ी है, इसके बारे में मैंने सदन में प्रश्न भी लगाया था। सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण पीने का पानी पीने लायक नहीं है। सिरसा जिले में तीन सब–डिविजन हैं लेकिन सीवरेज की सफाई के लिए केवल एक ही मशीन उपलब्ध है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हल्के की हैं। सरकार खिलाड़ियों के प्रति काफी जागरूकता दिखा रही है। लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी को तैयार करने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है। खिलाड़ियों के लिए ना तो कोई कोच की व्यवस्था है, ना ही खेलने का सामान ओर ना ही खिलाड़ियों के लिए कोई खुराक का प्रबंध बजट में प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, एक तरफ तो सरकार ''बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ'' का नारा देती है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के के गांव मलड़ी और लक्कड़वाली की लड़कियों ने अलग–अलग खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पद हासिल किए हैं। मेरे कालांवाली विधान सभा क्षेत्र के गांव लक्कड़वाली की लड़की राजपाल कौर ने नेशनल लेवल पर कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से मेरे क्षेत्र के गांव लक्कड़वाली की बेअंत कौर लम्बी कूद में और खुशप्रीत कौर जूड़ो में राष्ट्रीय स्तर तक खेल कर आई हैं तथा ये दोनों लड़कियां कबड्डी में भी राष्ट्रीय स्तर तक खेल कर आई हैं।

उपाध्यक्ष महोदया जी, उन लड़कियों को आज तक जिला स्तर का कोई भी अधिकारी मिलने के लिए नहीं गया है। वे लड़कियां बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। सरकार से पूरी सहायता न मिलने के कारण देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाली लड़कियां ऐसे ही घर में बंध कर रह जाती हैं। पिछली सरकार ने भी पंजाबी भाषा को बढावा देने के लिए वायदा किया था और पंजाबी भाषा को प्रदेश की दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिए राजनीति की थी। परन्तु आज तक पंजाबी भाषा को वह दर्जा नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। हरियाणा सरकार ने "नैशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क" स्कीम के अन्तर्गत वोकेशनल विषय को पढाने का फैसला लिया गया है, वोकेशनल विषय के रूप में पंजाबी, संस्कृत और उर्दू विषय का विकल्प बताया गया है। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2013 को एन.एस.क्यू.एफ. का जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें भी नहीं लिखा गया है कि वोकेशनल को किन–2 भाषाओं में पढाया जाएगा। यह हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची के अन्तर्गत तीन भाषाओं के फार्मूले की भी उल्लंघना है। इसके अनुसार किसी बच्चे को उसकी भाषा के अनुसार पढने से वंचित रखना, उसको उसके सपने से वंचित रखना है। उपाध्यक्ष महोदया जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी पंजाबी भाषा को नं0 1 पर एन.एस. क्यू.एफ स्कीम के तहत वोकेशनल विषय के विकल्प के रूप में न पढ़ाया जाए। वोकेशनल विषय के कारण नौंवी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पंजाबी, संस्कृत और उर्दू भाषाओं के रूप में जो समस्या सामने आयी है, उसका समाधान किया जावे। हमारी सरकार से मांग है कि एन.एस.क्यू.एफ के तहत वोकेशनल विषय को सातवे विषय के रूप में पढाया जाए और विकल्प के रूप में न पढाया जाए। 8वीं कक्षा तक भी सात विषय पढाये जाते हैं। भाषा का विकल्प सिर्फ भाषा होना चाहिए। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक सिख जाति के बच्चों का शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए न कि दूसरी भाषाओं को लागू करके पंजाबी भाषा को तीसरी भाषा का दर्जा दिया जाए। हरियाणा प्रदेश में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पंजाबी शिक्षा की किताबें नहीं मिलती हैं। इन किताबों को नये सिरे से छपवाकर स्कूलों में भेजा जाए। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक की किताबें कुछ स्कूलों में उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। इनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। छठी से 8वीं तक की कक्षाओं का सिलेबस तैयार करवाकर सारे पंजाबी हल्कों में सैमीनार लगावाए जाएं। एन.सी.ई.आर.टी. गुरूग्राम व शिक्षा बोर्ड भिवानी में पंजाबी

विषय में पी.जी.टी. की पोस्ट्स मंजूर की जाएं ताकि पंजाबी भाषा के प्रश्न पत्र बनाते समय कोई समस्या न आये और प्रश्न पत्रों की छपाई समय पर हो सके। हरियाणा प्रदेश के अन्दर पंजाबी अध्यापकों की 1182 पोस्टों में से 331 पोस्ट तथा पंजाबी पी.जी.टी. की 841 पोस्टों में से 421 पोस्ट खाली हैं। इनको जल्दी से जल्दी नयी भर्ती करके पूरा किया जावे। हरियाणा के सभी निजी स्कूल, एडिड स्कूल तथा सी.बी.एस.ई. के स्कूलों में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में लागू किया जावे। जिन स्कूलों में पंजाबी पढने वाले बच्चे हैं उन स्कूलों में लाईब्रेरियों में पंजाबी अखबार, किताब व मैगजीन उपलब्ध करवायी जाएं। उन किताबों को सभी स्कूल, कालेज व लाईब्रेरियों में भेजा जावे। इन सभी सुझावों पर विचार करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। पंजाबी भाषा के वास्ते यह बहुत जरूरी है। हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहां बैठे नहीं है। मुझे पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद पंजाबी है और वे पंजाबी लोगों की मांगों को जल्दी पूरा कर सकते हैं। मेरे हल्के में ही श्री गुरूगोविंद सिंह जी ने देह त्यागी थी, उनके नाम पर कुछ बनाये जाये इसके बारे में मैंने सवाल लगाया था लेकिन मेरी वह मांग अभी तक अधूरी है। पिछली सरकार ने इस काम के लिए पैसे भी दे दिए थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब मुख्यमंत्री जी हमारे हल्के में आए थे तो 10 करोड़ रुपए पेंडुखेत, 5 करोड़ रुपये मण्डी कालांवाली और 5 करोड़ रुपये रोड़ी पेंडलई के लिए उन्होंने घोषणा की थी। उपाध्यक्ष महोदया, उनकी घोषणा और जो राशि मैंने कही है, उसमें से एक भी काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लोगों को यह आशा है कि मुख्यमंत्री जी आयेंगे और वे लोगों की सारी मांगें और उम्मीदों को पूरा करके जाएंगे, जो उन्होंने घोषणाएं की थीं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि उन सभी कार्यों को पूरा करवाया जाए। हमारे यहां बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें हैं। बहुत से गांवों में पीने के पानी की कमी है। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक बिजली की बात है तो बिजली की बहुत भारी समस्या है। लोगों को अपने हर काम के लिए बिजली के बिना दिक्कत है। लोग छोटी–छोटी ढाणियां बनाकर खेतों में ही रहते हैं। जिन लोगों को बिजली–पानी नहीं मिलता है, उनके काम अधूरे रह जाते हैं और उनके बच्चे भी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। एक स्पैशल योजना बनाकर वहां पानी और बिजली का प्रबंध किया जाए। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बना तो दी हैं पर वे जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती हैं। सरकार को इस पर पूरे तौर से ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया,

आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री मक्खन लाल सिंगला (सिरसा) :** उपाध्यक्ष महोदया, बजट अभिभाषण आने वाले समय के लिए सरकार का आइना होता है, जिसमें दर्शाया जाता है कि सरकार लोक–भलाई के काम के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। इस अभिभाषण में लोक–भलाई कार्यों के लिए कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं दर्शाया गया, जिससे लोगों को बहुत सी उम्मीदें हों, केवल औपचारिकता निभाई गई है। न तो सरकार ने गांव व शहरों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान के लिए किसी योजना का वर्णन किया है और न ही आने वाले समय के लिए सामाजिक सुधार के लिए किसी घोषणा का जिक्र किया है। भाजपा सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, जिसके अनुसार कुछ शहरों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांवों में शहरों जितनी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। परंतु शहरों का भी वही बुरा हाल है जो गांवों का है। मेरे हल्के सिरसा के गांव बाजेकां में स्वास्थ्य केन्द्र भवन का बुरा हाल है और इसमें चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। गांव नहराणा में वाटर वर्क्स की जर्जर हालत है और जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक इसकी साफ–सफाई नहीं की गई जिससे गांव वाले गन्दा पानी पीने को मजबूर हैं। सिरसा शहर में सीवर व्यवस्था का बुरा हाल है जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर दो–दो, तीन–तीन फुट पानी खड़ा हो जाता है और इसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। मेरे हल्के के गांव कुकड़थाना में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और बार–बार कहने के बावजूद भी सरकार ने इस गांव के लिए कोई अलग से वाटर वर्क्स नहीं बनवाया। सिरसा शहर में ऑटो मार्केट का अभी तक पूर्ण विकास नहीं किया गया है और जिन्होंने इस मार्केट में दुकानें ली हैं उनके नाम अभी तक दुकानों की रजिस्ट्री नहीं की गई। प्रशासन को बार–बार इस बारे चेताया गया है। सिरसा शहर में पुरानी अनाज मंडी शहर के बीच में पड़ती है और अनाज की आमद को देखते हुए यह छोटी है। इसके लिए शहर से बाहर अनाज मंडी, कपास मंडी, सब्जी मंडी व काठ मंडी के लिए जमीन का अधिग्रहण करके इसे नई जगह स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सिरसा के गांव सलारपुर, रंगड़ी, खाजाखेड़ा, मंगाला, शहीदांवाली, धिंगतानीयां, मोड़िया खेड़ा, चौबुरजा, नटार, बाजेकां और बेगु में पानी की कमी है जिसके लिए सरकार से घग्गर नदी से पानी उपलब्ध करवाने के लिए बार–बार आग्रह किया गया है

परंतु सरकार कुंभकरण की नींद सोई हुई है। गांव नहराणा व नारायणखेड़ा में सेम की वजह से उपजाऊ भूमि बंजर हो गई है। बार–बार कहने के बावजूद इस सेम से बचाव का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया। जिला प्रशासन आंखें मुंदे बैठा है। सिरसा शहर के अन्दर ट्रेफिक जाम की समस्या आम है जिसे आम लोगों को असुविधा होती है। इसके लिए सरकार से अनुरोध है कि वह शहर के चारों और रिंग रोड़ बनाकर इसका स्थाई हल निकाले। सिरसा शहर में आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। सरकार से अनुरोध है कि इसका कोई स्थाई हल निकाला जाए ताकि सिरसा वासियों को दुर्घटनाओं से बचाया जाए।

18:00 बजे

**श्री जय प्रकाश (बरवाला) :** उपाध्यक्ष महोदया, वित्तमंत्री जी ने कल 2017–18 का बजट सदन में प्रस्तुत किया । उपाध्यक्ष महोदया, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरियाणा प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 100 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं । क्योंकि हमारे प्रदेश में कृषि आधारित मजदूर भी हैं, कारखाने भी हैं और व्यापारी भी हैं । वर्ष 2014–15 में कृषि दर 2 प्रतिशत रही, 2015–16 में 3 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2016–17 में यह दर 7 प्रतिशत तक पहुंच गई । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कृषि दर में वृद्धि हुई है क्या उसी हिसाब से प्रदेश के किसानों को आर्थिक फायदा हुआ है । मंत्री जी अपने जवाब में यह बात अवश्य बतायें क्योंकि कृषि करना पिछले कई वर्षों से नुक्सान का सौदा हो चुका है । यह बात मैं नहीं कह रहा हूं भारत सरकार का सर्वे कह रहा है । यह किस कारण से हुआ इस बारे में मैं किसी सरकार की बात नहीं करना चाहूंगा । किसान के नुक्सान की भरपाई के लिए मंत्री जी ने 2022 तक का समय रखा है जबकि आज किसानों को आर्थिक तौर पर बहुत नुक्सान हो रहा है उसके लिए बजट में सबसिडी का प्रावधान नहीं किया गया । वित्तमंत्री जी को किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए सबसिडी देनी चाहिए थी और बजट में पैसे का प्रावधान करना चाहिए था ताकि हमारे प्रदेश के किसानों की हालत मजबूत हो जाये । उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक राजस्व की बात आती है 42 प्रतिशत प्लान और नॉन प्लान बजट को इकट्ठा कर दिया गया है । इस प्रकार बजट का 42 प्रतिशत के करीब पैसा ब्याज, सैलरी और पैंशन में चला जायेगा । इस तरह से 58 प्रतिशत पैसा सरकार के पास बचेगा । उसमें से बजट में जो ग्रामीण विकास के लिए पैसा रखा गया है वह पहले से बढ़ाया गया है और बहुत अच्छा रखा गया

है । ग्रामीण विकास मंत्री ने बहुत अच्छी मेहनत करके यह पैसा रखवाया है । आज के दिन गांवों के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है । ज्यादातर गांवों में पानी की निकासी का बहुत बुरा हाल है । पानी की निकासी न होने के कारण पानी ओवर फलो होकर सड़कों पर फैल जाता है । सरकार ने सड़कें अच्छी बनाई हुई हैं लेकिन पानी की निकासी न होने के कारण बहुत दिक्कत आ रही है । इस बारे में मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने बताया कि पानी की निकासी के लिए 1200 करोड़ रुपये नाबार्ड से आयेगा । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि नाबार्ड ने यह पैसा नहीं दिया तो क्या सरकार अपनी तरफ से 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी । मंत्री जी इस बारे में रिप्लाई देते समय अवश्य बतायें । उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से बजट में कहा गया है कि दस हजार या उससे ज्यादा की आबादी के जो गांव हैं उनमें शहरी सुविधाएं दी जायेंगी । इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने गांव वर्ष 2017–18 में रखे जायेंगे और कितने गांव आने वाले सालों में रखे जायेंगे । क्योंकि पांच वर्षों का प्लान इस बारे में दिया है । इस योजना को मंत्री जी ने गोलमाल कर दिया है लेकिन यदि इस योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा तो यह बहुत अच्छी बात हमारे प्रदेश के गांवों के लिए होगी । उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं शिक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तमंत्री जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने बजट के माध्यम से आपको लूट लिया है । (विघ्न) शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और 58 वर्ष के बाद जो अध्यापक रिटायर होंगे उनको दोबारा नौकरी दी जायेगी । इसमें मेरा सुझाव है कि 12 हजार जे.बी.टी. कर्मचारी आज सड़कों पर हैं जिनके हक में हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था और वे तीन वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गये थे । उनकी ज्वायनिंग के लिए सरकार ढुलमुल नीति अपना रही है । उनकी भर्ती चाहे किसी भी सरकार ने की हो लेकिन उन नौजवानों को ज्वाइन करवाना चाहिए । उन नौजवानों को बहुत नुक्सान हो रहा है । मंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि उनको ज्वाइन क्यों नहीं करवाया जा रहा ? उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक बिजली का सवाल है इसके सुधार के लिए 73 नये सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं । हमारा एरिया धान का एरिया है । वहां पर पिछले वर्ष धान की फसल के समय बिजली न मिलने के कारण किसानों ने प्रदर्शन किया था और सरकार ने घोषणा की थी कि बड़सिकरी और सोंगल गांव में 33–33 के.वी.ए. के सब स्टेशन बनाये जायेंगे । लेकिन हमारे उन दोनों गांवों का बजट में

कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है । वहां के लोग सरकार पर किस तरह से विश्वास करेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि उन दोनों गांवों में अलग से सब स्टेशन बनाये जायें । इसी तरह से मेरे हल्के के चौसाला गांव में भी किसानों का बिजली को लेकर बहुत झगड़ा होता है इसलिए वहां पर भी नया सब स्टेशन बनाया जायेगा तो वहां बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा । उपाध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक लैटर निकाला गया है कि सरकारी नौकरियों का फार्म भरते वक्त जाति लिखना जरूरी होगा । मंत्री जी बतायें कि यह कब से शुरू किया गया है और क्या फार्म में जाति लिखना जरूरी है या इसे सरकार ने अपनी मर्जी से लागू किया है । देश में एक तरफ तो जात–पात को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार नौकरी के फार्म में जाति लिखना अनिवार्य कर रही है । फार्म में आरक्षण की कैटेगरिज तो लिखी जाती हैं लेकिन एच.एस.एस.सी. द्वारा अब जो नौकरी निकाली जाती हैं उनके फार्म में जाति का कॉलम दिया गया है, वह क्यों दिया गया है? इस तरह का कॉलम डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी है ? इस बारे में वित्तमंत्री जी अपने जवाब में बतायें । यदि सरकार इस तरह से जाति के आधार पर नौकरियों के फार्म भरवायेगी तो इसमें गड़बड़ी होने की शंका है । मुझे इसमें सरकार की मंशा में गड़बड़ लगती है इसलिए मैं सरकार से इस मामले में उसकी मंशा स्पष्ट करने की रिकवैस्ट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, यहां पर सत्ता पक्ष के भाई कह रहे थे कि सरकार द्वारा बजट में बहुत कुछ दिया गया है। हरियाणा का इस बार का बजट एक लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। यह मैं भी मानता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छी बात है। वित्तमंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत करके बहुत बुद्धिमता का परिचय दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वक्तव्य से माननीय वित्तमंत्री जी को प्रसन्नता हुई होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वित्तमंत्री जी की इस बुद्धिमता को मैं तभी सार्थक मांनूगा कि वे जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के बजट को पंजाब के बजट से ऊपर लेकर गये हैं वह काबिले तारीफ है। मुझे उम्मीद है कि वे उसी प्रकार से हरियाणा के कर्मचारियों को भी पंजाब के कर्मचारियों से ज्यादा वेतन देने की व्यवस्था करेंगे । मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा का बजट पंजाब से ज्यादा है उसी प्रकार से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भी पंजाब के सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा वेतन सरकार द्वारा दिया जाये। चाहे वह एक रूपया ही ज्यादा क्यों न हो अर्थात् चाहे वह बढ़ौतरी एक रूपया ही ज्यादा हो।

यह बढ़ौतरी कम हो या ज्यादा हो इससे मुझे कोई समस्या नहीं होगी लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के कर्मचारियों से ज्यादा वेतन मिले। इसी प्रकार से जो किसान को डीजल की खरीद पर सबसिडी दी जाती थी आज वह सबसिडी खत्म की जा चुकी है। किसान द्वारा जो डीजल खेत में प्रयोग होता है, उसके लिए किसानों के परमिट बनाये जायें ताकि ट्यूबवैल और ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल यूज हो उसमें किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा सके। इसी प्रकार से फसलों के बीज का मामला है। मैं यह बताना चाहूंगा कि आज के समय में फसलों के बीज के मामले में बहुत भारी गड़बड़ी हो रही है। सरकार डुप्लीकेट बीज की रोकथाम के लिए बहुत प्रयास करती है लेकिन इसके बावजूद भी डुप्लीकेट बीज की सप्लाई चोरी–छिपे होती ही रहती है। डुप्लीकेट बीज से किसान का बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए भी सरकार को नये सिरे से विचार करना चाहिए। पिछले दिनों मेरे हल्के में जाखौली के एक किसान के साथ ऐसा हुआ था कि डुप्लीकेट बीज के कारण उसका बहुत ज्यादा नुक्सान हो गया था। वह बेचारा किसान कोर्ट में भी गया था लेकिन उसके पास पक्का बिल न होने के कारण वहां से भी उसको कोई राहत नहीं मिली। बेचारे किसानों को इस बात की समझ नहीं होती जिस कारण वे शुरू में बीज की खरीद का पक्का बिल नहीं ले पाते और जिसके अभाव में बाद में नुक्सान होने की स्थिति उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो किसान को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले डीजल पर सबसिडी दी जाये और दूसरा सरकार डुप्लीकेट बीज सप्लाई के मामले में जल्दी से जल्दी सख्त कदम उठाकर कठोर सजा का प्रावधान करे ताकि किसानों को इससे होने वाली लूट से बचाया जा सके। अब मैं एक्स.एम.एल.एज़. की पैंशन के बारे में बात करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, जब सरकार द्वारा वर्तमान विधायकों का वेतन बढ़ाया जा चुका है और सरकारी कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ाकर वेतन दिया जा रहा है तो फिर एक्स.एम. एल.एज़. की पैंशन को सरकार द्वारा क्यों नहीं बढ़ाया गया है। सारे का सारा सदन इस बात पर पूरी तरह से राजी होगा कि एक्स.एम.एल.एज़. की पैंशन को भी जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाये । अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बारे में आवश्यक कार्यवाही अभी शुरू करवा देते हैं तो इससे एक बहुत अच्छा संदेश सभी एक्स.एम.एल.एज़. में जायेगा और वे मुक्त कण्ठ से सरकार की प्रशंसा करेंगे।

(विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एक्स.एम. एल.एज़. की पैंशन को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाये। इस सम्बन्ध में मेरे पास देश के 5–6 प्रदेशों से प्राप्त की गई जानकारी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। (विघ्न)

**श्री राम बिलास शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया जी, पिछले बजट सैशन के दौरान श्री जय प्रकाश जी की अध्यक्षता में एम.एल.एज़. के वेतन व भत्तों एवं एक्स एम.एल. एज़. की पैंशन के विषय पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इन्होंने सभी विधायक साथियों से विचार–विमर्श करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जो कि सारी की सारी इम्पलीमैंट हो चुकी है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि अब कौन सा काम बाकी रह गया है।

**श्री जय प्रकाश :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हमारी कमेटी की एम.एल.एज़. से सम्बंधित सिफारिशों पर ही सरकार द्वारा अमल किया गया था लेकिन एक्स एम.एल.एज़. की पैंशन के मामले को पैंडिंग रख लिया गया था।

**श्री जाकिर हुसैन :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी उस कमेटी का सदस्य था। हमारी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें से एम.एल.एज़. के वेतन से सम्बंधित विषय को तो टेक–अप कर लिया गया था लेकिन जो एक्स एम.एल.एज़. की पैंशन का मामला था उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम इस बारे में भी जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे और जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। एक्स एम.एल. एज़. को अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। यह बात भी सच है कि एक्स एम. एल.एज़. की पैंशन के बारे में कमेटी की सिफारिशों को मानने के लिए उस समय कमेटी को आश्वासन दिया गया था। हम सभी चाहते हैं और यह बहुत जरूरी है अतः इस बारे में सरकार को जल्दी से जल्दी सार्थक और सर्वमान्य निर्णय लेना चाहिए।

**श्री राम बिलास शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं इस कमेटी के चेयरपर्सन और माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि अभी उनकी कमेटी अभी ज्यों की त्यों एग्जिस्ट कर रही है। मैं सदन में आश्वासन देता हूं कि हम एक्स एम.एल. एज़. की पैंशन में भी जल्दी बढ़ौतरी कर देंगे।

**श्री जय प्रकाश :** उपाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं इसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक बात मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले बजट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम.एल.ए. फण्ड के लिए सभी एम. एल.एज़. को पांच–पांच करोड़ रूपये की राशि देने की बात कही थी लेकिन ये पांच–पांच करोड़ रूपये एम.एल़.एज़. को अभी तक नहीं दिये गये हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह बात सदन में बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो कारपोरेशन में कारपोरेटर है उसको चार करोड़ रूपये फण्ड के रूप में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बी क्लास की विधान सभा है लेकिन इसके बावजूद भी वहां के एम.एल.ए. को विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रूपये की राशि दी जाती है। इसके विपरीत हरियाणा प्रदेश का बजट इतना बड़ा है लेकिन इसके बावजूद भी यहां के एम.एल.एज़. को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणा के बाद भी पांच करोड़ रूपये की धनराशि अपने हल्कों में विकास कार्यों के लिए अभी तक प्रदान नहीं की गई है। यह सभी माननीय सदस्यों की मांग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, हम इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास करते हैं कि सभी एम.एल.एज़. को प्रति वर्ष अपने–अपने हल्कों में विकास कार्यों के लिए पांच–पांच करोड़ रूपये की राशि देने का जल्दी से जल्दी प्रावधान किया जाये जाये। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहन प्रेमलता जी कह रही थी कि विपक्ष का काम नुक्ताचीनी करने का होता है और विपक्ष कभी प्रशंसा नहीं करता, विपक्ष को प्रशंसा भी करनी चाहिए । मैं सिर्फ लोक निर्माण विभाग की प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सड़कों पर जो काम किया है वह काबिले तारीफ है । मैं मुख्यमंत्री जी की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे कलायत हल्के में ग्रांट भेजी है लेकिन जितनी जानी चाहिए थी उतनी नहीं गई है। कुछ कमी सड़कों में अभी भी रह गई है इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस कमी को भी दूर कर दिया जाये । मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने 1,02,329.35 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है । आज प्लान और नॉन प्लान को कोई आम आदमी नहीं जानता इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज आपका बजट पंजाब से ज्यादा है और हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब से कम वेतन मिल रहा है, विधान सभा के कर्मचारियों को सचिवालय के कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है इसलिए हरियाणा के कर्मचारियों का वेतन भी पंजाब के बराबर कर दिया जाये । इसी तरह से किसानों की सब्सिडी आपकी सरकार ने एक सिस्टम के तहत समाप्त कर दी

है । उसमें मेरा सुझाव है कि किसान के पास डीजल चाहे ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता हो चाहे ट्यूबवैल पर इस्तेमाल होता हो, किसान को डीजल पर सब्सिडी देने की घोषणा सरकार करे । इसके साथ ही साथ जो विधायकों को 5–5 करोड़ रुपये देने की बात है तो उसकी भी आप घोषणा करें, चाहे किसी भी प्रकार करें तो मैं बजट की प्रशंसा करूंगा । अगर आप यह सब करोगे तो मैं कहूंगा कि बजट अच्छा है और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो मैं कैसे कहूंगा कि आपने अच्छा बजट पेश किया है ? उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक बजट की प्रशंसा करने की बात है वह भी मैं कर सकता हूं अगर वित्त मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि हमने जो बिना टैक्स का बजट पेश किया है उसमें पूरे साल में कोई टैक्स नहीं लगायेंगे । अगर सरकार कल कोई टैक्स लगा देती है तो मैं उसकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूं ? उपाध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त भूतपूर्व विधायकों की डिमांड मेरे पास है, मैं उनको सदन के पटल पर रख रहा हूं उसको आप सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दें ।

**उपाध्यक्ष महोदया** : ठीक है, आप दे दीजिए हम उसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना देंगे ।

**श्री जयप्रकाश** : उपाध्यक्ष महोदया, ठीक है, मैं उनकी डिमांड को सदन के पटल पर रखता हूं आप इसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दें ।

**उपाध्यक्ष महोदया** : ठीक है ।

***श्री जयप्रकाश** : उपाध्यक्ष महोदया, मैं विभिन्न प्रदेशों के पूर्व विधायकों की पैंशन व भत्तों बारे विवरण सदन के पटल पर रखना चाहता हूं । हम यहां बता दें कि हरियाणा नंबर वन का दावा किए जाने के बाद भी हरियाणा में पूर्व विधायकों को मिलनें वाली पैंशन व अन्य सुंविधाएं दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से हरियाणा के पूर्व विधायकों को भी दूसरे राज्यों के बराबर पैंशन व सुविधाएं दिए जाने की मांग करते है। हरियाणा के मुकाबले दूसरे राज्यों को मिलने वाली पैंशन व सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

**हिमाचल प्रदेशः** पैंशन 36 हजार रुपये, 15 लाख रुपये कार व मकान पर लोन 4

.....

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का हिस्सा बनाया गया।**

प्रतिशत सालाना की दर पर और एक लाख 25 हजार रुपये यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष।

**उत्तर प्रदेशः—** पैंशन 25 हजार रुपये और एक लाख रुपये यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष।

**झारखंडः—** पैंशन 30 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये और तीन लाख रुपये यात्रा भत्ता गाडी के तेल सहित प्रतिवर्ष।

**छत्तीसगढ़ः—** पैंशन 20 हजार रुपये व दो लाख रुपये यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष। 15 हजार रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता। इंडोर पेशेंट का पूरा दवाई व अस्पताल खर्च।

**मध्य प्रदेशः—** पैंशन 20 हजार रुपये और 2500 किलोमीटर राज्य से बाहर व अपने राज्य में असीमित यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष।

**कर्नाटकः—** पैंशन 40 हजार रुपये और एक लाख रुपये यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष।

**महाराष्ट्रः—** बेसिक पैंशन 50 हजार रुपये और 35 हजार किलोमीटर यात्रा भत्ता बाहरी राज्यों में जाने पर व अपने राज्य में जितनी भी यात्रा करो उस गाड़ी के तेल का बिल।

**हरियाणाः—** दस हजार रुपये बेसिक पैंशन, कोई यात्रा भत्ता नहीं, कोई परमानैट चिकित्सा भत्ता नहीं।

बाकी उपरोक्त सभी प्रदेशों में पूर्व विधायकों को दी जा रही पैंशन व अन्य सुविधाओं बारे नोटिफिकेशन की प्रतियां साथ लगाकर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा व माननीय स्पीकर हरियाणा विधान सभा को आगामी कार्यवाही हेतु यह निवेदन करते हुए दे दी गई है कि पूर्व विधायकों को उपरोक्त राज्यों के अनुसार सुविधाए व पैंशन बढ़ाने की कृपा करें।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं समय पर अपने जवाब में सभी के सवालों का जवाब दे दूंगा । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये ।)**

**श्रीमती संतोष चौहान सारवान (मुलाना) (अ.जा.):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2017—18 के बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ से अधिक धनराशि का जो कर मुक्त बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं । बजट प्रदेश की

अढ़ाई करोड़ जनता के समग्र विकास और जरूरतों को पूरा करने वाला है । बजट में प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समुचित विकास, विशेषकर ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आई.टी., बिजली, पेयजल, सिंचाई तथा शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है । हरियाणा प्रदेश का गठन हुये 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सरकार हरियाणा की 50वीं वर्षगांठ पर सरकार की तरफ से 3000 से 10000 तक की आबादी वाले लगभग 1500 गांवों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय से, हरियाणा के महान नेता रहबरे आज़म स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर "दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना" के नाम से एक नई योजना की शुरूआत की गई है । इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना के सृजन और मौजूदा अवसंरचना के रख–रखाव के लिए हरियाणा के महान नेता पूर्व उप–मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सेन के नाम से नई योजना "मंगल नगर विकास योजना" शुरू की है जो भारतीय जनता पार्टी की जन हितैषी सोच को दर्शाता है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त का गठन होने के बाद प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी हैं उनके समय में हमेशा ही बिजली के रेट समय–समय पर बढ़े हैं । हरियाणा में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने बिजली के रेट को कम करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायत का चुनाव किया है। सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती, शिक्षकों को ऑन लाईन तबादला नीति, सी. एम. विन्डो के माध्यम से जनता की शिकायतों का तेजी से निपटारा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध करवा कर एक नये युग का सूत्रपात किया है । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रदेश में 15 नयी आई.टी.आई. खोलने का ऐलान किया है । उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र मुलाना के एक गांव नोणी में एक नई आई.टी.आई. खोलना शामिल है । उसके लिये भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं । स्पीकर सर, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपेक्षा करूंगी कि उनके समाधान के लिये संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिये जाएं । अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में बराड़ा कस्बे में पिछले डेढ़ साल से जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करीब 37 करोड़ रूपये सिवरेज की लाईन बिछाने के लिये और चार करोड़ रूपये सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के लिये दिये गये हैं । लेकिन पिछले डेढ़ साल से अधिकारियों ने उस जगह को और उस सारे सिस्टम को एक शटल कोक बना रखा है । स्पीकर सर,

मौजगढ़ गांव में जमीन उपलब्ध थी जो बराड़ा के बिल्कुल बराबर में है । हमने डिप्टी कमिशनर को वह प्रस्ताव पास करवा कर भेज दिया और साथ ही हमारे नगरपालिका के अधिकारियों ने भी उसको एप्रूव करके भेज दिया, लेकिन उस जमीन का फैसला नहीं हो सका है क्योंकि वह जमीन बस अड्डे के पास लगती है जो परिवहन विभाग के अधीन आती है जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपायुक्त अम्बाला ने परिवहन विभाग को भेज दी है । सौभाग्य से यहां परिवहन मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि यह काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है । नहीं तो यह पैसा लैप्स हो जाएगा। मेरा यह काम डेढ़ साल से लटका हुआ है जिससे लोगों को सीवरेज की सुविधा नहीं मिल रही है । अध्यक्ष महोदय, एक मेरे हल्के मुलाना में गांवों में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाने का काम लटका हुआ है । इसके लिये 22.5.2015 को 276 लाख रूपये की राशि एन.आर.डब्ल्यू.पी. की स्कीम के तहत स्वीकृत की गई थी । परन्तु विभाग की तरफ से इस मद में राशि न होने की वजह से यह फंड जारी नहीं हो सका । मैंने दिनांक 17.10.2016 को जन स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर 276 करोड़ रूपये की स्वीकृत धन राशि तथा 23 अन्य गांवों में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछवाने के लिये 169 लाख रूपये की अतिरिक्त धन राशि मुहैया कराने की गुजारिश की थी । उन्होंने इसके लिये विभाग को निर्देश भी जारी कर दिये थे । परन्तु अब तक मेरे हल्के के लिये वह राशि जारी नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि मेरे पूरे हल्के में कनाल बेस्ड सप्लाई नहीं है, टोटल ट्यूबवैल बेस्ड है । अब दो–तीन महीने में ही मई–जून मास की गर्मी का मौसम आ जाएगा और लोगों को पीने के पानी की भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा । इसलिये समय से पहले–पहले यह काम हो जाए तो लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा । अभी जनस्वास्थ्य मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं, मैं बाद में उनसे मिलकर इस समस्या को उनके पास भी रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा हल्का पीने के पानी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। अतः यहां पर पानी की पाईप लाईन जरूर बिछाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उन सभी कस्बों में जिनकी आबादी दस हजार को पार कर गई है, में सीवरेज बिछाने का निर्णय लिया है और इस संबंध में जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग ने कस्बों की पहचान करते हुए, एक सूची बनाई है और उसको सरकार के पास भेजा है। मेरे हल्के में स्थित मुलाना कस्बा दस हजार की आबादी पार कर गया है परन्तु

बावजूद इसके इस कस्बे को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस कस्बे का नाम भी सूची में डालकर मुलाना में भी सीवरेज डलवाने का काम करते हुए यहां के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अम्बाला छावनी से जगाधरी रोड़ पर स्थित कस्बा मुलाना में एक बस अड्ड़ा बनाये जाने की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। कितनी विचित्र बात है कि मुलाना में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थित है लेकिन यहां पर बस अड्ड़ा तक नहीं है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए रोजाना भारी संख्या में छात्र–छात्राए बसों के माध्यम से आते हैं। बारिश के दिनों में पक्की जगह नहीं होने की वजह से जब बसें कच्चे में उतरती हैं तो कच्ची जगह पर डेढ़–डेढ़ फीट गहरे खड्डे हो जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से बच्चों को बसों से उतरने व चढ़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आजू–बाजू कही भी जगह की उपलब्धता देखकर यहां पर बस अड्ड़े का निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने बराड़ा में पुलिस स्टेशन बनाने संबंधी एक मांग मैंने पिछले सत्र में भी रखी थी लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। मैं आज एक बार फिर से बराड़ा में पुलिस स्टेशन बनाने की अपनी मांग रखती हूँ। बराड़ा में 120 साल पुरानी एक सराय है जिसमें बराड़ा पुलिस स्टेशन चलाया जा रहा है। इस सराय की विकट स्थिति को देखते हुए इसको आज से 20 साल पहले कंडम घोषित किया जा चुका है। बारिश के मौसम में तो यह डर और भी ज्यादा हो जाता है कि कहीं इसकी छत न गिर जाये? अध्यक्ष महोदय, अगर इस सराय की छत गिर जाती है तो निःसंदेह प्रदेश और जनता के रक्षक हमारे पुलिस जवानों की जनहानि हो सकती है। बारिश के मौसम में यहां कार्यरत पुलिस के जवानों को साथ लगते किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाकर रात काटनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, आजू–बाजू जगह की उपलब्धत्ता न देखकर बराड़ा पुलिस स्टेशन के लिए मैंने गांव तौलावाली जोकि कंबासी की पंचायत में आता है, की चार एकड़ जमीन का प्रस्ताव करवा दिया है और इन परिस्थितियों में मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस जगह पर बराड़ा पुलिस स्टेशन बनाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, कस्बा बराड़ा में एक पशु अस्पताल है जोकि बिल्कुल कस्बा बराड़ा के बीच में आता है। पशु

अस्पताल को जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ फलों व सब्जियों की मंडी लगती है। जब बीमार पशुओं को इस रास्ते से ले जाया जाता है तो वह काफी उत्पात मचाते हैं। यहां यह बताना भी मैं वाजिब समझती हूँ कि जो यह पशु हस्पताल है, वह एक धर्मशाला की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। पशु अस्पताल की अपनी कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बराड़ा अब नगरपालिका में आ गया है अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि शहर से बाहर थोड़ा दूर एक पशु अस्पताल का निर्माण करवाया जाये ताकि धर्मशाला में चल रहे पशु अस्पताल को वहां पर शिफ्ट किया जा सके। यहां पर यह बताना भी उचित समझती हूँ कि मैं इस बाबत माननीय मंत्री जी से मिली थी और उन्होंने इसके लिए आर्डर भी किए थे परन्तु न जाने किस कारण यह आर्डर आगे जाकर इप्लीमैंट नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

## सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री जी सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे ।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं –

हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम, 2007 की धारा 41 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकरी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 2/एस.टी–2/एच.ए. 23/2007/एस. 40/2017 दिनांकित 27 जनवरी, 2017 ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 धारा 60 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 3/एस.टी–1/एच.ए. 6/2003/एस.60/2017. दिनांकित 8 फरवरी, 2017 ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना संख्या एच.ई.आर.सी./35/2016. दिनांकित 28 जुलाई, 2016 ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना एच.ई.आर.सी./36/2016, दिनांकित 28 जुलाई, 2016 ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना एच.ई.आर.सी./37/2016, दिनांकित 29 जुलाई, 2016 ।

मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012–2016 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग, चण्डीगढ़ की वार्षिक रिपोर्ट।
राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के साथ 49वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

## स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब पंडित मूल चन्द शर्मा, चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति, निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए फरीदाबाद, अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए गुरूग्राम तथा अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए रोहतक, नगर निगमों के लेखों पर लेखा–परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2016–2017 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की 10वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

**चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (पं. मूल चन्द शर्मा):** अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2016–2017 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की 10वीं रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

## विधान कार्य

### (1) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नंबर–1) बिल, 2017

**श्री अध्यक्ष :** अब वित्त मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरंत विचार किया जाए ।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :** अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

**श्री करण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में मैंने पढ़ा था कि यह बिल सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य होता है । अब आप इसे पास कर देंगे तो यह यह एक्ट बन जाएगा । अध्यक्ष जी, एक साल के बाद यह एक्ट किसी काम का नहीं रहेगा और इससे सरकारी दफ्तरों में कागजों का ढ़ेर लग जाएगा । इससे पहले भी सरकारी दफ्तरों में इस बिल के कागजों का इतना ढ़ेर लगा हुआ है कि अगर उसे बाहर निकालना हो तो इसके लिए अनेक ट्रकों की सहायता लेनी पड़ेगी । अध्यक्ष जी, मेरी इस विषय में माननीय मंत्री जी से बात भी हुई थी और अब मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने के साथ इसमें एक प्राविजन और कर दिया जाए कि यह बिल एक वर्ष के बाद रिपील समझा जाएगा । यह प्रोविजन हमारी भारत सरकार ने भी कर रखा है । इस प्रोविजन के पास होने से इस बिल के कागजों के बोझ से जो सरकारी कार्यालयों के कमरे भरे पड़े हैं वे खाली हो जाएंगे । इससे सरकारी कार्यालयों का बोझ खत्म होगा और सरकार का रख–रखाव का खर्च भी कम हो जाएगा । यह काम सरकार और जनता दोनों की भलाई का है । इस प्रोविजन को केन्द्र सरकार ने भी पास कर रखा है । अतः इस काम को करने में हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । इसके लिए आपको इस बिल में सिर्फ एक लाइन डालनी होगी कि इसे एक वर्ष के बाद रिपील समझा जाए । यह कार्य हमारी स्टेट और गवर्नमैंट दोनों के इंट्रस्ट में है । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं सदन का ध्यान एक दूसरे विषय की ओर भी दिलाना चाहूंगा । अभी सदन में माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठे हुए हैं और ये सरकार की पारदर्शिता की बात करते हैं । मैं इनका ध्यान फिशरीज़ डिपार्टमैंट में हुई नियुक्तियों की ओर दिलाना चाहूंगा । इन नियुक्तियों में बड़ी धांधली हुई । (विघ्न) इन नियुक्तियों को करते समय पैसों का लेन–देन किया गया और ये नियुक्तियां अपने और पराये आदमी की पहचान करके की गयी । माननीय उच्च न्यायालय में इन नियुक्तियों में हुई धांधली के विरूद्ध अपील दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने जब हरियाणा सरकार को इसका नोटिस दिया तो सरकार ने उच्च न्यायालय के डर से इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया । यह एक गम्भीर मसला है । अतः सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहिए कि इस तरह से गलत नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ? इसके अतिरिक्त मैं पूछना

चाहता हूं कि जब सरकार प्रॉपर तरीके से सलैक्शन कर चुकी थी तो मात्र एक सरकारी आदेश से सारी भर्ती को रद्द कैसे कर दिया गया ? मेरे विचार से इस तरह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता । इस निर्णय के विरूद्ध चुने हुए प्रतिभागी सरकार के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं । अभी हमने इस बजट सत्र में देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी सरकार में बड़ी पारदर्शिता की बात करते हैं । इस पर मेरा कहना है कि फिशरीज डिपार्टमैंट की नियुक्तियों में जिन लोगों ने धांधली की, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त सरकार को जांच करनी चाहिए कि यह धांधली किस स्तर पर हुई हैं और किन्होंने यह बेकायदगी की है ? अभी माननीय कोओपरेटिव मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठे हैं । इसी प्रकार से इस धांधली में कोओपरेटिव विभाग का भी जिक्र आया है । (विघ्न)

**कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने हाउस में मेरे विभाग से संबंधित एक विषय उठाया है । विभाग में भर्तियां की गई और सरकार ने उनको रद्द कर दिया । सरकार के इस फैसले को माननीय कोर्ट ने सही माना है । फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस भर्ती की जांच के लिए विभागीय जांच बैठा दी गई है । माननीय सदस्य सरकार पर बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और फिर अपनी बात से उल्टे हट जाते हैं । माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल अनेक विषयों पर हर हफ्ते प्रैस कांफ्रैंस करते हैं लेकिन दोबारा उस पर बात नहीं करते । इस नजरिये से ये एक इनक्रिडिबल सदस्य हैं । अतः इनके आरोपों में कोई दम नहीं होता है । लोक अपवाद मान्य है । इसी तरह सीता माता पर भी आरोप लगाए गए थे और श्री राम ने उन्हें वन में भेज दिया था। विभाग की भर्ती पर अंगुली उठते ही विभाग के अधिकारियों ने अपने आप ही उस भर्ती को रद्द कर दिया और उस पर जाँच के आदेश दे दिए। अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, सरकार को समय पर सदबुद्धि आ गई, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु):** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पिछली बार यानी दो साल पहले बैठकर सुझाव दिया

था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बिल्कुल वाजिब है। इस सुझाव को हमने प्रक्रिया में भी डाला था। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई थी जितने भी पुराने एप्रोप्रिएशन बिल हैं उन सबको रिपिल करने की प्रक्रिया हमने शुरू की है। यह ठीक है कि इस बिल में रिपिल करने की क्लॉज नहीं है। लेकिन उसको रिपिल करना चाहिए, माननीय सदस्य की बात से हम सहमत हैं। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था उस पर कार्यान्वयन करना हमारे स्तर पर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, जब एप्रोप्रिएशन बिल आज सदन में आया हुआ है उससे संबंधित डिमाण्ड्स पर सदन में माननीय सदस्य चर्चा करें तो वह चर्चा वाजिब है। अध्यक्ष महोदय, जिस डिमाण्ड का उस विभाग से कोई संबंध ही नहीं है अगर उस विभाग पर चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस पर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर न दिया जाये।

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के दौरान सारी बातें कही जा सकती हैं क्योंकि संबंधित विभाग के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इस पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि ताकि संबंधित विभाग की देख–रेख, साजो सामान और संबंधित विभाग में क्या अच्छा और बुरा हो रहा है, इस बात का पता लग सके। (विघ्न)

**कैप्टन अभिमन्युः** अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब एक सीनियर नेता हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा की अपनी एक मर्यादा होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि एक बार इस मर्यादा का मार्गदर्शन जरूर करें।

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, इस बिल में परिवहन विभाग का भी जिक्र हुआ है और उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं। इसके संबंध में मेरा सवाल भी लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश लेकर अपने चहेतों को फ्री बस पास जारी कर रखे हैं। देश और प्रदेश कानून से चलता है। (विघ्न) पता नहीं कितने मंत्रियों ने अपने स्टॉफ, गनमैन आदि को पास जारी कर रखे हैं। (विघ्न)

**परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 में हमने किसी को भी फ्री बस पास जारी नहीं किया।

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्षः** दलाल साहब, मांग पास हो चुकी है इसलिए इस पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। (विघ्न)

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय, मैं बोल सकता हूँ। यदि आपको लग रहा है कि मैं कानून के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ। (विघ्न) आप इसका पता कर लीजिए ।

**कैप्टन अभिमन्युः** अध्यक्ष महोदय, हम पहली बार चुनकर सदन में आए हैं। लेकिन माननीय सदस्य बहुत सीनियर और अनुभवी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो डिमाण्ड पास हो रही हैं, माननीय सदस्य उन डिमाण्डस से संबंधित प्रश्न पर बोल सकते हैं कि ये जो आप पैसा ले रहे हैं, यह ज्यादा ले रहे हैं या इतना नहीं लेना चाहिए था आदि इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन अपने मुद्दे से हटकर विभाग का नाम लेकर के यदि माननीय सदस्य चर्चा करें तो वह उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्पष्ट मार्गदर्शन करें।

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः** अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा का निर्माण हुआ है ऐसी प्रथा है कि बहुत से माननीय सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हैं और बहुत से माननीय सदस्य बजट पर बोलते हैं। जो माननीय सदस्य रह जाते हैं वे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हैं और डिमाण्डस पर भी बोलते हैं। इस तरह से चारों चीजों पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

**श्री अध्यक्षः** डा0 साहब, जब डिमांड पास हो चुकी है तो अब उन डिमांड्स के बारे में बोलने क्या लाभ होगा ?

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु):** अध्यक्ष जी, जो उन्होंने प्रैसीडैंस कहा है ऐसे प्रिसिडेंस 45 साल में रहे हैं, वो प्रैसीडैंस भी उन्होंने कंडीशनल बताये हैं कि जो सदस्य बोल नहीं पाया है उसे बोलने का मौका दिया जा सकता है।

**श्री करण सिंह दलालः** अध्यक्ष महोदय दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में बायो गैस, कई तरह के बीज, और दूसरे कई तरह के जो पदार्थ खरीदे गये हैं उनके क्लीनिकल टैस्ट फेल हो गये हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का इस तरह का सामान खरीदने में अरबों खरबों रूपये बर्बाद हो गये हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और यदि ऐसी कोई बात है तो उसकी इन्कवारी करवाई जानी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस

बिल में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कहा है उस बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा ।

**श्री ओम प्रकाश धनखड़ :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में बायो गैस कहां लगती है।

**कैप्टन अभिमन्यु :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपकी दरियादिली का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सदन का समय खराब कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमें चर्चा से कोई आपति नहीं है।

**श्री ओम प्रकाश धनखड़:** माननीय सदस्य बायो गैस के बारे में कह रहे हैं जबकि एग्रीकल्चर विभाग में बायो गैस के प्रयोग का कोई मतलब नहीं है।

**श्री करण सिंह दलाल:** मंत्री जी, ठीक है, बायो गैस मेरे से गलत बोला गया है।

**श्री ओम प्रकाश धनखड़:** अध्यक्ष महोदय, यह बायो गैस एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है।

**श्री करण सिंह दलाल:** मंत्री जी, ठीक है आपने करेक्ट करवा दिया है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न है–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2017 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अध्यक्ष:** अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई –क्लॉज विचार करेगा।

**क्लॉज–2**

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न है–

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## क्लॉज–3

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## शिडयूल

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि शिडयूल 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## क्लॉज–1

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## इनैक्टिंग फार्मूला

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## टाईटल

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अध्यक्षः** अब वित्त मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**विधेयक पारित हुआ।**

.....

## (2) दि हरियाणा लॉ ऑफिसर्ज (इंगेजमेंट) अमैंडमैन्ट बिल, 2017

**श्री अध्यक्ष :** अब वित्त मंत्री हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :** अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

**श्री परमिंदर सिंह ढुल :** अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च, 2016 को गाइडलाइंस जारी की थी और उन गाइडलाइन्स के अंतर्गत हरियाणा में विधि अधिकरियों की नियुक्ति के बारे में एक फार्मूला बनाया था, जिसमें हरियाणा और पंजाब के साथ दूसरी स्टेट्स को भी कहा गया था और एक क्राइटेरिया बना दिया गया था। यह बिल चहेते आदमियों को केवल रि–एप्वॉयमेंट करने के लिए लाया गया है। हाईकोर्ट में इस केस की तारीख 18.05.2017 लगी हुई है। हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए नोटिस दिया है कि कैसे बंद दरवाजे से अपने

आदमियों को फिर नौकरी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद और हाईकोर्ट के नोटिस के बावजूद यह अमैंडमैन्ट क्यों की जा रही है? इस तरह से यह क्लीयर–कट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वायलेशन है।

**कैप्टन अभिमन्यु :** अध्यक्ष जी, यह जानकारी गलत है और माननीय विपक्ष के साथी अलग–अलग बातों को जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे विधेयक को यहां प्रस्तुत करने से पहले इस पर सारी कानूनी राय ले ली गई है और कानूनी राय स्पष्ट है, इसलिए यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है।

**श्री परमिंदर सिंह ढुल :** अध्यक्ष जी, उनको दोबारा अप्वायंटमेंट देने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। यह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वॉयलेशन है। सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस आया हुआ है लेकिन कोर्ट में केस की सुनवाई से पहले ही दोबारा इनको कंटीन्यू करा दिया जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

**श्रीमती गीता भुक्कल :** अध्यक्ष जी, अभी ये हरियाणा लॉ आफिसर्ज इंगेजमेंट अमैंडमैन्ट बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है और जैसा कि परमिंदर ढुल जी ने भी इस बारे में अपनी बात रखी है। इस बिल में कहा गया है कि पूरा का पूरा प्रोसैस अपनाया जायेगा। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि मामला अभी सब्ज्यूडिश है और सरकार को इसमें कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं। जो आज सरकार अमैंडमैन्ट लेकर आई है, उसमें यह कहा गया है कि जो आलरेडी लॉ ऑफिसर्ज लगे हुए हैं और उनकी अगर टर्म खत्म नहीं हुई है तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसााब से कॉन्टीन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लॉ ऑफिसर्ज आलरेडी लगे हुए हैं, उनको जारी करने के लिए यह बिल आया है। चूंकि यह नया बिल आया था तो मैं केवल इसमें यह जानना चाहूंगी कि जिनको कंटीन्यू किया जाएगा तो क्या उसके अनुसार इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा? जो पुरानी भर्तियां या जो लॉ आफिसर्ज थे, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी पूरी तरह से नहीं लागू की जाती थी। मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि पुराने लगे लॉ आफिसर्ज कंटीन्यू किए जाएंगे या नई भर्ती होगी और क्या उसमें पारदर्शी तरीके से पूरी तरह से रिजर्वेशन लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी?

**श्री परमिंदर सिंह ढुल :** अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला माननीय ए.जी महोदय ही करेंगे, न कि सिलेक्शन कमेटी। इन आदमियों को कंटीन्यू करना है तो केवल उनकी कलम से ही होना है। अगर वो सैटिसफाइड होंगे तो ही इनको दोबारा

कंटीन्यू करेंगे। उन्होंने ही तो पहले ये लॉ ऑफिसर्ज लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों इनको प्रायरिटी नहीं दी और इसके लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, क्यों हाईकोर्ट अब दोबारा नोटिस दे रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

**सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है

कि सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज–2**

**श्री अध्यक्ष –** प्रश्न है

कि क्लाज–2 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्ष –** प्रश्न है

कि सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## टाइटल

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब वित्त मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(विधेयक पारित हुआ)**

.....

## श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरूद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मुझे श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक से श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरूद्ध एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मिला है मैं इस विषय पर दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर अपनी सहमति देता हूं । अब श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक इस संबंध में सदन की अनुमति लेंगे ।

**श्री ज्ञान चन्द गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं अनुरोध करता हूं कि जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे अपनी सीटों पर खड़े हो जायें ।

**(इस समय सत्ताधरी पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गये ।)**

**श्री अध्यक्ष :** इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या 15 से अधिक है इसलिए इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है । (विघ्न) अब श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

**श्री ज्ञान चन्द गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> कि आज बजट पर चर्चा के दौरान श्री कुलदीप शर्मा, विधायक ने अपने भाषण में अवैध खनन के बारे में आरोप लगाये कि निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ हैं । वे सरकारी लोग हैं । हरियाणा प्रदेश का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां इल्लीगल माईनिंग नहीं हो रही है। यहीं पर वे लोग बैठे हुए हैं जो ये काम करवा रहे हैं । जब श्री कुलदीप शर्मा, विधायक को ऐसे लोगों का नाम उजागर करने का कहा गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता जताई । इस प्रकार से उन्होंने इस महान सदन को गुमराह किया है। इसलिए श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन के तहत कार्यवाही की जाये तथा यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को रैफर किया जाये और अगले सत्र की पहली बैठक तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि आज बजट पर चर्चा के दौरान श्री कुलदीप शर्मा, विधायक ने अपने भाषण में अवैध खनन के बारे में आरोप लगाये कि निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ हैं । वे सरकारी लोग हैं । हरियाणा प्रदेश का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां इल्लीगल माईनिंग नहीं हो रही है। यहीं पर वे लोग बैठे हुए हैं जो ये काम करवा रहे हैं । जब श्री कुलदीप शर्मा, विधायक को ऐसे लोगों का नाम उजागर करने का कहा गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता जताई । इस प्रकार से उन्होंने इस महान सदन को गुमराह किया है। इसलिए श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन के तहत कार्यवाही की जाये और अगले सत्र की पहली बैठक तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

> कि आज बजट पर चर्चा के दौरान श्री कुलदीप शर्मा, विधायक ने अपने भाषण में अवैध खनन के बारे में आरोप लगाये कि निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ हैं । वे सरकारी लोग हैं । हरियाणा प्रदेश का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां इल्लीगल माईनिंग नहीं हो रही है। यहीं पर वे लोग बैठे हुए हैं जो ये काम करवा रहे हैं । जब श्री कुलदीप शर्मा, विधायक

को ऐसे लोगों का नाम उजागर करने का कहा गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता जताई । इस प्रकार से उन्होंने इस महान सदन को गुमराह किया है। इसलिए श्री कुलदीप शर्मा, विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन के तहत कार्यवाही की जाये और अगले सत्र की पहली बैठक तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** इस विषय को विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए रैफर किया जाता है तथा समिति को अगले सत्र की प्रथम बैठक तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है ।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 8 मार्च, 2017, बुधवार प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

18.46 बजे

**(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2017 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)**